दैनिक जागरण

क्रोध की अवस्था में सबसे पहले विवेक का क्षय होता है

टीएमसी के कितने टुकड़े

तृणमूल कांग्रेस के 19 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र भेजकर जिस तरह यह दावा किया कि असली टीएमसी हम ही हैं, उससे इस पर एक तरह से मुहर ही लगी कि इस दल के विधायकों की तरह लोकसभा सदस्यों में भी टूट की औपचारिकता मात्र शेष है। टीएमसी के राज्यसभा सदस्य भी छिटक रहे हैं। अब तक उसके तीन राज्यसभा सदस्य त्यागपत्र दे चुके हैं। आने वाले दिनों में उनकी संख्या और बढ़े तो हैरानी नहीं। चुनावों में हार के बाद आम तौर पर राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ती ही हैं, लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि पराजय के उपरांत किसी दल का अस्तित्व ही खत्म होता दिख रहा है। इसमें संदेह है कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी बचा सकेंगी, क्योंकि उनके पास बहुत कम विधायक और सांसद बचे हैं। इनमें से चंद ही खुलकर यह कह रहे हैं कि वे ममता के साथ हैं। इनमें भी कुछ ऐसे हैं, जो यह कह रहे हैं कि उन्हें ममता का नेतृत्व तो स्वीकार है, लेकिन उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का नहीं। ममता के प्रबल समर्थक के रूप में सामने आए लोकसभा सदस्य कल्याण बनर्जी ने यह कहकर एक तरह से अल्टीमेटम ही दिया कि उन्हें पार्टी और अभिषेक में से किसी एक का चयन करना होगा।

टीएमसी केवल दो टुकड़ों में ही बंटती नहीं दिख रही है। उसके कई टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में बगावत का नेतृत्व करने वाली टीएमसी सांसद काकोली घोष कह रही हैं कि उन्हें बागी विधायकों के नेता ऋतब्रत बनर्जी से कोई लेना-देना नहीं। जहां ऋतब्रत विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाने को कह रहे हैं, वहीं काकोली मोदी सरकार का साथ देने की घोषणा कर रही हैं। यह समय ही बताएगा कि टीएमसी का क्या होगा, लेकिन पार्टी में बिखराव के लिए ममता बनर्जी अपने अलावा और किसी को दोष नहीं दे सकतीं। उनका दोष केवल इतना ही नहीं कि वे मनमाने तरीके से सरकार चला रही थीं, बल्कि यह भी है कि उन्होंने पार्टी पर भतीजे अभिषेक पर थोप दिया था। वे किसी रियासत के अहंकारी युवराज की तरह पार्टी चला रहे थे। टीएमसी पहली पार्टी नहीं, जिसमें भाई-भतीजावाद हावी हो गया हो। अधिकतर क्षेत्रीय दल ऐसे ही हैं। वे परिवार विशेष से संचालित होते हैं और उसके आगे किसी की नहीं चलती। ऐसे दलों में न तो आंतरिक लोकतंत्र होता है और न ही असहमति के लिए कोई स्थान। इन दलों में वही होता है, जो परिवार चाहता है। टीएमसी में भी वही हो रहा था, जो ममता और अभिषेक चाह रहे थे। विचारधाराविहीन यह दल तभी तक अपने नेताओं को अपने साथ जोड़े रखने में समर्थ रहा, जब तक उसके पास सत्ता रही। सत्ता मिलने की आस, सत्ता और उससे मिलने वाले लाभ ही पार्टी को एकजुट रखने वाले मूल तत्व थे। इनके हटते ही पार्टी में भगदड़ मच गई।

जल संरक्षण जरूरी

झारखंड में सूखे तालाबों, कुओं और अन्य निष्क्रिय जलस्रोतों को वर्षा जल संचयन के माध्यम से पुनर्जीवित करने की पहल जल प्रबंधन के प्रति बदलती सोच का परिचायक है। यह अभियान प्रकृति के साथ संतुलित विकास की दिशा में सकारात्मक कदम है। यह प्रयास इस तथ्य को स्वीकार करता है कि जल संकट का समाधान केवल नए स्रोतों के निर्माण में नहीं, बल्कि उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पुनर्भरण में निहित है। विगत वर्षों में भूगर्भ जल का दोहन तो हुआ, जबकि पुनर्भरण पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। शहरीकरण, कंक्रीटीकरण और जलग्रहण क्षेत्रों के क्षरण ने स्थिति को और गंभीर बनाया है। ऐसे समय में राज्य के 2500 से अधिक सूखे या कम जल वाले जलस्रोतों को वर्षा जल संचयन से जोड़ने की योजना दूरगामी महत्व रखती है। इस पहल की विशेषता यह है कि इसमें खराब पड़े हैंडपंप, डीप बोरिंग और परित्यक्त खदानों को भी जल रिचार्ज संरचनाओं के रूप में उपयोग करने की योजना है। यह संसाधनों के पुनः उपयोग और सतत विकास की अवधारणा को मजबूत करता है। साथ ही, बड़े बांधों की बजाय छोटी एवं स्थानीय जल संरचनाओं पर जोर देना विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन की उपयोगिता को रेखांकित करता है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते जल संकट के दौर में जल संरक्षण केवल तकनीकी आवश्यकता नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व भी है।

जलवायु परिवर्तन और बढ़ते जल संकट के दौर में जल संरक्षण केवल तकनीकी आवश्यकता नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व भी है

नए दौर में भारतीय कृषि

शिवराज सिंह चौहान

मोदी सरकार में कृषि 'उत्पादन के क्षेत्र' तक सीमित न होकर किसान की समृद्धि, जोखिम सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, हरित तकनीक और ग्रामीण विकास का समन्वित आधार बन गई है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। पहले हमारी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि देश में अनाज की कमी न हो और किसी तरह भूख से बचाव हो जाए। आज मोदी जी की दूरदर्शिता और किसान हितैषी नीतियों के कारण कृषि सिर्फ 'उत्पादन के क्षेत्र' तक सीमित न होकर किसान की समृद्धि, जोखिम-सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, हरित तकनीक और ग्रामीण विकास का समन्वित आधार बन गई है। हरित क्रांति के बाद पहली बार नीतियां फसल उत्पादन के बजाय किसान की वास्तविक आय, टिकाऊ कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती जैसे पहलुओं पर केंद्रित हैं। इसी सोच से दलहन-तिलहन मिशन, काटन मिशन, प्राकृतिक खेती मिशन, पीएम धन-धान्य कृषि योजना, खेत बचाओ अभियान, डिजिटल कृषि और शोध-नवाचार, सबको एक ही दृष्टि से जोड़ा जा रहा है। समन्वित प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में 3765.63 लाख टन के रिकार्ड स्तर पर है।

मोदी सरकार ने किसान की जोखिम-सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 22 किस्तों के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे 4.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता पहुंच चुकी है। सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, कृषि-अवसंरचना, वेयरहाउस और कोल्ड-चेन में निवेश ने उत्पादन, भंडारण और बाजार तक पहुंच को मजबूत किया है। लंबे समय तक दालें, खाद्य तेल और कपास जैसे क्षेत्रों में हम अपनी क्षमताओं से पीछे रहे। मोदी सरकार ने इन तीनों को रणनीतिक प्राथमिकता देते हुए अलग-अलग मिशन के रूप में आगे बढ़ाया है। राष्ट्रीय दलहन, तिलहन और काटन मिशन इस दिशा में बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। इन अभियानों का उद्देश्य है किसान को उत्पादन के साथ-साथ वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा योग्य गुणवत्ता, बेहतर मूल्य और स्थिर आय भी मिल सके।

रासायनिक तत्वों पर बढ़ती निर्भरता, मिट्टी की दुर्बलता और भूजल पर दबाव जैसे बिंदु हमें आगाह कर रहे हैं कि खेती के तौर-तरीके बदलने होंगे। इसी समझ के साथ प्राकृतिक खेती को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सेंसिटाइज कर इनमें से लगभग 18 लाख किसानों को सक्रिय रूप से प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए तैयार किया जाए और चरणबद्ध रूप से करीब 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाया जाए। यह परिवर्तन धीरे-धीरे, वैज्ञानिक प्रमाणों और किसानों के अनुभव के आधार पर आगे बढ़ रहा है। इस पहल का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, रासायनिक लागत घटाना और जलवायु झटकों के सामने फसलों को टिकाऊ बनाने के साथ ही उत्पादों को पोषक बनाना है।

अवधेश राजपूत

भारत जैसे विशाल देश में कुछ क्षेत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ अलग-अलग वजहों से पीछे रह जाते हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए पीएम धन-धान्य कृषि योजना की संकल्पना की गई है। इस योजना के तहत लगभग 100 कम उत्पादन वाले जिले चिह्नित किए गए हैं, जहां प्रति हेक्टेयर पैदावार राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और किसान अपेक्षित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इन जिलों में 11 विभागों की 36 योजनाओं जोड़कर उन्हें समग्र पैकेज में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके तहत सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, बीज, उर्वरक, फसल विविधीकरण, पशुपालन, बागवानी, कृषि-उपकरण, कौशल विकास, अवसंरचना और बाजार-जुड़ाव जैसी सुविधाएं सहजता से उपलब्ध हो पा रही हैं।

असंतुलित उर्वरक उपयोग, भूजल का अत्यधिक दोहन और सीमित फसल चक्र ने खेत की सेहत को प्रभावित किया है। इसे देखते हुए हमने 'खेत बचाओ अभियान' शुरू किया है। यह अभियान केवल मिट्टी बचाने का नहीं, बल्कि किसानों की आय, भोजन की गुणवत्ता और भविष्य की खाद्य सुरक्षा की रक्षा का है। इसके पांच मुख्य संदेश हैं-किसान मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का उपयोग करे, डीएपी और यूरिया पर अत्यधिक निर्भरता कम करे, जैव एवं नैनो उर्वरकों को अपनाए, हरी खाद, जैविक खाद और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा दे, नकली बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के विरुद्ध सतर्क रहे। लक्ष्य यह नहीं कि उर्वरक खपत अचानक कम कर दी जाए, बल्कि यह है कि हर किसान सही मात्रा, सही समय और सही मिश्रण का उपयोग करे, ताकि मिट्टी की सेहत लंबे समय तक बनी रहे, लागत घटे और उत्पादन भी सुरक्षित रहे।

कृषि को विज्ञान, अनुसंधान और डिजिटल तकनीक के माध्यम से और लाभकारी बनाने की दृष्टि से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) ने 2014-25 के बीच लगभग 3,000 ऐसी किस्में विकसित की हैं, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में कहीं अधिक सक्षम हैं। इस क्रम में डिजिटल कृषि मिशन और एग्रीस्टैक के तहत किसान पहचान, फसल प्लाटों का डिजिटलीकरण, ड्रोन- आधारित सेवाएं, कीट-रोग निगरानी, मौसम और स्थान विशेष की आवश्यकता के अनुरूप सलाह जैसी व्यवस्था की जा रही है।

भारत को दुनिया की खाद्य, पोषण और जलवायु चुनौतियों के बीच अपने कृषि-तंत्र को और मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री का विजन स्पष्ट है कि किसान की आय बढ़े, उसकी मेहनत का उचित सम्मान और मूल्य मिले, दालों, तिलहनों और कपास में आत्मनिर्भरता से पोषण, तेल, वस्त्र सुरक्षा मजबूत हो। प्राकृतिक खेती, खेत बचाओ अभियान और जलवायु -अनुकूल तकनीक से खेत की मिट्टी, पानी और किसान की सुरक्षा सुनिश्चित हो और कम उत्पादन वाले जिलों में असमानता घटे। खेती कुशल, लचीली, टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी बने। याद रहे कि जब खेत बचेगा, तब ही किसान बचेगा। जब किसान बचेगा, तब कृषि बचेगी और जब कृषि बचेगी, तब भारत का भविष्य सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा। हमारी नई कृषि यात्रा का सार है-फसल से आगे, किसान के विश्वास और ग्रामीण भारत की समृद्धि की ओर।

(लेखक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री हैं)
response@jagran.com

बिखर रही क्षेत्रीय दलों की राजनीति

उमेश चतुर्वेदी

सत्ता जाते ही नेताओं में अपने दल से पीछा छुड़ाने और सत्ताधारी दल में शामिल होने की हिचक अब नहीं दिखती

बंगाल में सत्ता से दूर होते ही ममता बनर्जी का साथ छोड़ने की उनके सहयोगियों में होड़ लग गई है। चार मई को बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजे आने से पहले अजेय समझी जाती रहीं ममता बनर्जी की पार्टी के लगभग 20 लोकसभा सदस्य बगावत करने के लिए तैयार हैं। उनके राज्यसभा सदस्य भी एक-एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं। उनके 58 विधायक पहले ही बागी हो चुके हैं। चुनावी हार के बाद यह बिखराव कोई पहला नहीं है। तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों के बाद अन्नाद्रमुक को भी बिखराव का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पार्टी नेता पलानीस्वामी हालात पर नियंत्रण पाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। पार्टी ह्विप का उल्लंघन करके विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय का साथ दे चुके 25 में से उनके 21 विधायक नेतृत्व के प्रति आस्था जता चुके हैं। इसके ठीक पहले अरविंद केजरीवाल के सबसे नजदीकी सहयोगी माने जाते रहे राघव चड्ढा की अगुआई में आम आदमी पार्टी के दस में से सात राज्यसभा सदस्यों ने अलग गुट बना लिया। महाराष्ट्र की दो प्रमुख पार्टियां शिवसेना और राकांपा भी ऐसे ही हालात से दो-चार हो चुकी हैं। दोनों ही पार्टियों के बागी अब असली पार्टी बन चुके हैं और पार्टी का अधिकृत चुनाव निशान भी उन्हीं के पास है।

बिखराव वाले दलों में एक समानता है। सभी दल एक तरह से पारिवारिक पार्टी हैं। जब तक इन पार्टियों के साथ जनसमर्थन और सत्ता रही, इनके पारिवारिक मुखिया की हर बात स्वीकार्य रही, लेकिन सत्ता हाथ से जाते ही जिस तरह बिखराव बढ़ा है, उससे साफ है कि बागी दिल से दलीय अनुशासन या नेतृत्व के प्रति निष्ठा से नहीं बंधे थे। ममता बनर्जी के दल में जारी बड़ी बगावत के पीछे भाजपा का हाथ बताया जा रहा है, लेकिन इस आरोप के शोर में ममता के कार्यों और उनकी पार्टी चलाने की शैली को नहीं भुलाया जा सकता। पार्टी नेता मानते हैं कि ममता अधिनायकवादी ढंग से पार्टी चलाती रहीं। इसके खिलाफ उनकी पार्टी में असंतोष पहले से ही था। एक तरह से अंदर ही अंदर तूफान चल रहा था। अगर पार्टी सत्ता में

वंशवाद की राजनीति से भी बढ़ता है आक्रोश। फाइल

लौट आई होती तो सरकारी ताकत की गोंद और नेताओं की कुछ पा लेने की उम्मीद के चलते यह तूफान थम जाता, लेकिन पार्टी चौथी बार सत्ता में नहीं लौट पाई। लिहाजा अंदर पनप रहा विद्रोह सतह पर आ गया। इस आग में चुनावी हार के बाद हुई पहली बैठक में अभिषेक बनर्जी की मनमानी ने घी का काम किया। पार्टी के जीत की स्थिति में अभिषेक की बात मानने का फरमान स्वीकार हो जाता, लेकिन तृणमूल कार्यकर्ता अपनी हार के लिए अभिषेक की कार्यशैली को ही जिम्मेदार मानते हैं। लिहाजा उन्हें अभिषेक की सरपरस्ती मंजूर नहीं हुई। कार्यकर्ताओं को यह मलाल रहा कि तृणमूल बनाने वाले पिछड़ते गए और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ताकतवर होते गए। कुछ ऐसे ही हालात राकांपा में भी रहे। शरद पवार ने पार्टी की स्थापना की, उसमें उनका साथ उनके भतीजे अजीत पवार ने दिया। अजीत शरद पवार के स्वाभाविक उत्तराधिकारी माने जाते थे, लेकिन सुप्रिया सुले के आने के बाद उन्हें लगा कि जिस पार्टी को उन्होंने सींचा है, उसकी कमान उनके हाथ आने से रही तो उन्हें भी बगावत की राह सूझी। शिवसेना की स्थिति थोड़ी अलग रही।

शिवसेना की पूरी राजनीति कट्टर हिंदुत्व के इर्द-गिर्द रहते हुए कांग्रेस विरोध पर टिकी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिद में भाजपा को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस का हाथ थाम लिया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं के सामने वैचारिक संकट खड़ा हो गया। जैसे ही सत्ता शिवसेना के हाथ से फिसली, पार्टी दोफाड़ हो गई। रही बात आम आदमी पार्टी की तो आंदोलन से निकली इस पार्टी ने पहले वैचारिकता प्रतिबद्धता का आदर्शवादी माडल प्रस्तुत करने का दावा किया, लेकिन बाद में वहां एकाधिकारवाद बढ़ता गया। अन्नाद्रमुक में विद्रोह की बड़ी वजह सत्ता से बढ़ती दूरी से उपजी निराशा रही।

विपक्षी दलों में बिखराव का भाजपा को फायदा होगा, लेकिन इस तथ्य को भुलाया नहीं जा सकता कि लोकतांत्रिक राजनीति की बुनियाद में वैचारिक निष्ठा बेहद अहम है। दलों के अपने सिद्धांत इसी बुनियाद पर आधारित होते हैं और वे इसी आधार पर वोट मांगते हैं। हालांकि विचारधारा की राजनीति में गिरावट लंबे अर्से से दिख रही है, लेकिन अब यह चरम पर है। सत्ता जाते ही अपने दल से पीछा छुड़ाने और सत्ताधारी दल में शामिल होने की हिचक अब नहीं दिखती। हैरत की बात है कि उन्हें शामिल कराने वाला दल भी उनके पहले के अपशब्दों और निजी आक्षेपों को भुला देता है। निष्ठाएं बदलने के पीछे एक वजह चुनावी राजनीति का लगातार महंगा होता जाना भी है। अकूत संपत्ति के बिना आज के दौर में अपने दम पर चुनाव लड़ पाना आसान नहीं है। सामान्य पृष्ठभूमि के वही उम्मीदवार चुनावी मैदान में गंभीर चुनौती देने में कामयाब होते हैं, जिनका दल मजबूत होता है या फिर उनका राजनीतिक नेतृत्व उनका साथ देता है। चूंकि सत्ता की ही सवारी के जरिये ताकत और संपत्ति कमाई जा सकती है, इसलिए वैचारिक निष्ठाएं त्यागने में देर नहीं लगती।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

निर्मल मन

ऋषियों ने सभी प्राणियों को ईश्वर का अंश माना है और उनमें मनुष्य को श्रेष्ठ बताया है। मनुष्य के पास 'मन' है, जिसके आधार पर वह अपना जीवन व्यतीत करता है। मूलतः मन सदैव सही मार्ग दिखाता है। एक प्रकार से मन मनुष्य का न्यायाधीश होता है, किंतु कभी-कभी बाहरी प्रभावों के कारण उसकी निर्मलता प्रभावित हो जाती है। जब मन पर नकारात्मक भावों और विचारों का प्रभाव पड़ने लगता है, तब बुद्धि और विवेक के माध्यम से उन विचारों का मंथन करना आवश्यक हो जाता है। गलत रास्ते पर चलने का परिणाम अंततः कष्ट ही होता है। यदि बुद्धि और विवेक व्यक्ति को गलत कार्यों से रोक लें तो वह जितेंद्रिय बन सकता है।

गोस्वामी तुलसीदास ने 'निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा' चौपाई के माध्यम से मन की निर्मलता पर विशेष बल दिया है। वे कहते हैं कि निर्मल मन वाला व्यक्ति ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान भले ही सशरीर प्राप्त न हों, किंतु उनका परमानंदमय स्वरूप अवश्य अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अंतर्मन से प्रसन्न है तो समझना चाहिए कि उस पर ईश्वर की कृपा बरस रही है। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति भीतर से दुखी है, तनाव, ईर्ष्या, निंदा और छल-कपट में डूबा हुआ है तो यह संकेत है कि वह ईश्वर से दूर होता जा रहा है। ऐसे व्यक्ति के आसपास नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है। कपट, छल और छिद्रान्वेषण दैत्य प्रवृत्ति के लक्षण माने गए हैं।

निर्मल मन वाले व्यक्ति के शरीर से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। वह जहां भी जाता है, वहां का वातावरण सकारात्मक बन जाता है और उसके शुभ परिणाम दिखाई देने लगते हैं। इसलिए यह मनुष्य के हाथ में है कि वह कैसा बनना चाहता है- भगवत्कृपा से युक्त या दुष्प्रवृत्तियों से प्रभावित।

सलिल पांडेय

राष्ट्र सुरक्षा का स्मार्ट कवच

देवेंद्रराज सुथार

किसी भी राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित हैं तो समाज सुरक्षित है, अर्थव्यवस्था सुरक्षित है और भविष्य सुरक्षित है

हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्मार्ट बार्डर परियोजना की घोषणा की। यह भारत की सुरक्षा सोच में हो रहे उस परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था की जगह सक्रिय और पूर्वानुमान आधारित सुरक्षा तंत्र विकसित करने का प्रयास दिखाई देता है। लंबे समय तक सीमा प्रबंधन का अर्थ था- बाड़ लगाना, चौकियां बनाना और गश्त बढ़ाना, लेकिन आज का समय ऐसी व्यवस्था की मांग करता है, जो खतरे को घटित होने से पहले पहचान सके और उसका उत्तर तत्काल दे सके।

यह समझना आवश्यक है कि किसी राष्ट्र की सीमाएं केवल बाहर से आने वाले शत्रुओं को रोकने का माध्यम नहीं होतीं। वे राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य की भी रक्षा करती हैं। सीमाओं के रास्ते होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी केवल अपराध नहीं है, वह देश की युवा शक्ति पर सीधा हमला है। नकली मुद्रा का नेटवर्क केवल वित्तीय अपराध नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का संगठित प्रयास है। मानव तस्करी केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मानव गरिमा के विरुद्ध अपराध है। इसलिए जब सीमा सुरक्षा की चर्चा होती है, तब उसके भीतर आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सांस्कृतिक सुरक्षा के अनेक आयाम समाहित होते हैं।

यही कारण है कि स्मार्ट बार्डर की अवधारणा अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह सुरक्षा बलों की क्षमता को तकनीक की शक्ति से जोड़ने का प्रयास है। आधुनिक सेंसर, निगरानी प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण, ड्रोन और रीयल-टाइम संचार नेटवर्क केवल उपकरण नहीं हैं, वे सुरक्षा व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, त्वरित और प्रभावी बनाने वाले साधन हैं। भविष्य के संघर्षों और अपराधों का स्वरूप तकनीक आधारित होगा, इसलिए उनकी रोकथाम भी तकनीक आधारित होनी चाहिए। यदि अपराधी ड्रोन, एन्क्रिप्टेड संचार और डिजिटल नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं तो सुरक्षा एजेंसियों को उससे अधिक उन्नत साधनों से लैस होना ही पड़ेगा। आज यह स्पष्ट हो चुका है कि सीमा प्रबंधन केवल सुरक्षा बलों का दायित्व नहीं हो सकता। स्थानीय प्रशासन, खुफिया तंत्र, तकनीकी संस्थान और सीमावर्ती समाज-सभी की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। सुरक्षा केवल बंदूक से नहीं आती, वह सूचना, समन्वय, तकनीक और सामाजिक सहभागिता से भी निर्मित होती है।

2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखने वाले भारत के लिए मजबूत सीमाएं अनिवार्य शर्त हैं। आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक-दूसरे के पूरक हैं। असुरक्षित सीमाओं वाला राष्ट्र दीर्घकालिक विकास की यात्रा में स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए सीमा सुरक्षा पर किया गया प्रत्येक निवेश वस्तुतः भारत के भविष्य पर किया गया निवेश है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

झूठे मुकदमेबाजों पर लगे अंकुश

कानूनों का दुरुपयोग रोकने का समय-शीर्षक से लिखे आलेख में डा. ऋतु सारस्वत ने बिल्कुल सही कहा है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले वास्तविक उत्पीड़न के मामलों में कानून का कठोर होना जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी झूठे और दुर्भावनापूर्ण मुकदमों पर भी अंकुश लगाना है, क्योंकि कानून का दुरुपयोग न केवल निर्दोष व्यक्तियों को पीड़ा देता है, बल्कि न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को भी कमजोर करता है। सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब व्यक्तिगत और पारिवारिक विवादों में अदालतों और पुलिस की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। यह केवल न्याय व्यवस्था पर बढ़ते बोझ का संकेत नहीं है, बल्कि समाज में बढ़ रही कटुता और संवाद की कमी को भी दिखाता है। कई मामलों में लोग समाधान खोजने के बजाय सीधे कानूनी लड़ाई का रास्ता चुन रहे हैं। समस्या का दूसरा पक्ष समाज का रवैया है। अक्सर लोग तथ्यों और जांच से पहले आरोपों पर भरोसा कर लेते हैं। अदालत का फैसला वर्षों बाद आता है, लेकिन सामाजिक फैसला उसी दिन सुना दिया जाता है, जिस दिन आरोप लगता है। यह न्याय की मूल भावना के खिलाफ है। समाधान केवल नए कानून बनाने में नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया को तेज और निष्पक्ष बनाना होगा, ताकि न पीड़ित को वर्षों इंतजार करना पड़े और न निर्दोष व्यक्ति अनावश्यक परेशानी झेले। साथ ही यदि अदालत में यह साबित हो जाए कि किसी ने जानबूझकर झूठा आरोप लगाया, फर्जी साक्ष्य दिए या कानून का दुरुपयोग किया तो उसके लिए सख्त दंड होना चाहिए। न्याय तभी सार्थक है, जब उसमें अधिकारों के साथ जवाबदेही भी शामिल हो।

अमन सिंह गौर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

मेलबाक्स

गृहिणियों के लिए सम्मान

सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के फैसले में गृहिणियों को राष्ट्र निर्माता कहे जाने पर जोर दिया, जो उन महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान की बात है जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने घर, परिवार को समर्पित कर दी। देश में महिलाओं को अधिकतर गृहिणियों के रूप में जाना जाता है। और उनका दायरा घर परिवार तक ही सीमित समझा जाता है। घर के कार्य, परिवार की जरूरतों का ध्यान रखना उनका दायित्व समझा जाता है। इन सबके लिए उन्हें न कभी प्रशंसा मिलती है, न मेहनताना और न ही सम्मान। ऐसा भी देखा गया है कि पुरुष भी समाज और लोगों से अपनी पत्नी को गृहणी के रूप में परिचय कराने में शर्म महसूस करते हैं। एक गृहिणी अपने सपनों, ख्वाहिशों को दरकिनार कर बगैर कोई छुट्टी लिए दिन-रात काम करती है। ऐसे में उसके काम और काबिलियत को कम आंकना गलत है। वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा, सही मार्गदर्शन कर एक अच्छा इंसान बनाती है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं जो युवा बन देश के निर्माण में सहयोग देते हैं। गृहिणियों के घर, परिवार, समाज और राष्ट्र में योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। उन्हें राष्ट्र निर्माता कहना उनके गृह कार्य का सम्मान है।

अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

अमेरिका और ईरान युद्ध रोकें

अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध छिड़ने के के कारण विश्व अर्थव्यवस्था के लिए समस्याएं बढ़ रही है। होर्मुज समुद्री जल मार्ग बंद होने से तेल और गैस के दाम बढ़ेंगे। जिसके कारण भारत में और एशिया में महंगाई बढ़ेगी। अमेरिका और ईरान को समझौता करने के लिए भारत को वैश्विक दबाव बनाना होगा। ईरान को हिजबुल्लाह का समर्थन बंद करना होगा। होर्मुज घाटी में आने जाने वाले पूरे विश्व के जहाजों पर हमला करने से चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका दोनों को रोकना होगा। अमेरिका होर्मुज की नाकेबंदी तुरंत हटाए और विश्व के सभी देशों के जहाजों को वहां से आने जाने दे। और किसी भी जहाज पर कोई भी हमला न करें। ऐसा करने के लिए विश्व के सभी देशों को एक होकर अमेरिका और ईरान पर वैश्विक दबाव बनाना होगा।

ativir.jain@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

4.11 करोड़ कंटेनर को लोड-अनलोड किया था वर्ष 2024 में सिंगापुर के बंदरगाह ने, जबकि भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक व्यस्त जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ने उसी वर्ष महज 70 लाख कंटेनर को लोड-अनलोड किया था।

आजकल

प्रतिद्वंद्वी नहीं सहयोगी बने चीन

चीन सरकार के एक प्रवक्ता ने हाल ही में कहा है कि भारत और चीन को एक-दूसरे को प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि सहयोगी मानना चाहिए। यह वक्तव्य उस देश से आया जो एक ओर एलएसी पर दबाव बनाए रखता है तो दूसरी ओर हमसे व्यापारिक लाभ भी चाहता है। यह विरोधाभास ही चाणक्य के उस सिद्धांत की आधुनिक परीक्षा है, जो कहता है कि पड़ोसी सदा प्रतिस्पर्धी होते हैं, इसलिए पड़ोसी के पड़ोसी से मित्रता लाभकारी होती है। लिहाजा हमें इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझना होगा

प्रो. एम. एल. मीणा
विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

इतिहास में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब कोई राष्ट्र अपनी भौगोलिक नियति के ठीक सामने खड़ा होता है, किंतु उसे पहचानने में चूक जाता है। प्राचीन रोम ने भूमध्य सागर की केंद्रीयता को पहचाना और उसे अपनी शक्ति का आधार बनाया था। सातवीं शताब्दी के अरब व्यापारियों की सफलताओं को देखें तो उन्होंने हिंद महासागर के मानसूनी पवनों की लय को समझा और एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप के बीच व्यापार का सूत्र अपने हाथ में ले लिया था। 20वीं शताब्दी में सिंगापुर ने मलक्का जलडमरूमध्य की भौगोलिक अनिवार्यता को अपनी संपत्ति बनाया और एक ऐसे द्वीप को, जिसके पास न कृषि-योग्य भूमि थी और न प्राकृतिक संसाधन, विश्व के सर्वाधिक समृद्ध राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। इन सबमें एक समान सूत्र है कि भूगोल के द्वारा प्रदत्त अवसर को नीति ने सही समय पर पहचाना था। भारत के सामने आज ठीक वैसा ही एक ऐतिहासिक क्षण है, किंतु उस क्षण और भारतीय नीति विमर्श के बीच एक गहरी, अनकही दूरी है जो देश की सबसे बड़ी अनुत्तरित भू-राजनीतिक पहेली बन गई है।

इस पहेली को समझने के लिए पहले उस आर्थिक वास्तविकता को देखना होगा जो भूगोल ने स्वयं रची है। वर्ष 2024 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 138 अरब डालर तक पहुंच गया था। यह एक ऐसा संबंध है जो पिछले एक दशक में चार गुना विस्तृत हो चुका है। किंतु इस विस्तार की प्रकृति पर ध्यान देना आवश्यक है। वर्ष 2005 में भारत ने चीन को 10 अरब डालर का निर्यात किया था, 2024 में यह केवल 14.9 अरब डालर तक ही पहुंच पाया। उसी अवधि में चीन से आयात दस गुना बढ़कर 100 अरब डालर से अधिक हो गया और वित्त वर्ष 2025-26 में यह व्यापार-घाटा 102 अरब डालर को पार कर गया था। अगर थोड़ा सा और गहराई से देखें तो भारत की जिस सौर ऊर्जा क्रांति पर जलवायु परिवर्तन के लिए नेतृत्व का दावा किया जाता है, उसके पैनल तो चीन में बनते हैं। जिन दवाओं को भारत विश्व की फार्मेसी कहकर निर्यात करता है, उसके मूल रासायनिक घटक चीन से आते हैं। यह विवरण यह समझने के लिए है कि भूगोल ने जो आर्थिक गुरुत्वाकर्षण बनाया है, वह नीतिगत घोषणाओं से नहीं टूटता है।

अब उस दूसरे छोर की ओर दृष्टि डालते हैं। वर्ष 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 प्रतिशत तक आयात-शुल्क लगाया जो किसी भी प्रमुख साझेदार देश पर उस दौर का सर्वाधिक शुल्क था। फिर भी भारत ने फरवरी 2026 में अमेरिका के साथ व्यापार समझौता किया जिसमें अमेरिकी माल भारत में शून्य शुल्क पर आ सकता है, जबकि भारतीय माल पर अभी भी 18 प्रतिशत शुल्क लागू है। इसके बदले भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीद में भारी कटौती का अनौपचारिक वचन दिया था। एक ऐसे देश के लिए जो रणनीतिक स्वायत्तता को अपनी विदेश नीति का प्राण बताता है, यह समझौता उस स्वायत्तता की कीमत का एक ठोस दस्तावेज बन गया है। यहां एक और मूलभूत प्रश्न उठता है कि वैश्विक व्यापार में आज भौगोलिक निकटता को आपूर्ति- श्रृंखलाओं की प्राथमिकता माना जा रहा है। ऐसे में एक ऐसे साझेदार के साथ दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति बनाना, जो न सिर्फ भौगोलिक रूप से दूर है, बल्कि उसकी नीतियां भी प्रत्येक चुनाव-चक्र के साथ बदल जाती हैं, कितनी टिकाऊ नींव हो सकती है?

इस प्रश्न का उत्तर आने वाले दशक की भू-राजनीतिक संरचना में निहित है। अमेरिका का वैश्विक नेतृत्व अब उतना निर्विवाद नहीं रहा जितना शीत युद्ध के बाद तीन दशकों तक रहा था। यूरोप की भी आंतरिक राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में नई जटिलताएं उभर रही हैं। वहीं रूस को यह काफी हद तक समझ आ गया है कि वह अब अकेले वैश्विक नेतृत्व नहीं कर सकता है। इसमें चीन और रूस की साझेदारी को अगर संभावना के रूप में देखें तो यह जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक परतदार है।

चीनी राष्ट्रपति की उत्तर कोरिया की हालिया यात्रा इसी बहुआयामी गणित का हिस्सा है। एक और उदाहरण हम देखें तो जो आस्ट्रेलिया क्वाड और हिंद-प्रशांत साझेदारी का महत्वपूर्ण सदस्य है, उसी के आर्थिक हित तो चीन के साथ गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। इन सब प्रवृत्तियों को देखें तो रूस, चीन और दक्षिण एशिया को मिलाने वाली एक नई भू-राजनीतिक चाप की संभावना प्रबलता से उभर रही है, जिसे भौगोलिक आधार भी प्राप्त है।

इस बीच यदि अमेरिका भविष्य में किसी भी कारण से हिंद-प्रशांत क्षेत्र से स्वयं को हटाता है, तो भारत को अपने क्षेत्र में उभरती भू-राजनीतिक चाप में ही स्वयं को एक निर्णायक अभिनेता के रूप में स्थापित करना होगा। क्या भारत इसके लिए तैयार है, यह नीतिगत प्रश्न है।

इन सब तथ्यों को एक साथ देखें तो यह स्पष्ट होता है कि भारत के पास एक अद्वितीय कूटनीतिक प्रयोगशाला है। उसकी भौगोलिक स्थिति उसे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच दो सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मध्य, और पूर्व से पश्चिम जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यापार-मार्गों के केंद्र में रखती है। यह वह भूगोल है जिसके लिए इतिहास गवाह है कि ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान या जर्मनी में से कोई भी अपनी संपूर्ण संपदा देने को तैयार हो सकता था। प्रश्न केवल यह है कि भारत उस भौगोलिक नियति को उस विदेश नीति से कब जोड़ेगा जो किसी भी राष्ट्र के व्यवहार को आकार लेती है।

भारत में बंदरगाहों के समग्र विकास से माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का योगदान बढ़ सकता है। फाइल

भारतीय आर्थिकी में हिंद महासागर का बढ़े योगदान

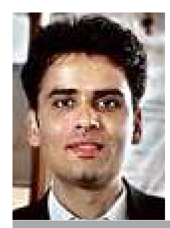

रवि दास बिश्नोई
वरिष्ठ अध्येता, इंडो पैसिफिक डोमेन

भूगोल और अर्थशास्त्र के बीच एक स्वाभाविक संबंध होता है कि जो देश व्यापारिक मार्गों के केंद्र में होगा, वह साधारणतः उन मार्गों से लाभ भी उठाएगा। परंतु भारत इस नियम का एक असाधारण अपवाद है। साढ़े सात हजार किलोमीटर से अधिक की तटरेखा, हिंद महासागर के उत्तरी छोर पर केंद्रीय स्थिति, और फिर भी वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी केवल दो प्रतिशत है। हम अगर तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य से देखें तो यहां पर सिंगापुर का उदाहरण बहुत उपयोगी होगा। 2024 में सिंगापुर के बंदरगाह ने 4.11 करोड़ कंटेनर संभाले थे, जबकि भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ने उसी वर्ष महज 70 लाख कंटेनर। यह अंतर सिर्फ अधोसंरचना का नहीं है। सिंगापुर इसके लिए भूभाग, बड़ी जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन का तर्क नहीं दे सकता है, क्योंकि वहां इन कारकों का तो अभाव है। भारत के पास भौगोलिक स्थिति सिंगापुर से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है, परंतु इच्छाशक्ति के अभाव में शायद ऐसा नहीं हो पाया है।

इस स्थिति का एक और पहलू है जो और अधिक विचारणीय है। भारत का 95 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयतन की दृष्टि से समुद्री मार्ग से होता है, परंतु उस व्यापार को ढोने वाले जहाजों में भारत की हिस्सेदारी वैश्विक क्षमता का केवल 1.3 प्रतिशत है। अर्थात भारत का माल भारतीय जहाजों के बजाय विदेशी जहाजों में जाता है, और उन जहाजों का किराया भारत विदेशी मुद्रा में चुकाता है। 2022-23 में भारत ने माल-भाड़े के रूप में लगभग 75 अरब डालर से अधिक विदेशी मुद्रा खर्च की थी। हमने यह भी बड़े स्तर पर यह अनुभव किया था कि हमारा अधिकतर निर्यात तो पारगमन निर्भरता से प्रभावित है। जैसे पहले व्यापारिक वस्तुएं श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह या सिंगापुर जाएं, फिर वहां से बड़े जहाजों में लादकर आगे भेजा जाए। एक भौगोलिक सत्य यह भी है कि भारत के बंदरगाहों की गहराई और अधोसंरचना अभी उस स्तर पर नहीं है जहां बड़े मालवाहक जहाज सीधे तौर पर व्यापकता के साथ भारतीय बंदरगाहों पर रुक सकें। इसका परिणाम यह है कि भारत का तट व्यापार का केंद्र बनने के बजाय व्यापार का एक पड़ाव बनकर रह गया है।

इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक तथ्य याद आता है। चोल साम्राज्य ने 11वीं शताब्दी में इसी हिंद महासागर को अपनी व्यापारिक धुरी बनाया था और दक्षिण-पूर्व एशिया तक अपना प्रभाव स्थापित किया था। उस काल में भारत का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा 30 प्रतिशत से अधिक था। वह समृद्धि स्थल-मार्गों से नहीं, समुद्री व्यापार से आई थी। आधुनिक भारत ने उस इतिहास को स्मृति में तो रखा, परंतु नीति में उतारना शेष रह गया है। आधुनिक भारत में सरकार ने 2047 तक भारत को विश्व के शीर्ष पांच समुद्री राष्ट्रों में लाने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में सागरमाला परियोजना के अंतर्गत 5.8 लाख करोड़ रुपये के निवेश की भी योजना है। परियोजना के भाग के रूप में ही वाधवान में एक नए बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है। ये सब सकारात्मक संकेत हैं। हमें उस मानसिकता को भी बदलना होगा जिसने भारत को एक स्थलीय सभ्यता के रूप में परिभाषित किया और समुद्र को व्यापार का माध्यम नहीं, बल्कि सीमा के रूप में देखा था।

ऐसे में हिंद महासागर आज की सदी के लिए महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक धुरी है। चीन इसे समझकर श्रीलंका, पाकिस्तान और अफ्रीका में बंदरगाह बना चुका है। यह भारत के तट के प्रभावाधीन है, परंतु उस तट का पूरा अर्थशास्त्र अभी लिखा जाना बाकी है। इसलिए भारत को यथाशीघ्र इस क्रम में सकारात्मक प्रयास करने ही होंगे।

खरी-खरी

खेला होए गे चे

विनय कुमार पाठक

खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब... पर आज क्या स्थिति है। खिलाड़ी देश के लिए नाज है। वैसे सभी नहीं। जो ऊंचाई पर पहुंच पाए वही। और क्रिकेट में जो आइपीएल तक पहुंच गए वह भी। क्रिकेट को अलग ही दर्जा मिला है हमारे देश में। वरीयता क्रम में क्रिकेट का सौवां खिलाड़ी जितना लोकप्रिय होता है अन्य खेल के पहले रैंक वालों को भी वह नसीब नहीं होती। शतरंज, टेनिस और बैडमिंटन खिलाड़ी फिर भी कुछ भाग्यशाली होते हैं।

खिलाड़ी सिर्फ खेल में नहीं, अन्य क्षेत्र में भी होते हैं। अतः यहां बात उस खेल की नहीं हो रही है। बात हो रही है खेला की। जिसके बारे में एक महिला नेता ने यह कहकर कि 'खेला होबे' पिछले चुनाव में गजब की पटकनी दी थी विरोधियों को। अब खेल में जीत और हार तो लगे रहते हैं। कई बार अंतिम समय में कुछ ऐसा होता है कि जीता हुआ पक्ष हार जाता है और हारा हुआ पक्ष जीत जाता है। और भितरघात तो ऐसी चीज है जो खेल का सत्यानाश कर देता है। रावण की ओर से सोचें तो विभीषण ने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया था। तो इस बार विरोधियों ने इस महिला नेता को धोबीपछाड़ दे दिया।

कई बार ऐसा भी होता है कि हार जाने के बाद हारे हुए लोग सुल्तानपुर के मजरूह का गीत गुनगुनाने को बाध्य हो जाते हैं- कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। 'खेला होबे' में इस बार परिणाम उलट गया। महिला नेता के करीबी लोग अब उन्हीं के गोल पोस्ट में ही दनादन गोल दागने लगे हैं। कोई पैर से तो कोई हेड से गोल कर रहा है। एक गोलकीपर और गोल करने वाले इतने लोग! वे कैसे बचा पाएंगी, यह तो भविष्य के गर्भ में है। परंतु अभी तो उन्हें एक पार्टी की शरण में जाना पड़ रहा है। उसी पार्टी की शरण में जिससे वे दशकों पहले अलग हुई थीं। और गठबंधन में उस पार्टी को एक भी सीट देने के लिए राजी नहीं थीं। उनका कहना था कि वह पार्टी तो समाप्त हो गई है, उसे सीट देना बेमानी है। इस पूरे प्रकरण से हमें यह शिक्षा यह मिलती है कि राजनीति में किसी को भी स्थायी दुश्मन नहीं समझना चाहिए।

पोस्ट

तृणमूल में लगातार टूट की खबरें यही साबित करती हैं कि क्षेत्रीय दलों की कोई विचारधारा नहीं होती। यहां सब कुछ सुविधा पर टिका होता है। सुविधाएं खत्म तो रिश्ता खत्म।
नवनीत मिश्रा@navneetmishra99

आजकल चुनावी रणनीतिकार बहुत हैं, संगठन शिल्पी भी मिल जाते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में तो पार्टी टूट बचाओ विशेषज्ञ का पद भी अब हर दल में आवश्यक होता जा रहा है।
डा. अवनींद्र राय@avanindra43

सबसे भयानक विमान हादसों में से एक में 260 लोगों की मौत के एक साल बाद भी जांच के बारे में हमारे पास बस यही जानकारी है कि न कोई शुरुआती रिपोर्ट, न ही कोई फाइनल रिपोर्ट। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उन्हें अब तक कोई समाधान या राहत नहीं मिली है।
विष्णु सोम@VishnuNDTV

जसपाल राणा के आकस्मिक निधन ने पूरे देश को झकझोर दिया है। उन्होंने खुद तो देश का नाम रोशन किया ही, भारत का नाम चमकाने वाले नए शूटर भी तैयार किए।
संजय निरुपम@sanjaynirupam

बिहार डायरी

विलय या स्वतंत्र अस्तित्व: किसे चुनेंगे उपेंद्र

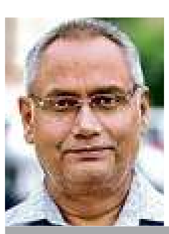

अरुण अशेष
उप राजनीतिक संपादक, बिहार

बिहार के लोग कम से कम इस मामले में बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें राजनीतिक चर्चा के लिए हर समय नया विषय मिल जाता है। पुराने विषयों पर चर्चा करके ये बोर नहीं होते हैं। अभी विषय यह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल के सदस्य दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य क्यों नहीं बनाया गया? यह भी कि बिना किसी सदन के सदस्य रहते वे कितने दिनों तक मंत्री बने रह सकते हैं? लोग संचित और अचानक प्राप्त ज्ञान के आधार पर बहस में हिस्सा ले रहे हैं।

दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं। यह मोर्चा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। उपेंद्र कुशवाहा ने खुल कर किसी नेता का नाम नहीं लिया। लेकिन, मोर्चा के प्रदेश सम्मेलन में उन्होंने कहा कि एक पद के लिए हम अपनी पार्टी का अस्तित्व समाप्त नहीं कर सकते हैं। उसी से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दीपक प्रकाश को विधान परिषद की एक सीट देने के बदले भाजपा ने विलय की शर्त रखी थी। कुशवाहा ने मना कर दिया। मगर, वे निराश नहीं हैं। उन्हें लग रहा है कि राजग का शीर्ष नेतृत्व दीपक के लिए कोई रास्ता निकालेगा। वे 10 जून को आयोजित राजग के समागम में भी शामिल हुए। कुशवाहा और पीएम नरेन्द्र मोदी के हाव-भाव से यही लगा कि दोनों के बीच परिषद की एक सीट को लेकर कटुता भाव नहीं है।

निकट भविष्य में बिहार विधान परिषद की कोई सीट रिक्त नहीं है। इस साल जो रिक्तियां हो रही हैं, वह शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की हैं। इनमें दलों की बड़ी भूमिका नहीं होती है। जीत के लिए उम्मीदवारों को वर्षों पहले से तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए परिषद की इन सीटों पर दीपक के उम्मीदवार बनने की संभावना नहीं के बराबर है। बहस में

उपेंद्र कुशवाहा। फाइल

उपेंद्र कुशवाहा के विरोधी उन पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। यह आरोप टिक नहीं पाता है, क्योंकि सभी क्षेत्रीय दलों में परिवारवाद है। जदयू इससे अछूता था। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद जदयू भी अपवाद नहीं रहा। राजद, लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पहले से ही परिवारवाद पर आश्रित हैं। हां, भाजपा पर क्षेत्रीय दलों को निगलने और उसके विधायकों को तोड़ने का आरोप लग रहा है। इसके लिए भाजपा की आलोचना भी हो रही है।

बहस को अतीत की घटनाओं से जोड़ें तो इसमें भी कुछ नयापन नहीं है। बिहार में क्षेत्रीय दल क्या, राष्ट्रीय दलों के विधानमंडल दल में विभाजन होता रहा है। वर्ष 1995 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा विधायक दल में विभाजन को गया था। उसके 39 में से 13 विधायक अलग हो गए। संपूर्ण क्रांति दल का गठन किया। लालू प्रसाद की अगुआई वाली तत्कालीन जनता दल की सरकार का समर्थन किया। वर्ष 1990 से 2000 के बीच राज्य में दलबदल का ऐसा सिलसिला चला कि लालू प्रसाद को सरकार बनाने में सहयोग करने वाले दल भी स्वयं को नहीं बचा पाए। लालू ने इंडियन पीपुल्स फ्रंट (अब भाकपा माले), भाकपा और झामुमो विधायक दल को तोड़ कर उसके सदस्यों को अपने दल में मिला लिया। यह अलग तथ्य है कि टूट के शिकार लालू प्रसाद भी हुए। इसी अवधि में समता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी आदि का गठन हुआ, जो मूल जनता दल से निकले नेताओं की पार्टियां हैं।

उपेंद्र कुशवाहा भी इसी धारा की राजनीति की उपज हैं। वर्ष 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग की सरकार बनने के बाद भी यह चलन समाप्त नहीं हुआ। अलगाव के समय में नीतीश ने भी भाजपा के तीन विधायकों को अपने दल में शामिल करा लिया। दलबदल कानून की परिधि में आने के कारण इन विधायकों की सदस्यता जा सकती थी। इन विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया। उन्हें विधान परिषद की सदस्यता दिलाई गई। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी के चार विधायक बने थे। यह राजग की घटक पार्टी थी। नीतीश सरकार का समर्थन कर रही थी। फिर भी वीआइपी के चारों विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिए गए।

वर्ष 2023 के जून में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा नीतीश सरकार से अलग हो गई। इसके संस्थापक जीतन राम मांझी का कहना था कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि अपनी पार्टी का जदयू में विलय करा दीजिए। मांझी राजी नहीं हुए। उनके पुत्र संतोष कुमार ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। नीतीश उस समय महागठबंधन की मदद से सरकार चला रहे थे। बाद में राजग में शामिल हुए, मांझी पहले वहां पहुंच गए थे। लोजपा का विभाजन भी इसी अवधि में हुआ। उसके छह में से पांच सांसद अलग होकर राजग में चले गए। इस पृष्ठभूमि उपेंद्र कुशवाहा को मिला विलय का प्रस्ताव अनोखा है। हां, विलीन होने और इस तरह के प्रस्ताव को निरस्त करने के उदाहरण भी हैं। बहस में शामिल लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अंततः उपेंद्र कुशवाहा किस विकल्प का चयन करेंगे।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया जाना सही है?

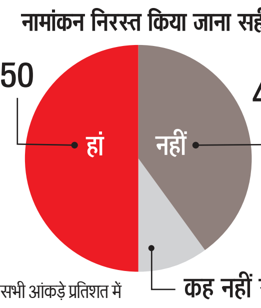

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

केन विलियमसन न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास के अभी तक के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

हुआ भतीजा रोग सा किंतु न छूटे साथ,
आखिर इस अभिषेक में कुछ तो होगी बात।
कुछ तो होगी बात छूटते जाएं साथी,
पर वारिस का साथ छोड़ ममता ना पातीं।
सिर पर उसे चढ़ाय रही हैं भोग नतीजा,
दल की खातिर कर्क रोग सा हुआ भतीजा!
-ओम प्रकाश तिवारी

मंथन

महंगाई और विकास में संतुलन

अनेक वैश्विक कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में महंगाई को नियंत्रण में रखते हुए विकास कार्यों की गति बनाए रखना मुश्किल है

सतीश सिंह
आर्थिक मामलों के जानकार

भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय एक जटिल मोड़ पर खड़ी है। एक ओर विकास दर अभी भी मजबूत बनी हुई है, तो दूसरी ओर महंगाई के फिर से सिर उठाने, रुपये की कमजोरी, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक अनिश्चितताओं ने नीति-निर्माताओं की चुनौती बढ़ा दी है। ऐसे समय में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों को यथावत रखते हुए विदेशी पूंजी प्रवाह बढ़ाने और रुपये को सहारा देने वाले कई कदम उठाए हैं। क्या इन पहलों से बढ़ती महंगाई, रुपये की कमजोरी, विदेशी निवेश में कमी और विकास दर पर मंडरा रहे जोखिमों को नियंत्रित किया जा सकेगा?

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। साथ ही स्थायी जमा सुविधा दर को 5.0 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा दर को 5.5 प्रतिशत पर यथावत रखा गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि फिलहाल होम लोन, कार लोन और अन्य खुदरा ऋणों की ईएमआइ बढ़ने की तत्काल आशंका नहीं है। इससे आम उपभोक्ता पर ब्याज लागत का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और खपत, बचत तथा निवेश को कुछ सहारा मिल सकता है।

हालांकि रेपो दर को स्थिर रखा गया है और ऐसा करना यह संकेत नहीं है कि महंगाई का खतरा समाप्त हो गया है। खुदरा महंगाई दर आगे बढ़कर 4.6 प्रतिशत से 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वहीं, अप्रैल 2026 में थोक महंगाई मार्च के 3.88 प्रतिशत से बढ़कर 8.30 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो चिंता का विषय है। थोक महंगाई में तेज वृद्धि का असर कुछ समय बाद खुदरा कीमतों पर भी दिख सकता है। इसलिए रिजर्व बैंक के सामने चुनौती यह है कि वह महंगाई पर नजर भी रखे और विकास की गति को ब्याज दरों के दबाव से भी बचाए।

इस बीच महंगाई बढ़ी है जिसके कई कारण हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों और आपूर्ति- श्रृंखला पर दबाव बना हुआ है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने पर भारत का आयात बिल बढ़ता है, चालू खाते के घाटे पर दबाव आता है और रुपया कमजोर होता है। रुपये की कमजोरी से आयात महंगे हो जाते हैं, जिससे महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। इसके अलावा कमजोर मानसून या ला-नीना जैसी परिस्थितियां खाद्य महंगाई को बढ़ा सकती हैं। यही कारण है कि रिजर्व बैंक ने इस बार केवल ब्याज दरों के जरिये महंगाई नियंत्रित करने के बजाय रुपये को सहारा देने और डालर की आवक बढ़ाने पर अधिक जोर दिया है। यदि रुपये में तेज गिरावट होती है, तो कच्चा तेल, खाद्य तेल, उर्वरक, इलेक्ट्रानिक्स और अन्य आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। इसका असर अंततः आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ता है। इसलिए रुपये को स्थिर रखना भी महंगाई नियंत्रण की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने भी बाजार और रुपये पर दबाव बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2025-26 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये की निकासी की। विदेशी निवेशक भारत में निवेश करते समय केवल रुपये में मिलने वाले लाभ को नहीं देखते, बल्कि डालर के हिसाब से वास्तविक रिटर्न का आकलन करते हैं। यदि शेयर बाजार में लाभ हो, लेकिन रुपया कमजोर हो जाए, तो डालर में उनका वास्तविक रिटर्न घट जाता है।

विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है आरबीआइ। फाइल

भारतीय बांड बाजार में विदेशी निवेश की हिस्सेदारी अभी भी बहुत कम है। 31 मार्च 2025 तक सरकारी और कारपोरेट बांड मिलाकर भारतीय बांड बाजार लगभग 238 लाख करोड़ रुपये का था, जिसमें विदेशी निवेशकों का योगदान करीब 3.75 लाख करोड़ रुपये यानी लगभग 1.6 प्रतिशत था। इसका अर्थ है कि भारत के बांड बाजार में विदेशी निवेश बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। यही वह क्षेत्र है, जहां रिजर्व बैंक और सरकार विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की संभावना देख रहे हैं।

कुल मिलाकर, रिजर्व बैंक की मौजूदा नीति संतुलन साधने की कोशिश है। उसने ब्याज दरें बढ़ाकर विकास पर दबाव डालने के बजाय रुपये को सहारा देने, विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ाने और वित्तीय बाजारों में भरोसा बनाए रखने की रणनीति अपनाई है। महंगाई अभी केंद्रीय बैंक की निर्धारित सीमा के भीतर है। लेकिन अगर महंगाई छह प्रतिशत के स्तर को पार करती है या लंबे समय तक ऊंची बनी रहती है, तो रिजर्व बैंक को नीतिगत दरें बढ़ाने जैसे कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं।

आरबीआइ की पहलों से महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिल सकती है, क्योंकि रुपये में स्थिरता आयातित महंगाई को कम कर सकती है। विदेशी निवेश बढ़ने से डालर प्रवाह मजबूत होगा और रुपये को सहारा मिलेगा। बांड बाजार में विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना है, जबकि शेयर बाजार में असर धीरे-धीरे और सीमित हो सकता है। विकास दर को भी इन कदमों से सहारा मिल सकता है, लेकिन वैश्विक जोखिमों के कारण तेज वृद्धि की राह आसान नहीं।

मई में खाने योग्य तेल का आयात 6.7% बढ़ा

नई दिल्ली : मई में खाने योग्य तेलों का आयात 6.7 प्रतिशत बढ़कर लगभग 13.39 लाख टन हो गया। वहीं इस दौरान भारत का वनस्पति तेल (खाद्य और अखाद्य) का आयात आठ प्रतिशत बढ़कर 13.65 लाख टन हो गया, जबकि मई 2025 में यह 12.67 लाख टन था। नवंबर 2025-मई 2026 के दौरान खाने योग्य तेल का आयात 13 प्रतिशत बढ़कर 92.17 लाख टन हो गया, जबकि पिछले साल इसी समय में यह 81.31 लाख टन था। (प्रेट्र)

स्मार्टफोन खंड में कंपनी की वर्तमान बाजार हिस्सेदारी दो प्रतिशत से कम है, लेकिन पिछले चार वर्षों में इस श्रेणी में हमारी वार्षिक वृद्धि 40-50 प्रतिशत रही है।
-सुनील रैना, प्रबंध निदेशक, लावा इंटरनेशनल लिमिटेड

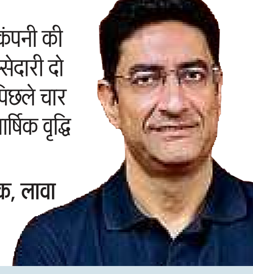

सेंसेक्स	75,527.95	▲ 1,695.40	
निफ्टी	23,622.90	▲ 461.30	
सोना	प्रति दस ग्राम	₹ 1,56,900	▲ ₹ 3,000
चांदी	प्रति किलो ग्राम	₹ 2,55,700	▲ ₹ 10,000
डालर		₹ 95.18	▼ ₹ 0.67
क्रूड	प्रति बैरल	$ 86.78	

एक नजर में

विदेशी मुद्रा भंडार में 71.10 करोड़ डालर की कमी आई

मुंबई : पांच जून को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 71.1 करोड़ डालर घटकर 681.61 अरब डालर रह गया। इससे पिछले सप्ताह मुद्रा भंडार 93.8 करोड़ डालर बढ़कर 682.321 अरब डालर हो गया था। इस दौरान गोल्ड रिजर्व का मूल्य 1.975 अरब डालर बढ़कर 114.575 अरब डालर हो गया। विदेशी मुद्रा आस्तियां (यह विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा होता है) 2.704 अरब डालर घटकर 543.444 अरब डालर रह गया। विशेष आहरण अधिकार 1.8 करोड़ डालर बढ़कर 18.765 अरब डालर हो गए। (प्रेट्र)

सेबी से तीन कंपनियों को आइपीओ की मिली मंजूरी

नई दिल्ली : बोनफिग्लिओली ट्रांसमिशंस, बांबे कोटेड एंड स्पेशनल स्टील्स लिमिटेड और स्वराज ग्रीन पावर एंड फ्यूल लिमिटेड को आइपीओ के जरिये फंड जुटाने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। बोनफिग्लिओली ट्रांसमिशंस के आइपीओ का आकार दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा होने का अनुमान है। आइपीओ पूरी तरह से ओएफएस है, इसलिए कंपनी को इससे कोई फंड नहीं मिलेगा। इश्यू से होने वाली सारी कमाई शेयरधारकों को बेचने वालों को मिलेगी। (प्रेट्र)

सीयूबी ने एफसीएनआर (बी) जमा पर ब्याज बढ़ाया

नई दिल्ली : सिटी यूनियन बैंक (सीयूबी) ने एफसीएनआर (बी) जमा की ब्याज दरों में बदलाव का एलान किया है। यह अनिवासी भारतीय ग्राहकों को विदेशी मुद्रा निवेश पर आकर्षक रिटर्न देगा। 10 जून से बैंक तीन से पांच साल तक की जमा (डालर में) अवधि के लिए 7.10% सालाना की बढ़ी हुई ब्याज दर दे रहा है। संशोधित एफसीएनआर (बी) जमा दरें एनआरआइ को विदेशी मुद्रा में अपने निवेश को बनाए रखते हुए अधिकाधिक रिटर्न कमाने का मौका देती हैं। (वि)

युद्ध खत्म करने के एलान से बाजार में बहार

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगभग चार प्रतिशत गिरकर 90 डालर प्रति बैरल से नीचे आईं

मुंबई, प्रेट्र : कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के एलान से शुक्रवार को शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1,695.40 अंक या 2.30 प्रतिशत उछलकर 75,527.95 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान एक समय यह 1,775.47 अंक या 2.40 परसेंट बढ़कर 75,608.02 पर पहुंच गया था। वहीं एनएसई निफ्टी 461.30 अंक की तेजी के साथ 23,622.90 पर बंद हुआ। ट्रंप की टिप्पणी के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगभग चार प्रतिशत गिर गईं और यह 90 डालर प्रति बैरल से नीचे ट्रेड कर रहा था।

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टूब्रो, इंटरग्लोब एविएशन, टाइटन, इटरनल और एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा फायदे में रहे। टेक महिंद्रा और पावर ग्रिड ही इस सूची में पीछे रहीं। बुधवार को बीएसई सेंसेक्स 150.63 अंक या 0.20 प्रतिशत गिरकर 73,832.55 पर बंद हुआ। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कास्पी 4.63 प्रतिशत उछला जबकि जापान का निक्केई225 इंडेक्स 2.81 प्रतिशत चढ़ा। शंघाई का एसएसई कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंगसेंग भी बढ़त के साथ बंद हुए।

1,695.40 अंक उछलकर 75,527.95 पर बंद हुआ सेंसेक्स

461.30 अंक की तेजी के साथ 23,622.90 पर पहुंचा एनएसई का निफ्टी

सेक्टरवार तेजी% में	
रियल्टी	3.55
इंडस्ट्रियल्स	3.45
फाइनेंशियल सर्विसेज	3.14
प्राइवेट बैंक्स इंडेक्स	3.07
बैंकेक्स	2.94

"भारतीय शेयर बाजार में आज एक मजबूत रिकवरी देखने को मिली। यह रैली वैश्विक जोखिम धारणा में तेज सुधार, भू-राजनीतिक चिंताओं में कमी की वजह से हुई। आज के कदम का सबसे बड़ा कारण पश्चिम एशिया में तनाव में अचानक आया बदलाव था।
हरिप्रसाद के. संस्थापक और शोध विश्लेषक, लाइवलांग वेल्थ

9.66 लाख करोड़ रुपये बढ़ी निवेशकों की संपत्ति

नई दिल्ली, प्रेट्र : शुक्रवार को शेयर बाजार में तेजी के चलते निवेशकों की संपत्ति में 9.66 लाख करोड़ का इजाफा हुआ। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 9,66,538.35 करोड़ रुपये बढ़कर 4,62,00,318.80 करोड़ रुपये (4.84 ट्रिलियन डालर) हो गया।

रुपया 67 पैसे उछलकर 95.18 पर बंद हुआ

शुक्रवार को रुपया डालर के मुकाबले 67 पैसे बढ़कर 95.18 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि घरेलू शेयर बाजार में मजबूती और कमजोर डालर ने भी रुपये को सहारा दिया। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.40 पर खुला और 94.95-95.53 की रेंज में ट्रेड करने के बाद 95.18 पर बंद हुआ। फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी के ट्रेजरी हेड अनिल कुमार भंसाली ने कहा, 'तेल की कीमतें तीन महीने बाद 88.58 डालर के स्तर पर आने से रुपया चढ़ा।

सोना 3,000 तो चांदी 10 हजार रुपये चढ़ी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भू-राजनीतिक तनाव कम होने के संकेत मिलने से शुक्रवार को कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। सोना 3,000 रुपये बढ़कर 1,56,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी में भी सुधार हुआ और 10 हजार रुपये बढ़कर 2,55,700 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

पिछले सत्र में सफेद धातु 2,45,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना थोड़ा कम होकर 4,206.88 डालर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है जबकि चांदी भी 0.48 प्रतिशत गिरकर 67.02 डालर प्रति औंस पर आ गई। कुछ मुनाफावसूली होने के बावजूद इसने अपनी हाल की ज्यादातर बढ़त बनाए रखी है। एलकेपी सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी के मुताबिक, 'निवेशक भू-राजनीतिक स्तर पर होने वाले घटनाक्रमों पर नजर रखेंगे और बातचीत की प्रगति से बुलियन की कीमतों की दिशा तय होगी।

लगातार पांचवें महीने बढ़ी खुदरा महंगाई

- ईंधन और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से मई में 3.93% रही मुद्रास्फीति
- आरबीआइ भविष्य में रेपो रेट में बढ़ोतरी का कर सकता है फैसला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पश्चिम एशिया संकट की वजह से खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। ईंधन और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से मई की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.93 प्रतिशत हो गई जबकि पिछले महीने यह 3.48 प्रतिशत थी। पिछले पांच महीनों से खुदरा महंगाई दर बढ़ रही है और आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो आरबीआइ भविष्य में रेपो रेट में बढ़ोतरी का फैसला ले सकता है।

मई में खाद्य महंगाई दर भी बढ़कर 4.78 प्रतिशत पर पहुंच गई जबकि गत अप्रैल में यह दर 4.20 प्रतिशत थी। खास बात यह है कि अप्रैल और मई दोनों महीनों में शहर के मुकाबले गांव में खुदरा महंगाई दर अधिक दर्ज की गई। आरबीआइ अपने मौद्रिक नीति बनाते समय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) आधारित खुदरा महंगाई को ध्यान में रखता है। पिछले सप्ताह आरबीआइ ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अपने महंगाई के अनुमान को 4.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया। एचडीएफसी बैंक की प्रमुख अर्थशास्त्री साक्षी गुप्ता ने बताया कि 2026-27 में खुदरा महंगाई की दर 5.2 प्रतिशत रहेगी। उनका मानना है कि आबीआइ अगस्त में बैंक दर में बदलाव नहीं करेगा, लेकिन अक्टूबर व दिसंबर की बैठक में महंगाई को रोकने के लिए बैंक दरों में इजाफा कर सकता है।

सबसे अधिक महंगाई तेलंगाना में

मई में सबसे अधिक 6.15 प्रतिशत की खुदरा महंगाई दर तेलंगाना में दर्ज की गई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी राष्ट्रीय महंगाई दर से अधिक दर दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में मई में खुदरा महंगाई दर 3.97 प्रतिशत, उत्तराखंड में 3.72 प्रतिशत, बिहार में 2.94 प्रतिशत, हरियाणा में 3.09 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 4.17 प्रतिशत तो दिल्ली में 2.50 प्रतिशत दर्ज की गई।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

जुलाई से 1.5% तक महंगे हो जाएंगे टाटा मोटर्स के यात्री वाहन

नई दिल्ली, प्रेट्र : टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड आंतरिक दहन इंजन (आइसीई) और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सहित अपने यात्री वाहनों की कीमतों में एक जुलाई से 1.5 प्रतिशत तक की वृद्धि करने का फैसला किया है। वाहनों की कीमतों में यह तीन महीने में दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले कंपनी ने एक अप्रैल से आइसीई व्हीकल रेंज की कीमतें बढ़ाई थीं। इसके पीछे उसने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के चलते बढ़ती लागत को वजह बताया था।

कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा, 'यह मूल्य संशोधन कच्चे माल की बढ़ती लागत और मुद्रास्फीति के निरंतर दबाव के प्रभावों को आंशिक रूप से संतुलित करने के लिए किया जा रहा है।' कंपनी लागत वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा स्वयं वहन कर रही है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डाला जा रहा है।

स्पेसएक्स लाई दुनिया का सबसे बड़ा आइपीओ

एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियन डालर व्यक्ति बने

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्पेसएक्स के नेस्डेक में सूचीबद्ध होते ही एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियन डालर व्यक्ति बन गए हैं। समूह की अन्य कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी को मिला लें तो उनकी कुल संपत्ति 1.1 ट्रिलियन डालर आंकी गई है। कंपनी ने स्पेसएक्स के आइपीओ का मूल्य 135 डालर प्रति शेयर तय किया था। शुक्रवार को यहां 150 डालर पर कंपनी का शेयर सूचीबद्ध हुआ और थोड़ी ही देर में 164 डालर पर पहुंच गया। इस मूल्य पर कंपनी का मूल्यांकन 2.18 ट्रिलियन डालर होता है। इस तरह स्पेसएक्स अमेरिका की छठी मूल्यवान कंपनी बन गई है।

मस्क की राकेट और सेटेलाइट कंपनी स्पेसएक्स ने दुनिया का सबसे बड़ा आइपीओ लाकर 75 अरब डालर जुटाए हैं। आइपीओ मूल्य पर कंपनी का मूल्यांकन 1.77 ट्रिलियन डालर था। कंपनी ने आइपीओ के जरिये 55.50 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचे। स्पेसएक्स से पहले सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको दुनिया का सबसे बड़ा आइपीओ लेकर आई थी। उसने आइपीओ से 29 अरब डालर से ज्यादा जुटाए थे और इस तरह उसकी वैल्यूएशन 1.7 ट्रिलियन डालर हो गई थी। अमेरिकी प्रतिभूति बाजार में जमा किए गए दस्तावेज के अनुसार स्पेसएक्स का पहली तिमाही में राजस्व 15 प्रतिशत बढ़कर 4.69 अरब डालर हो गया, जो एक साल पहले 4.07 अरब डालर था। स्पेसएक्स के अलावा एआइ कंपनी एंथ्रोपिक और चैटजीपीटी बनाने वाली ओपेनएआइ ने भी आइपीओ लाने के लिए गोपनीय तरीके से दस्तावेज जमा किए हैं। इनमें से प्रत्येक कंपनी की वैल्यूएशन एक ट्रिलियन डालर है।

टेस्ला ने दिया है 20 हजार प्रतिशत का रिटर्न : मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला 2010 में सार्वजनिक होने के बाद से टेस्ला शेयरधारकों को 20 हजार प्रतिशत का रिटर्न दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की कमाई में 1.2 ट्रिलियन डालर से ज्यादा बढ़ी है।

135 डालर प्रति शेयर पर 75 अरब डालर जुटाए

2.18 ट्रिलियन डालर हुआ कंपनी का मूल्यांकन

नैस्डेक में शेयर सूचीबद्ध होते ही एलन मस्क बने ट्रिलियन डालर व्यक्ति

400 कर्मियों के अरबपति बनने की उम्मीद

सैन फ्रांसिस्को के एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफार्म हिलडाटकाम के एक विश्लेषण में अनुमान लगाया गया है कि 4,400 से ज्यादा मौजूदा और पुराने स्पेसएक्स कर्मचारी भी आइपीओ से करोड़पति बन सकते हैं। माना जा रहा है कि लगभग 400 कर्मचारी ऐसे होंगे, जिनके 10 करोड़ डालर या उससे ज्यादा कमाने की उम्मीद है।

ऐसे समझें एक ट्रिलियन डालर वैल्यूएशन को

- एमेजोन के जेफ बेजोस, ओरेकल के लैरी एलिसन और गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई बिन की संयुक्त संपत्ति एक ट्रिलियन डालर से थोड़ी ही ज्यादा है।
- दुनियाभर की 50 सबसे कीमती स्पोर्ट्स टीम की कुल कीमत 353 अरब डालर है और यह मस्क की कुल संपत्ति का लगभग एक तिहाई है।
- पिछले साल अमेरिका में बेची गईं सभी नई कारों की कुल कीमत एलन मस्क की नेटवर्थ से कम है।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के दो पूर्व अधिकारी गिरफ्तार

नई दिल्ली : ईडी ने शुक्रवार को रिलायंस अनिल अंबानी समूह के दो पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि सतीश सेठ और गौतम दोशी को मनी लांड्रिंग रोधी कानून के प्रविधानों के तहत मुंबई में गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि ईडी गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ला रही है, क्योंकि यह मामला राष्ट्रीय राजधानी में दर्ज है। ये दोनों पहले रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड में डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। (प्रेट्र)

हिमाचल में अब फ्यूल चार्ज ने बढ़ाया बिजली बिल

शिमला : हिमाचल में बिजली सब्सिडी सीमित होने के बाद अब उपभोक्ताओं पर फ्यूल चार्ज का अतिरिक्त बोझ पड़ने लगा है। बिजली बिलों में इस बार 50 से 200 रुपये तक फ्यूल चार्ज जोड़कर राशि वसूली जा रही है। प्रदेश में पहले ही बिजली पर प्रति यूनिट 10 पैसे मिल्क सेस, दो पैसे पर्यावरण उपकर और अन्य शुल्क लिए जा रहे हैं। इसके अलावा स्मार्ट मीटर लगाने की लागत भी उपभोक्ताओं से किस्तों में वसूली जा रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं पर भार लगातार बढ़ता जा रहा है। बिजली बोर्ड का तर्क है कि बिल में बढ़ोतरी मुख्य रूप से बिजली खपत बढ़ने के कारण हो रही है और शुल्क नियामकीय प्रविधानों के तहत वसूले जा रहे हैं। (जासं)

प्रसारण के लिए एक जैसे नियम का प्रस्ताव

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने टेलीविजन और रेडियो प्रसारण सेवाओं के लिए एक समान नियामक ढांचे का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत 'राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता वाले विषयों' पर कार्यक्रम प्रसारित करने की जिम्मेदारी को प्राइवेट रेडियो सेवाओं पर भी लागू होगा। इस मसौदे पर 27 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। शुक्रवार को सार्वजनिक किए गए मसौदे में कहा गया है कि टीवी चैनल को सुबह छह बजे से रात 11 बजे के बीच प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक इन विषयों से संबंधित कंटेंट प्रसारित करना होगा। वहीं, रेडियो स्टेशन को इसके लिए हर दिन एक घंटे का समय निर्धारित करना होगा। (प्रेट्र)

मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक की बहू को पति के महिला मित्र ने मारी गोली

रीवा के एक निजी अस्पताल में इलाजरत घायल योगिता सिंह। वीडियो ग्रैब

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना

- नागौद के पूर्व राजपरिवार की बहू योगिता सिंह गंभीर रूप से घायल
- आरोपित महिला गिरफ्तार, पति बाबा राजा पर नहीं हुई कोई कार्रवाई

मध्य प्रदेश में नागौद के पूर्व राजघराने से जुड़ी परसमनिया गढ़ी अचानक सुर्खियों में है। लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवाद के बीच फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग में पूर्व राजपरिवार की बहू योगिता सिंह गंभीर रूप से घायल हो गईं। योगिता सिंह की मां ने आरोप लगाया कि जब उनकी बेटी गढ़ी के अंदर जाने लगी तो उसे उसके पति रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा ने धक्का दिया। उसके बाद बाबा राजा की महिला मित्र सुनीता सिंह ने 22 बोर की लाइसेंसी बंदूक से नौ राउंड फायरिंग की। इस घटना में एक गोली उसकी बेटी योगिता के पेट में लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने केवल सुनीता सिंह को आरोपित बनाया है। बाबा राजा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

बता दें कि योगिता सिंह, पूर्व मंत्री व नागौद से वर्तमान भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह के भतीजे रूपेंद्र कुमार सिंह उर्फ बाबा राजा की पत्नी हैं। बताया गया है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसके चलते योगिता सिंह परसमनियां गढ़ी छोड़कर कुछ समय पहले से नागौद स्थित किले में रह रही थीं। इधर बाबा राजा सुनीता सिंह नामक एक महिला के साथ परसमनिया गढ़ी में रहने लगे। आपसी विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से योगिता सिंह अपने स्वजन के साथ गुरुवार को परसमनिया गढ़ी पहुंची थीं। बातचीत के दौरान विवाद अचानक बढ़ गया। पुलिस ने सुनीता सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

सरकार ने प्याज खरीद का मूल्य बढ़ाकर 16.50 रुपये प्रति किग्रा किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : किसानों की आय बढ़ाने की कोशिशों के तहत सरकार ने बफर स्टाक प्रोग्राम के तहत प्याज की खरीद कीमत शनिवार से बढ़ाकर 16.50 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी है। अभी यह कीमत 15.80 रुपये प्रति किलोग्राम है। महाराष्ट्र के किसान 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीद चाहते हैं, क्योंकि राज्य में इनपुट कीमतें ज्यादा है। देश में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। सरकार ने इस साल के लिए दो लाख टन खरीद का लक्ष्य रखा है और यह 2025-26 में खरीदे गए तीन लाख टन से कम है।

मौजूदा सीजन के लिए प्याज की खरीद 15 मई से शुरू हुई थी। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2025-26 में प्याज का उत्पादन 307.37 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 में यह 307.67 लाख टन था। इस सप्ताह की शुरुआत में महाराष्ट्र में किसानों ने 3,000 रुपये प्रति क्विंटल (30 रुपये प्रति किलोग्राम) के न्यूनतम खरीद मूल्य की मांग की थी।

42 साल बाद फैसला, तिर्वा एस्टेट की सरप्लस जमीन सरकार की

जागरण संवाददाता, कानपुर

- कन्नौज के तिर्वा एस्टेट राजा शारदा नारायण सिंह की 67.29 एकड़ जमीन सीलिंग के दायरे में आ गई थी
- लंबी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट पहुंचा मामला तो दोबारा सुनवाई का मिला आदेश, अब आया निर्णय

कन्नौज के तिर्वा एस्टेट के राजा शारदा नारायण सिंह के परिवार के नाम दर्ज 67.29 एकड़ जमीन को लेकर चली आ रही 42 वर्ष पुरानी कानूनी लड़ाई खत्म हो गई। करीब 150 करोड़ रुपये बाजार मूल्य की जमीन पर सरकार का दावा बरकरार रखा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर दोबारा हुई सुनवाई के बाद कानपुर मंडल की अपर आयुक्त (प्रशासन) रेनू सिंह की कोर्ट ने जमीन को सीलिंग में सरप्लस (अतिरिक्त) घोषित करते हुए सरकारी दस्तावेज में दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

मामला वर्ष 1984 का है। उस समय उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम (सीलिंग एक्ट) के तहत 12.50 एकड़ से अधिक कृषि भूमि रखने वालों की अतिरिक्त जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहीत की जा रही थी। इसी प्रक्रिया में तिर्वा क्षेत्र के अन्नपूर्णा मंदिर के निकट स्थित राजा शारदा नारायण सिंह परिवार की 67.29 एकड़ जमीन भी सीलिंग की जद में आ गई थी। राजा शारदा नारायण सिंह ने इसके खिलाफ कोर्ट गए। कई वर्षों तक विवाद विभिन्न कोर्ट में चलता रहा। वर्ष 1990 में तत्कालीन मंडलायुक्त की कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। दोबारा अपील हुई तो 1994 में मंडलायुक्त कोर्ट ने सीलिंग का दायरा बढ़ाकर 89 एकड़ जमीन सरप्लस घोषित कर दी। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। इसी बीच मुख्य वादी राजा शारदा नारायण की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके बेटे दिग्विजय नारायण सिंह आगे आए। कोर्ट ने 27 जून 2023 को 1994 में पारित आदेश को निरस्त कर दिया था।

उधार चुकाने को दुकानदार की स्वस्थ बेटियों को दिला दी दिव्यांग पेंशन

- पेंशन घोटाले की जांच में एक-एक कर खुल रहीं गड़बड़ियों की परतें
- बिचौलिये ने रिश्वत के 12 हजार रुपये बकाये में करा दिए समायोजित

संवाद सहयोगी, जागरण● साहिबगंज : झारखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में हुए फर्जीवाड़े की जांच के क्रम में घोटालेबाजों की तरह-तरह की कारस्तानियां सामने आ रही हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बिचौलियों ने योजनाओं में ऐसी अंधेरगर्दी मचाई कि कई मामले देख जांच अधिकारियों का भी सिर चकरा जा रहा है। कहीं जवान को वृद्धा पेंशन का लाभार्थी बना दिया गया तो कहीं सुहागन महिला को विधवा पेंशन का लाभ और कहीं स्वस्थ लोगों को दिव्यांग पेंशन का लाभ दिला दिया गया।

साहिबगंज के बोरियो में भी एक ऐसा मामला सामने आया है। यहां बोरियो निवासी गंगा साह की तीन नाबालिग पुत्रियों को दो माह से स्वामी विवेकानंद दिव्यांग पेंशन का लाभ मिल रहा है, जबकि लड़कियां दिव्यांग नहीं हैं। मामले की जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। गंगा साह राशन की दुकान चलाते हैं। शाहिद अंसारी उनके यहां से राशन ले जाता था। राशन के काफी पैसे बकाया हो जाने पर दुकानदार ने पैसे मांगे तो शाहिद ने उधार चुकाने के बजाय उसकी तीनों बेटियों के नाम पर दिव्यांग पेंशन की स्वीकृति दिला दी और प्रत्येक पेंशन के लिए चार हजार रुपये की दर से 12 हजार रुपये उसके बकाये में समायोजित करा दिए। शुक्रवार को गंगा साह को कार्यालय बुलाया गया। वहां बीडीओ नागेश्वर साह व थाना प्रभारी रोहित कुमार की मौजूदगी में गंगा साह से पूछताछ की गई।

अवैध विवाह तो विधवा का दर्जा नहीं, पेंशन की भी हकदार नहीं : हाई कोर्ट

दयानंद शर्मा, जागरण चंडीगढ़ : अगर कोई सरकारी कर्मी पहली पत्नी के जीवित रहते अवैध ढंग से दूसरी शादी करता है तो उसकी मौत के बाद दूसरी पत्नी को विधवा नहीं माना जा सकता। उसे मृत कर्मी की फैमिली पेंशन का भी अधिकार नहीं है। यह निर्णय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने मोहाली की प्रिया की अपील खारिज करते हुए सुनाया। पीठ ने कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत दूसरी शादी तभी मान्य हो सकती है, जब वह कानूनन वैध हो।

मेजर हरि सिंह की मृत्यु के बाद पहली पत्नी मोहिंदर कौर और दूसरी पत्नी प्रिया के बीच सेवानिवृत्ति लाभों व अन्य अधिकारों को लेकर विवाद शुरू हुआ था। मोहिंदर ने खुद को मेजर की वैध पत्नी बता सेवानिवृत्ति लाभों पर अधिकार मांगा था।

मुंबई से निकाह करने बिजनौर पहुंची नर्स को प्रेमी ने मारकर खेत में दबाया

जागरण संवाददाता, बिजनौर

35 वर्षीय नर्स 21 साल के युवक से निकाह करने मुंबई से बिजनौर के मंडावर आ गई। युवक के स्वजन निकाह के खिलाफ थे, लेकिन महिला निकाह की जिद पर अड़ी थी। युवक महिला को खादर क्षेत्र में ले गया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। शव को खेत में दबा दिया। महिला का सामान गंगा में फेंक दिया और सिम निकालकर मोबाइल अपने पास रख लिया। इसके बाद युवक वापस मुंबई चला गया। महिला की बहनों ने मुंबई में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया तो पुलिस ने संदेह पर युवक को हिरासत में लिया।

शुक्रवार को मुंबई पुलिस महिला की एक बहन शबाना और आरोपित युवक के साथ मंडावर में घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि फैजल उर्फ फैसल वहां चिकन शाप पर काम करता है। उसका शादीशुदा सना से प्रेम प्रसंग था। सना का नौ वर्ष का बेटा भी है। प्रेम प्रसंग के चलते सना ने अपने पति को तलाक दे दिया, जिसके बाद फैजल उसके घर ही रहने लगा था। कुछ दिन बाद फैजल ने दूरी बनानी शुरू कर दी। सना 28 मई को संदिग्ध हालात में लापता हो गई। स्वजन ने शिकायत दर्ज कराई तो उसके मोबाइल की लोकेशन बिजनौर में मिली। पुलिस ने फैजल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि सना 29 मई को उसे बिना बताए निकाह करने के लिए बिजनौर आ गई थी। उसके स्वजन निकाह के खिलाफ थे। वह उसी दिन सना को खादर क्षेत्र में ले गया और उसने वहां सना की गला दबाकर हत्या कर दी। वह पांच जून को मुंबई चला गया। फैजल ने सना का शव एक खेत में दबाया था। सना का मोबाइल पुलिस फैजल से बरामद कर चुकी, लेकिन सिम का पता नहीं चला। शाम सात बजे मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच गया है, शव की निकालने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

घटना के बारे में जानकारी देतीं मृतक सना की बहन शबाना। जागरण

6 | संपादकीय
जनसत्ता | 13 जून, 2026

कल्पमेधा

कभी-कभी आप दीवारें दूसरों को दूर रखने के लिए खड़ी नहीं करते, बल्कि इसलिए खड़ी करते हैं कि आप यह देखना चाहते हैं कि इन्हें कौन तोड़ने की कोशिश करता है।
– सुकरात

कठघरे में साख

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन कोई न कोई ऐसा बयान देते हैं, जिसके बाद कई स्तर पर उथल-पुथल हो जाती है। हालांकि आमतौर पर कुछ ही समय के बाद वे या तो अपनी बात से उलट कुछ नया कह देते हैं या फिर उसे वापस ले लेते हैं। विडंबना यह है कि वैश्विक कद के मद्देनजर ट्रंप के बयानों को बिल्कुल बेमानी मान लेना भी संभव नहीं होता है और उनके विचारों को स्थिर मानना भी मुश्किल होता है। दरअसल, कई बार बेहद हड़बड़ी में की गई उनकी टिप्पणियों की वजह से ऐसी स्थितियां पैदा हुईं, जिनका वैश्विक स्तर पर व्यापक असर हुआ, लेकिन वे खुद अपनी बातों को लेकर गंभीर नहीं दिखे। मसलन, करीब दो महीने पहले जब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत नाकाम हुई थी, तब ट्रंप ने युद्ध की आग ज्यादा भड़कने को लेकर लगातार कई धमकियां दीं। इसके बाद शेयर बाजार में 4500 से ज्यादा अंकों की तेज गिरावट दर्ज की गई थी। मगर जब भी वे हमलों के धीमा पड़ने या बातचीत को लेकर सकारात्मक बयान देते हैं, तो उसके बाद शेयर बाजार में भारी उछाल देखा जाता है।

इसके अलावा, पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों की आपूर्ति श्रृंखला बाधित है और वे भी ट्रंप के रुख को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। ट्रंप जब कहते हैं कि युद्ध खत्म करने या विराम को लेकर सहमति बन सकती है, तो उससे शेयर बाजार में राहत के साथ-साथ प्रभावित देशों के भीतर शांति और स्थिरता की उम्मीद पैदा हो जाती है। मगर इससे बेखबर ट्रंप अगले ही दिन इसके उलट या भ्रम पैदा करने वाला कोई और बयान दे देते हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी की कि बहुत जल्द ईरान के तेल-गैस उद्योगों और खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लिया जाएगा और इसके लिए अमेरिका आज रात ईरान पर व्यापक पैमाने पर हमला करेगा। जाहिर है, इसके बाद युद्ध के और जटिल शक्ल अख्तियार करने को लेकर व्यापक आशंका पैदा हुई। मगर इसके कुछ ही घंटे बाद उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है और इस वजह से उस पर बमबारी रद्द कर दी गई है। यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है, बल्कि जब से ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने साझा हमला किया, तब से वे कई बार इसी तरह के बयान दे चुके हैं और उससे पलट चुके हैं।

यह समझना मुश्किल है कि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी जिस युद्ध की वजह से न केवल इन देशों के नागरिक, बल्कि कई देश बुरी तरह प्रभावित हैं, व्यापक ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं, उसके बारे में ट्रंप इतने हल्के अंदाज में कैसे कोई भी बयान दे देते है। उनके अगंभीर रवैये की वजह से कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं, जिनका कुछ देशों की आर्थिक स्थिति पर बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अफसोस की बात यह है कि जल्दबाजी भरे बयानों और उसमें स्थिरता न रहने के कारण उनकी विश्वसनीयता में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वे व्यापार से लेकर कूटनीति तक के मामले में भारत को अपना सहयोगी बताने में पीछे नहीं रहते, लेकिन भारतीय नाविकों वाले जहाजों को निशाना बनाने में अमेरिका को कोई हिचक नहीं हुई। हालांकि भारत की तीखी आपत्ति के बाद ट्रंप ने आरोप का रुख ईरान की ओर मोड़ने की कोशिश की। सवाल है कि क्या युद्ध को खत्म करने और वैश्विक शांति के लिए ट्रंप किसी स्पष्ट तथा स्थिर नीति के तहत अपने कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, जिससे उनकी विश्वसनीयता भी मजबूत हो!

बेखौफ अपराधी

हरियाणा के हांसी में एक जिम संचालक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर देने की घटना ने एक बार फिर इस बात को उजागर किया है कि अपराधियों को कानून का कोई खौफ नहीं है। जब अपराधी खुलेआम हथियार लेकर घूमते हों और मौका पाकर इस तरह की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाएं, तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इससे न केवल आमजन में असुरक्षा की भावना बढ़ती है, बल्कि सरकार के सुरक्षा एवं जांच तंत्र पर उनका भरोसा भी डगमगाने लगता है। सवाल है कि आखिर अपराधियों के भीतर कानून का भय क्यों खत्म हो गया है? इसे सुरक्षा एजंसियों की लापरवाही और नाकामी नहीं, तो और क्या कहा जाएगा कि हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी आसानी से फरार हो जाते हैं? सरकार की ओर से अक्सर यह दावा किया जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए समूची प्रणाली को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। इसके बावजूद अगर अपराध कम नहीं हो रहा, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

गौरतलब है कि हांसी में जिम संचालक की गुरुवार सुबह उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वह लोगों के एक समूह को खुले में व्यायाम करा रहे थे। मोटरसाइकिल पर आए हमलावरों ने दस गोलियां चलाईं। यानी हमलावर यह सुनिश्चित करना चाहते थे, जिम संचालक किसी भी हाल में जिंदा न बचे। इस वारदात की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, लेकिन हमलावर फरार होने में कामयाब रहे। इस घटना के कुछ घंटों बाद दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने एक जिम पर गोलीबारी की, जिसकी जिम्मेदारी लारेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े एक समूह ने ली है। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध है। फिलहाल पुलिस इस बारे में जांच कर रही है। मगर शासन-प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि सिर्फ कानून बना देने से सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त नहीं हो जाती है, जब तक सुरक्षा एवं जांच तंत्र में हर स्तर पर सतर्कता, संवदेनशीलता और जवाबदेही तय नहीं जाएगी, तब तक कानून व्यवस्था में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती।

पहाड़ के लिए जोखिम बनते दावानल

गर्मी का मौसम शुरू होते ही पहाड़ी वनों में आग लगने की घटनाएं प्रतिवर्ष सुर्खियां बनने लगती हैं, लेकिन किसी भी राज्य ने आग रोकने का स्थायी प्रबंध करने की जरूरत आज तक नहीं समझी है।

प्रमोद भार्गव

उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के जंगलों में लगी आग पर वायुसेना ने काबू न पाया होता, तो यह बड़े संकट का सबब बन गई होती। हिमाचल के सोलन जिले के कसौली क्षेत्र में लगी आग सैन्य ठिकानों और आवासीय इलाकों तक पहुंच गई थी। वन अमला आग बुझाने का कोई सार्थक उपाय कर नहीं पाया, तब भारतीय वायुसेना को राहत अभियान में उतरना पड़ा। उत्तरकाशी में जंगल की आग गंगोत्री राजमार्ग पर पहुंच गई थी, जहां गेस्ट हाउस में ठहरे 70 यात्रियों को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर और रामवन जिलों में कई दिनों तक पहाड़ धधकते रहे।

गर्मी का मौसम शुरू होते ही पहाड़ी वनों में आग लगने की घटनाएं प्रतिवर्ष सुर्खियां बनने लगती हैं, लेकिन किसी भी राज्य ने आग रोकने का स्थायी प्रबंध करने की जरूरत आज तक नहीं समझी है। इन घटनाओं से हजारों हेक्टेयर जंगल सुलग कर राख में बदल जाते हैं। हिमाचल के अकेले कसौली वन क्षेत्र में दस हेक्टेयर जंगल राख हो गया। उत्तराखंड के वनों में आग लगने की 388 से ज्यादा घटनाएं दर्ज होने के साथ तीन लोगों की मृत्यु हो गई। कोई 340 हेक्टेयर वन भूमि धधकती रही। चमोली के आदिबद्री और कालसी में ग्रामों तक आग पहुंच गई। पौड़ी में आग लगाने के आरोप में दो लोगों को हिरासत में लिया गया। जम्मू-कश्मीर के रामवन, चंदरकोट और उधमपुर में भी कई वनक्षेत्रों के धधकने की खबर आई। इन पहाड़ी क्षेत्रों में आग पर काबू पाना इसलिए मुश्किल होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में राहत आसानी से पहुंच नहीं पाती। यहां आग बुझाने का काम वन विभाग और स्थानीय लोगों की मदद से ही संभव हो पाता है।

चीड़ के जंगल और लैंटाना की झाड़ियां इस आग को फैलाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। दरअसल, चीड़ के पत्तों में एक विशेष किस्म का ज्वनलशील पदार्थ होता है। ये पत्तियां पतझड़ के मौसम में आग में घी का काम करती हैं। गर्मियों में पत्तियां जब सूख जाती हैं, तो इनकी ज्वलनशीलता और बढ़ जाती है। इसी तरह, लैंटाना जैसी विषाक्त झाड़ियां आग को भड़काने का काम करती हैं। करीब 40 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में ये झाड़ियां फैली हुई हैं। इन पत्तियों में भयावह आग लग जाती है। इससे वर्षा कम होती है। तापमान बढ़ जाता है। इन वजहों से यहां पतझड़ की मात्रा बढ़ी, उसी अनुपात में मिट्टी की नमी घटती चली गई। ये ऐसे प्राकृतिक संकेत थे, जिन्हें वन अधिकारियों को समझने की जरूरत थी।

वैसे चीड़ और लैंटाना भारतीय मूल के पेड़ नहीं हैं। अंग्रेजों ने जब पहाड़ों पर आशियाने बनाए, तब उन्हें बर्फ से आच्छादित पहाड़ियां अच्छी नहीं लगीं। वे ब्रिटेन के बर्फीले क्षेत्र में उगने वाले चीड़ की प्रजाति के पौधे को भारत ले आए और बर्फीली पहाड़ियों के बीच खाली पड़ी भूमि में रोप दिए। इन पेड़ों को जंगली जीव और मवेशी नहीं खाते हैं। इसलिए अनुकूल प्राकृतिक वातावरण पाकर ये तेजी से फलने-फूलने लगे। इसी

तरह, लैंटाना को भारत की दलदली और बंजर भूमि में पौधारोपण के लिए लाया गया था। यह विषैला पेड़ भारत के किसी काम तो नहीं आया, लेकिन इसने लाखों हेक्टेयर भूमि में फैल कर उपजाऊ भूमि जरूर लील ली। ये दोनों प्रजातियां ऐसी हैं, जो अपनी छाया में किसी अन्य पेड़-पौधे

> **जब पहाड़ियां तपिश के चलते शुष्क हो जाती हैं और चट्टानें भी खिसकने लगती हैं, तो प्राय: घर्षण से जंगल में आग लग जाती है। तेज हवा चलने पर जब बांस परस्पर टकराते हैं, तो इस घर्षण से भी आग लग सकती है। बिजली गिरना भी जंगल में आग लगने के कारणों में शामिल है। ये कारण प्राकृतिक हैं और इन पर विराम लगाना असंभव है। मगर मानव-जनित जिन कारणों से आग लगती है, वे खतरनाक हैं। इसमें वन-संपदा के दोहन से अकूत मुनाफा कमाने की होड़ भी शामिल है। भू-माफिया, लकड़ी माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों का गठजोड़ इस कारोबार के फलने-फूलने में सहायक बना हुआ है। राज्य सरकारों ने विकास का पैमाना भी आर्थिक उपलब्धि को माना है, इसलिए सरकारें पर्यावरणीय क्षति को नजरअंदाज करती हैं।**

को पनपने नहीं देती हैं। चीड़ की एक खासियत यह भी है कि जब इसमें आग लगती है, तो इसकी पत्तियां ही नष्ट होती हैं। तना और डालियों को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। पानी बरसने पर ये फिर से हरे-भरे जाते हैं। लगभग यही स्थिति लैंटाना की है।

चीड़ और लैंटाना को उत्तराखंड से निर्मूल करने के लिए कई बार सामाजिक संगठन आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सार्थक नतीजे नहीं निकले। अलबत्ता, इनके पत्तों से लगी आग से बचने के लिए चमोली जिले के एक गांव के लोगों ने जरूर चीड़ के पेड़ की जगह हिमालयी मूल के पेड़ लगाने शुरू कर दिए। जब ये पेड़ बड़े हो गए, तो इस गांव में 20 साल से आग नहीं लगी। इसके बाद कई ग्रामवासियों ने इस देसी तरीके को अपना लिया। इन पेड़ों में पीपल, देवदार और अखरोट के वृक्ष लगाए गए हैं। यदि वन-अमला ग्रामीणों के साथ मिल कर ऐसे उपाय करता तो आज उत्तराखंड के जंगलों की यह दुर्दशा नहीं होती।

जंगल में आग लगने के कई कारण होते हैं। जब पहाड़ियां तपिश के चलते शुष्क हो जाती हैं और चट्टानें भी खिसकने लगती हैं, तो प्रायः घर्षण से आग लग जाती है। तेज हवाएं चलने पर जब बांस परस्पर टकराते हैं, तो इससे पैदा होने वाले घर्षण से भी आग लग जाती है। बिजली गिरना भी आग लगने के कारणों में शामिल है। ये कारण प्राकृतिक हैं और इन पर विराम लगाना असंभव है। मगर मानव-जनित जिन कारणों से आग लगती है, वे खतरनाक हैं। इसमें वन-संपदा के दोहन से अकूत मुनाफा कमाने की होड़ भी शामिल है। भू-माफिया, लकड़ी माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों का गठजोड़ कारोबार को फलने-फूलने में सहायक बना हुआ है। राज्य सरकारों ने विकास का पैमाना भी आर्थिक उपलब्धि को माना है, इसलिए सरकारें पर्यावरणीय क्षति को नजरअंदाज करती हैं।

आग लगने की अन्य वजहों में बीड़ी-सिगरेट भी हैं, तो कभी शरारती तत्त्व भी आग लगा देते हैं। कभी ग्रामीण अपने पशुओं के चारे के लिए सूखी और कड़ी पड़ चुकी घास में आग लगाते हैं। ऐसा करने से धरती में जहां-जहां नमी होती है, वहां-वहां घास की नई कोंपलें फूटने लगती हैं। जो मवेशियों के लिए पौष्टिक आहार का काम करती हैं। पर्यटन वाहनों के साइलेंसर से निकली चिंगारी भी आग की वजह बनती है। आग से बचने के कारगर उपायों में पतझड़ के दिनों में टूट कर गिर जाने वाले पत्ते आग लगने की वजह बनते हैं। केंद्रीय हिमालय में 2.1 से लेकर 3.8 टन प्रति हेक्टेयर पतझड़ होता है। इसमें 82 फीसद सूखी पत्तियां और बाकी टहनियां होती हैं। जंगलों पर वन विभाग का अधिकार होने से पहले अपने अनुभव से ग्रामीण इस पतझड़ से जैविक खाद बना लिया करते थे। इन पत्तों को मवेशियों के बिछौने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। किंतु वन कानूनों के वजूद में आने से वनोपज पर स्थानीय लोगों का अधिकार खत्म हो गया।

इस सब के बावजूद जंगल में लगी आग को बुझाने के तरीके परंपरागत हैं। वन अमला हरी टहनियों की झाड़ू बनाता है और उसकी फटकार से आग बुझाने का काम करता है। इस तरीके से दावानल को नहीं बुझाया जा सकता है। वनों में आग लगने का एक बड़ा कारण आरक्षित वनों, अभयारण्यों और उद्यानों से ग्रामवासियों का विस्थापन किया जाना भी है। ये जब तक जंगल के वासी रहे, तब आग बहुत कम लगती थी, क्योंकि ये लोग आग लगते ही उसे बुझा दिया करते थे।

भय के आयाम

अखिलेश श्रीवास्तव चमन

हमारे चतुर्दिक भय का एक घना आवरण निर्मित है। ऐसा आवरण जो हमारे जीवन की अनिवार्यता बन चुकी है। हम 'होमोसेपियंस' यानी मानव प्रजाति के प्राणधारी एक भ्रूण के रूप में अपनी मां के गर्भ में आने से लेकर इस दुनिया को अलविदा कहने तक की यात्रा में हर क्षण भय के साए में ही जीते हैं। जन्म के बाद मनुष्य आजीवन भय में ही जीता है। बचपन में माता-पिता बच्चे पर निरंतर 'यह करो... वह करो... यह मत करो... वह मत करो' के चाबुक चलाते रहते हैं। निर्देशों की रंचमात्र भी अवहेलना करने पर वे बच्चे को डांट-फटकार तिरस्कार और पिटायी तक की सजा दिया करते हैं। परिणामस्वरूप बच्चा अपने बचपन को स्वच्छंद होकर नहीं जी पाता है। बहुत सारे काम वह अपनी अनिच्छा के बावजूद सिर्फ मां-पिता की नाराजगी और सजा के भय के कारण करता है। यहां तक कि बहुत सारे कार्य जो उसे स्वाभावतः करना चाहिए उन्हें भी वह भयवश करने का आदी हो जाता है।

भय में जीने की बचपन में पनपी यह प्रवृत्ति आदमी को जीवन पर्यंत अपने पाश में ग्रसित किए रहती है। बच्चा विद्यालय जाता है, तो पढ़ाई वह आमतौर पर शिक्षक के भय के कारण करता है। उसके भविष्य की दिशा माता-पिता निर्धारित करते हैं और बच्चा उसे स्वीकार कर लेता है। हो सकता है कि बच्चा चित्रकार बनना चाहता हो और माता-पिता उसे डाक्टर बनाने पर तुले हों। हो सकता है कि बच्चे की रुचि संगीत में हो, लेकिन उसके मां-पिता उसे प्रशासनिक अधिकारी बनाने की महत्त्वाकांक्षा पाले बैठे हों। चूंकि बच्चा अपनी आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से अपने माता-पिता पर निर्भर होता है, इसलिए उस निर्भरता के भय के कारण वह माता-पिता द्वारा निर्धारित दिशा में चल पड़ता है।

आदमी को दया, करुणा, ममता और सहिष्णुता आदि मानवीय गुणों से संपृक्त करने में भी भय की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चा यदि खेल-खेल में या गलती से भी एक चींटी या किसी कीड़ा को मार दे, तो अभिवावक उसे तुरंत 'पाप लगने' का भय दिखाता है। झूठ बोलेगे, तो पाप लग जाएगा... चोरी करोगे, तो पाप लग जाएगा... बड़ों की बात नहीं मानोगे, तो पाप लग जाएगा। यह पाप लगने का भय आदमी के बाल्यावस्था में इतना घनीभूत रहता है कि उसके अचेतन में सदा-सर्वदा के लिए अंकित हो जाता है। फिर आदमी आजीवन पाप के भय से संचालित होता रहता है। दुनिया का चाहे कोई भी धर्म हो, सभी का अस्तित्व भय के आधार पर ही टिका है। हर धर्म के फैलाव का कारक उसे न मानने से होने वाली हानि या सजा का भय ही है। स्वर्ग, नरक, मोक्ष, मुक्ति आदि की धारणाएं भय के ही औजार हैं। आदमी अगर किसी विषम स्थिति में फंस जाता है या उसे किसी अनिष्ट की आशंका होती है, तो वह तत्काल अपने आराध्य की शरण में भागता है। आराध्य के पास उसके जाने का कारण आराध्य के प्रति भक्ति या प्रेम कितना होता है, पता नहीं, लेकिन उस अनिष्ट की आशंका जरूर होती है, जिससे वह बचना चाहता है। अनिष्ट या मरणोपरांत नर्क का भय न हो, तो उपासना घरों में ताले पड़ जाएं। ऐसे भी लोग होते हैं, जो आदमी के अचेतन में बैठे भय को उद्वेलित करके अपना उल्लू सीधा करते हैं।

भय का एक सार्थक पक्ष यह है कि अगर भय न रहे, तो आदमी निष्क्रिय हो जाए। यहां तक कि जो कार्य उससे स्वाभाविक प्रक्रिया में अपेक्षित है, उसके लिए भी वह भय का कारक ढूंढ़ने लगता है। अधिकतर कर्मचारी नौकरी में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अपना कर्तव्य मान कर नहीं, बल्कि अपने उच्चाधिकारियों के भय या नौकरी पर आंच आने के भय के कारण करते हैं। इसी प्रकार, आदमी तमाम सामाजिक रिवाजों तथा मान्यताओं को न चाहते हुए भी सिर्फ लोकलाज और अपयश के भय के कारण ढोता है। यहां तक कि आदमी अपने पारिवारिक जीवन में भी बहुत सारे कार्य और समझौते भयवश यानी गृह कलह को बचाने के लिए करता है। कमजोर लोग बाहुबलियों से मिले अपमान और ज्यादती को उनकी ताकत के भय के कारण चुपचाप सहन कर लेते हैं। पुलिस विभाग का तो सारा दारोमदार ही उनके डंडे के भय की बदौलत है।

आदमी की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में भी भय की बहुत बड़ी भूमिका है। देखने में आता है कि सामान्य नियमों का पालन भी आदमी एक जागरूक नागरिक के तौर पर कम, बल्कि कानून के डर के कारण ज्यादा करता है। उदाहरण के लिए मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनने, कार में सीट बेल्ट बांधने और वाहन को निर्धारित गति से चलाने के नियम आदमी के फायदे के लिए उसकी सुरक्षा को दृष्टिगत रख कर बनाए गए हैं। लेकिन अगर ज्यादातर लोग इन नियमों का पालन अपनी सुरक्षा की सोच के कारण नहीं, बल्कि यातायात पुलिस द्वारा पकड़े जाने और चालान के भय के कारण किया करते हैं। अगर टीटीई द्वारा पकड़े जाने का भय न हो, तो बहुत सारे लोग ट्रेन में बगैर टिकट यात्रा करने लगें। अगर न्यायालय और जेल का भय न हो, तो समाज में अराजकता फैल जाए।

सच यह है कि भय ही वह हथियार है, जिसकी बदौलत शासक वर्ग शासन करता है। भय की स्थापना के लिए शासक वर्ग विविध प्रकार के कानून बनाता है और उन कानूनों के उल्लंघन के लिए सजाएं निर्धारित करता है। अपने बनाए कानूनों के अनुपालन के लिए वह नई-नई व्यवस्थाएं और नए-नए उपकरण निर्मित करता है। सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल निगरानी और नार्को टेस्ट आदि भय के नवीनतम उपादान हैं। तात्पर्य यह कि समाज को सजाने-संवारने और सुरक्षित बनाए रखने के लिए भय को अनिवार्य मान लिया गया है। अगर भय न हो तो समाज में अनैतिक और आपराधिक मानसिकता वाले लोगों पर कोई अंकुश ही नहीं होगा।

दुनिया मेरे आगे

> **संभव है कि बच्चा चित्रकार बनना चाहता हो और माता-पिता उसे डाक्टर बनाने पर तुले हों। बच्चे की रुचि संगीत में हो, लेकिन उसके माता-पिता उसे प्रशासनिक अधिकारी बनाने की महत्त्वाकांक्षा पाले बैठे हों। चूंकि बच्चा अपने माता-पिता पर निर्भर होता है, इसलिए वह ना-नुकुर किए बगैर चुपचाप उनके द्वारा निर्धारित दिशा में चल पड़ता है।**

दोहरे पैमाने

पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के नागरिक लंबे समय से सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग करते आ रहे हैं। मगर वहां लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के बजाय सेना का दमन चक्र चल रहा है। पाकिस्तानी सेना द्वारा वर्षो से लोगों को जबरन जेलों में बंद कर प्रताड़ित किया जाता है। विरोध करने पर हत्या कर दी जाती है। अभी हाल ही में लोग मुजफ्फराबाद में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हुकूमत से मांग कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना को हर बार की तरह इस बार भी मांग नागवार गुजरी और सेना प्रमुख मुनीर के इशारे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी लोगों पर अंधाधुंध गोलाबारी की गई। दूसरी ओर, दुनिया में मानवता की दुहाई देने वाले संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठनों को यह बर्बरता क्यों नहीं नजर आती है? मुजफ्फराबाद में कई निर्दोष लोगों की मौत की निंदा की जानी चाहिए। पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की आवाज क्यों नहीं उठाई जाती है? मानवाधिकार के प्रश्न पर बड़े देश दोहरे मापदंड क्यों अपनाते हैं?

– अरविंद रावल, झाबुआ

चेतना के बिना

आज शिक्षा प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य केवल कागज के बेजान टुकड़े बटोरना भर रह गया है, जबकि मनुष्य का आंतरिक विकास ठप है। विश्वविद्यालय अब ज्ञान के केंद्र नहीं, बल्कि डिग्रियों के कारखाने बन चुके हैं। ये संस्थान समाज में शिक्षित तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन इंसान के भीतर की वास्तविक पात्रता (योग्यता और विवेक) को सुखा रहे हैं। यह बौद्धिक चेतना का भयावह अकाल है। प्रश्नपत्र लीक जैसे गंभीर मामले इसी खोखली व्यवस्था का जीवंत प्रमाण हैं, जहां ज्ञान की कोई कीमत नहीं बची, बल्कि शिक्षा अब महज जुगाड़ और नकल की खुली मंडी बन चुकी है। नैतिक पतन इस समय इतना चरम पर है कि देश में रीढ़विहीन और वैचारिक अंधेरे में रेंगने वाली प्रवृत्तियां हावी हो रही हैं। ये व्यवस्था के सड़े हुए कोनों में स्वार्थ के लिए फलती-फूलती हैं। जब तक शिक्षा चरित्र निर्माण और चेतना को जागृत नहीं करती, तब तक ये डिग्रियां केवल दीवारों की शोभा बढ़ाने वाले भ्रम हैं।

– हिमांशु सिंह, लखनऊ

भरोसे पर घात

लगभग प्रतिदिन किसी न किसी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी अथवा पद के दुरुपयोग के मामले सामने आते रहते हैं। यह स्थिति प्रशासनिक व्यवस्था और आम जनता के विश्वास, दोनों के लिए चिंताजनक है। भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए केवल दंडात्मक कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अधिकारियों में सेवा के प्रारंभ से ही उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना आवश्यक है। नियुक्ति के समय अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों के कानूनी परिणामों, कारावास की परिस्थितियों तथा दंड के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए। यदि उनके परिवारजन भी इन परिणामों से अवगत होंगे, तो वे भी सदैव ईमानदार और कानूनसम्मत कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। कुछ देशों में सरकारी सेवकों को नियुक्ति से पूर्व नैतिकता, अनुशासन और कानूनी दायित्वों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे देश में भी ऐसी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

– अरविंद जैन 'बीमा', उज्जैन

कीटों का महत्त्व

प्रकृति के संतुलन में कीटों की अहम भूमिका होती है। मधुमक्खियां, तितलियां और अन्य कीट परागण के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता करते हैं। कई कीट जैविक अपशिष्टों के विघटन में योगदान देकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं तथा खाद्य श्रृंखला का भी महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसलिए सभी कीट हानिकारक नहीं होते। अनेक कीट मानव और प्रकृति के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। मगर कुछ कीट मानव स्वास्थ्य, कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती भी बनते हैं। मच्छरों से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं, जबकि दीमक, टिड्डियां फसलों तथा संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में हर वर्ष कीटजनित रोगों और फसल हानि के कारण भारी आर्थिक क्षति होती है। इसलिए जरूरत कीटों के विनाश की नहीं, बल्कि उनके वैज्ञानिक और संतुलित नियंत्रण की है।

– ओपी चौधरी, रतलाम

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

चिंतन

गरीब की थाली तक खाड़ी युद्ध का दबाव

अमेरिका-ईरान के बीच जारी जंग का असर अब गरीब की थाली पर भी दिखने लगा है। हाल के महीनों में खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने गरीब और मध्यम वर्ग की चिंता को और बढ़ा दिया है। मई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.93 प्रतिशत और खाद्य महंगाई 4.78 प्रतिशत तक पहुंच जाना इस बात का संकेत है कि रसोई का बजट लगातार दबाव में है। टमाटर, अदरक और अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेज उछाल ने परिवारों की मासिक योजनाओं को प्रभावित किया है। वहीं, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और खाड़ी क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति इस समस्या को लगातार गंभीर बनाती जा रही है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर खाड़ी देशों से आयातित कच्चे तेल पर निर्भर है। जब भी इस क्षेत्र में युद्ध या राजनीतिक तनाव बढ़ता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर हो जाती हैं। तेल महंगा होने का असर केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवहन, भंडारण और उत्पादन लागत बढ़ने के कारण इसका प्रभाव खाद्य पदार्थों की कीमतों पर भी पड़ता है। यही कारण है कि खाड़ी क्षेत्र में चल रहे संघर्ष का दबाव अंततः गरीब की थाली तक पहुंच रहा है। महंगाई का सबसे अधिक असर उन परिवारों पर पड़ता है, जिनकी आय सीमित है। गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लिए भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों के बीच संतुलन बनाना कठिन हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई दर शहरी क्षेत्रों से अधिक होना इस बात का प्रमाण है कि किसान और ग्रामीण परिवार भी इस संकट से अछूते नहीं हैं। खाद्य महंगाई के पीछे केवल अंतरराष्ट्रीय कारण ही नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक गर्मी, बेमौसम बारिश और आपूर्ति शृंखला में आने वाली बाधाएं भी कीमतों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कई फसलों के उत्पादन में कमी और समय पर बाजार तक आपूर्ति न हो पाने से मांग और उपलब्धता के बीच अंतर बढ़ रहा है। इसका सीधा परिणाम उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकाने के रूप में भुगतना पड़ रहा है। रोजमर्रा की जरूरत वाली सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों की महंगाई आम उपभोक्ता के लिए बड़ी चिंता बनी हुई है। यही वजह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी आगामी वित्त वर्ष के लिए महंगाई के अनुमान को बढ़ाया है। यह संकेत है कि आने वाले समय में कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। दूसरी ओर, रिजर्व बैंक को भी महंगाई नियंत्रण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। केवल ब्याज दरों में बदलाव से खाद्य महंगाई पर पूरी तरह नियंत्रण संभव नहीं है, क्योंकि इसके पीछे आपूर्ति संबंधी कारण अधिक प्रभावी हैं। इसलिए केंद्र और राज्यों को मिलकर कृषि, भंडारण और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। कुल मिलाकर यह समझना होगा कि महंगाई केवल आर्थिक आंकड़ों का विषय नहीं है, बल्कि यह करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा सवाल है। खाड़ी क्षेत्र का युद्ध, वैश्विक तनाव, जलवायु परिवर्तन और घरेलू आपूर्ति संबंधी चुनौतियां मिलकर आम आदमी की थाली को प्रभावित कर रही हैं। यदि समय रहते प्रभावी नीतिगत कदम नहीं उठाए गए, तो इसका सबसे बड़ा बोझ उन लोगों पर पड़ेगा, जो पहले से ही सीमित संसाधनों के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए सरकार, रिजर्व बैंक और समाज के सभी हितधारकों को मिलकर ऐसा समाधान तलाशना होगा, जो आर्थिक स्थिरता के साथ-साथ गरीब की थाली की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सके।

पहाड़ों को भी सांस की जरूरत है

विचार
डॉ. संजय शुक्ला

पहाड़ मनुष्य के लिए हमेशा से आस्था और आकर्षण का केंद्र रहे हैं। विभिन्न धर्मों के तीर्थस्थल इन पहाड़ों पर हैं वहीं दूसरी ओर पहाड़ों के तराई की सुरम्यता सैलानियों को लुभाती है जिसके चलते हर साल इन इलाकों में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन दिनों हिमाचल से लेकर उत्तराखंड की पहाड़ों में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भीड़ अटी पड़ी है। उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड तोड़ भीड़ के चलते सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उत्तराखंड सरकार के सूत्रों के मुताबिक कपाट खुलने के बाद अब तक चारधाम यात्रा के लिए 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं जो राज्य बनने के बाद मई महीने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के अनुसार बीते साल 2025 में 6 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री और पर्यटक राज्य के पहाड़ों पर आए जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड है। अलबत्ता इस भारी भीड़ के चलते जोशीमठ से बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग पर सोनप्रयाग में 20-25 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो रहा है। इस जाम में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं घंटों भूखे - प्यासे फंस रहे बावजूद लोगों में उत्साह है। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के पैदल रास्तों में भारी संख्या में लोगों की भारी भीड़ है।

गर्मियों के दौरान पर्यटकों के सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कुफरी, कसौली और डलहौजी जैसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की बात करें तो यहां टूरिस्टों का सैलाब उमड़ पड़ा है फलस्वरूप सभी प्रमुख मार्गों पर कई किलोमीटर का ट्रैफिक जाम लग रहा है।पर्यटन विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार इन दिनों प्रतिदिन लगभग 25-30 हजार पर्यटक हिमाचल के पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं वीकेंड में यह आंकड़ा बढ़ जाता है। मीडिया से जुड़े खबरों के मुताबिक बीते एक महीने के दौरान अकेले शिमला क्षेत्र में 8 लाख और मनाली में 70 हजार से ज्यादा पर्यटक वाहनों की एंट्री हुई है। आलम यह है कि इन पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों पर गाड़ियां दौड़ नहीं बल्कि रेंग रही है। चिंतनीय है कि पहाड़ों पर बढ़ रहे मानवी भीड़, बसाहट और वाहनों के बोझ के चलते पहाड़ हांफने लगे हैं। पहाड़ों की सकरी और घुमावदार सड़कों पर हजारों वाहनों के लंबे जाम की वजह से इन इलाकों में चौबीसों घंटे ध्वनि और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इन प्रदूषणों की वजह से जहां पर्यावरणीय खतरा बढ़ रहा है वहीं पहाड़ों के परिस्थितिकी तंत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

विचारणीय है कि पहाड़ों पर बढ़ती भीड़ केवल पर्यावरण को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा है बल्कि यह धार्मिक परंपराओं और संस्कृति पर भी विपरीत असर डाल रहा है। गौरतलब है कि पहले लोग चारधाम यात्रा में आध्यात्मिक भाव लेकर जाते थे लेकिन अब एक बड़ा तबका इन स्थानों में महज सैर-सपाटे के लिए जा रहे हैं। बीते कुछ सालों के दौरान इन इलाकों में सोशल मीडिया से जुड़े यूट्यूबर्स की आमद बढ़ी है जो इस मीडिया में फालोवर्स बढ़ाने के सनक के चलते केवल रील्स बनाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं।इसके अलावा कुछ ऐसे समूह भी केदारनाथ सहित अन्य धामों में पहुंच रहे हैं जो ढोल - नगाड़ों और तेज स्पीकर की आवाज में नाचते हुए नजर आते हैं। जबकि अनेक पर्यावरणविदों ने पहले ही चेतावनी दी है कि उत्तराखंड के पहाड़ 'डेंजर जोन' में आता है और तेज आवाज के चलते इसके चट्टान खिसक सकते हैं बावजूद इस चेतावनी का असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरी ओर इस तीर्थक्षेत्र में पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ भी जुर्मानी कार्रवाई किया है जिन्होंने मादक पदार्थों का सेवन किया था। बहरहाल पहाड़ों पर हो रहे इन गतिविधियों से देवस्थानों के मंदिरों की मर्यादा भंग हो रही है। हालांकि मंदिर और स्थानीय प्रशासन इस प्रकार के गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए हर साल निर्देश जारी करती है लेकिन नतीजा शून्य है।

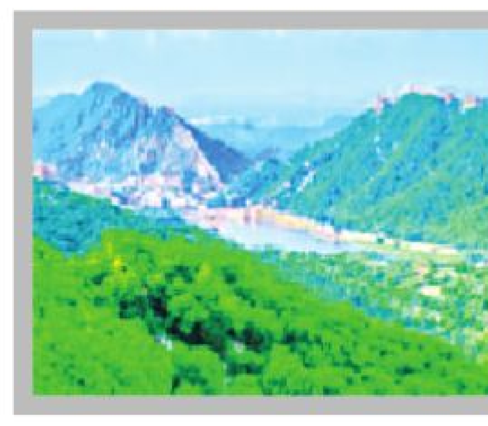

बहरहाल यह कहना गैर-मुनासिब नहीं होगा कि मानव सभ्यता का विकास प्रकृति के गोद में हुआ है लेकिन आधुनिक सभ्यता ने सबसे ज्यादा असभ्यता और अनुदारता प्रकृति के साथ ही दिखाई है। पहाड़ पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा है जो परिस्थितिकी तंत्र को सहेजता है और नदियों का प्रमुख स्रोत भी है।पहाड़ हमारे लिए केवल प्राकृतिक संसाधन ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक धरोहर है। देश के इतिहास पर गौर करें तो मध्ययुगीन काल की अनेक वीर गाथाएं और परंपराएं पहाड़ों से ही जुड़ी है। पहाड़ सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील होते हैं। चिंतनीय है कि अंधाधुंध विकास की अंधी दौड़ के चलते पहाड़ों के सीने को छलनी किया जा रहा है। विकास के लिए बिजली चाहिए और इसके लिए अविरल नदियों को बांधकर पहाड़ों पर जलविद्युत परियोजनाएं बनाई जा रही है। जलविद्युत संयंत्रों और सड़क निर्माण के दौरान पहाड़ों को खोखला कर कई किलोमीटर लंबाई वाले सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। इन परियोजनाओं और निर्माण के लिए दैत्याकार क्रेन और भारी निर्माण उपकरण पहाड़ों को खोद रहे हैं, चट्टानी सीने को बारुद के विस्फोटों से तोड़ा जा रहा है। पहाड़ों को सहेजे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है।पेड़ों के कटने, विस्फोट और ड्रिल मशीनों के कंपन से पहाड़ों की मिट्टी और चट्टान कमजोर होकर धसकने लगे हैं जिसके चलते इन क्षेत्रों में आपदाएं लगातार बढ़ रही है।

देश में जारी शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, सड़कों, बांधों के निर्माण और खनिज उत्खनन के लिए पहाड़ों को खोदा जा रहा है। विचारणीय है कि उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद वहां की सरकारों ने बिजली उत्पादन और पर्यटन उद्योग को अपने पहली प्राथमिकता में रखा जिसके चलते इस राज्य में पनबिजली परियोजनाओं और होटल-रिसॉर्ट निर्माण की बाढ़ आ गई है। केंद्र सरकार ने चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए "ऑल वेदर रोड" का निर्माण भी शुरू कर दिया।पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के आवागमन और आवास की सुविधा के लिए पहाड़ों और पेड़ों को काटकर सड़कें, पुल, होटल, रिसॉर्ट और कृत्रिम पर्यटन केंद्र बनाए जा रहे हैं जिससे पहाड़ों का परिस्थितिकीय तंत्र भी बिगड़ रहा है।

विडंबना है कि हमारी व्यवस्था अब देश के इतिहास के साथ भूगोल को भी बदलने के लिए आमादा है जिसके घेरे में जंगल, पहाड़ और नदियां हैं। गौरतलब है कि विकास का सपना शुरू में लुभावना होता है लेकिन जब यह विनाश बनकर प्रकट होता है तो वह बड़ा ही प्रलयंकारी और भयावह होता है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा कितना भयानक हो सकता है? इसका अंदाजा साल 2013 में केदारनाथ के जलतांडव से लेकर 2025 में जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, भूस्खलन, बादल फटने से हुई तबाही से लगाया जा सकता है।बीते एक दशक के दौरान कश्मीर से कन्याकुमारी तक के पहाड़ी इलाकों में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की वजह से हजारों लोगों की मौतें हुई है तथा सैकड़ों हताहत हुए हैं वहीं अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ है।

विचारणीय यह भी है कि पहाड़ों पर हो रहे अत्याचार के लिए केवल सरकार और मशीनरी ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि आम जनता भी समान रूप से जवाबदेह है जो मानव सभ्यता का कचरा पहाड़ों और नदियों पर डाल रहे हैं। पर्वतीय इलाकों में पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के वाहनों के धुएं और हार्न उस इलाके में वायु और ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं फलस्वरूप पर्यावरण और ईकोसिस्टम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यहां आने वाले लोगों द्वारा हर महीने हजारों टन प्लास्टिक कचरा जिसमें प्लास्टिक बोतल, पॉलिथीन बैग, शीतल पेय के केन, स्ट्रा, चिप्स एवं अन्य खाद्य पदार्थों के पैकेट और अन्य डिस्पोजेबल सामान पहाड़ों, जंगलों या नदियों में फेंक दिए जाते हैं। एक एनजीओ हीलिंग हिमालय के प्रदीप सांगवान बताते हैं कि हिमालयन क्षेत्र के पर्यटन स्थलों से वे रोज 1.5 टन गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा इकट्ठा करते हैं। ये प्लास्टिक कचरे हिमालय के तापक्रम को बढ़ाते हैं जिससे ग्लेशियर पिघलता है फलस्वरूप झील बनते हैं जो जलतांडव लाते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि पहाड़ों पर हो रहे आपदा कुदरती नहीं बल्कि इंसानी आपदा है और इसकी कीमत आने वाली पीढ़ी को भी चुकाना होगा।

बहरहाल भारत के अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। पहाड़ हमेशा से पर्यटकों को बुलाते रहे हैं लेकिन अब इसकी दुश्वारियां सामने है फलस्वरूप पहाड़ों का सब्र टूटने लगा है। देश में पहाड़ों के विकास, पर्यावरण संरक्षण, आस्था और कानून के चौराहे पर खड़े हैं। सरकार और पर्यावरणविदों के पहाड़ों पर अपने - अपने दावे और वादे हैं। बिलाशक पर्यावरण और इकोसिस्टम के लिए पहाड़ जरूरी है लेकिन आर्थिक विकास और रोजगार के लिए भी पहाड़ जरूरी है। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि पहाड़ों के सहेज कर ही विकास का खाका खींचा जाए ताकि पहाड़ों के अस्तित्व पर कोई संकट न आए।आखिरकार क्या हम ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं जहां जंगल न हो, पहाड़ न हो और नदियों का अविरल प्रवाह न हो ? बेशक इसके बिना इंसानी सभ्यता का अस्तित्व भी खतरे में है लिहाजा विकास के लिए प्रकृति को विमर्श में लाना ही होगा।

श्रद्धांजलि

डॉ. घनश्याम बादल

गोल्डन बॉय शूटर जसपाल राणा का यूं अचानक जाना

भारतीय खेल जगत के लिए 12 जून 2026 का दिन एक गहरे शोक में बदल गया, जब देश के महानतम निशानेबाजों में से एक, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शूटर और कोच जसपाल राणा के निधन का समाचार सामने आया। मात्र 49 वर्ष की आयु में उनका जाना न केवल भारतीय निशानेबाजी के लिए, बल्कि पूरे खेल जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। जिस खिलाड़ी ने दशकों तक अपने अचूक निशाने से भारत का तिरंगा विश्व मंच पर लहराया और बाद में प्रशिक्षक के रूप में नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को सफलता का मार्ग दिखाया, उसका इस प्रकार अचानक चले जाना विश्वास करना कठिन है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की धरती पर जन्मे जसपाल राणा ने उस समय भारतीय निशानेबाजी को पहचान दिलानी शुरू की, जब यह खेल देश में अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय था। कम उम्र में ही उनकी प्रतिभा ने खेल विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। उनके पिता नारायण सिंह राणा स्वयं शूटिंग से जुड़े रहे और उन्होंने ही अपने पुत्र की प्रतिभा को तराशने का कार्य किया। देखते ही देखते, यह युवा खिलाड़ी भारतीय निशानेबाजी का पर्याय बन गया। जसपाल राणा की उपलब्धियों की सूची इतनी लंबी है कि उसे संक्षेप में समेटना कठिन है। वे भारत के सबसे सफल कॉमनवेल्थ गेम्स खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उन्होंने 1994 से 2006 के बीच आयोजित चार राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 15 पदक जीते, जिनमें 9 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। यह उपलब्धि उन्हें भारतीय खेल इतिहास के सर्वाधिक सफल खिलाड़ियों की श्रेणी में स्थापित करती है। एशियाई खेलों में भी उनका प्रदर्शन असाधारण रहा। 1994 एशियन गेम्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। इसके बाद 2006 के एशियाई खेलों में उन्होंने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल और 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। सेंटर फायर पिस्टल प्रतियोगिता में उन्होंने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी भी की थी।

एशियाई खेलों में उनके खाते में कुल आठ पदक दर्ज हैं, जो उनकी निरंतरता और उत्कृष्टता का प्रमाण हैं। देश ने भी उनकी उपलब्धियों का सम्मान किया। मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्हें 1994 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वे सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में शामिल थे। इसके बाद 1997 में उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत किया गया। खेल जगत में उनकी सेवाओं और प्रशिक्षक के रूप में योगदान को देखते हुए वर्ष 2020 में उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह एक दुर्लभ उपलब्धि है कि किसी खिलाड़ी को खिलाड़ी और प्रशिक्षक दोनों रूपों में देश के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा जाए। हालांकि जसपाल राणा की महानता केवल उनके जीते गए पदकों तक सीमित नहीं थी। खेल जीवन के बाद उन्होंने भारतीय निशानेबाजी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। वे उन प्रशिक्षकों में रहे जिन्होंने खिलाड़ियों के भीतर आत्मविश्वास, अनुशासन और विजेता मानसिकता का विकास किया। भारतीय निशानेबाजी की नई पीढ़ी, विशेषकर मनु भाकर जैसी खिलाड़ियों की सफलता के पीछे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर की ऐतिहासिक सफलता ने यह सिद्ध कर दिया था कि जसपाल राणा केवल महान खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि असाधारण गुरु भी थे। उनका असमय निधन इसलिए भी अधिक पीड़ादायक है क्योंकि वे अभी भी भारतीय शूटिंग के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। उनके अनुभव, मार्गदर्शन और नेतृत्व की देश को आगे भी आवश्यकता थी। उनके जाने से जो रिक्तता पैदा हुई है, उसे भर पाना आसान नहीं होगा। पदक जीतने वाले खिलाड़ी समय-समय पर आते रहेंगे, लेकिन खेल को दिशा देने वाले व्यक्तित्व विरले ही जन्म लेते हैं। आज जब हम जसपाल राणा को अंतिम विदाई दे रहे हैं, तब उनके द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों, स्थापित रिकॉर्डों और प्राप्त सम्मानों से कहीं अधिक उनकी वह विरासत स्मरणीय है जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को सौंपी है। उनके निशाने ने केवल लक्ष्य भेदे नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीय युवाओं के सपनों को भी दिशा दी। भारतीय खेल इतिहास में उनका नाम सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। भारतीय खेल जगत का यह सितारा भले ही अस्त हो गया हो, किंतु उसकी चमक कभी मंद नहीं पड़ेगी। भावभीनी श्रद्धांजलि।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

चेतना की चौथी अवस्था है शिव तत्व

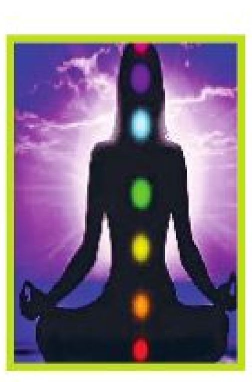

संकलित
दर्शन

शिव को अनुभव करने का प्रयास न करें। आपको बस उस पल में मौजूद रहना है और निश्चिंत रहना है, शिव तत्व पहले से ही वहां मौजूद है। हमारी चेतना की 3 अवस्थाएं हैं - जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति, और चेतना की एक चौथी अवस्था भी है, जहां हम न तो जाग्रत होते हैं, न स्वप्न देखते हैं और न ही सोते हैं। इसका अनुभव ध्यान में होता है। उस चौथी अवस्था की झलक को ही शिव तत्व कहा जाता है। उपनिषद कहते हैं शिवम्, शांतम्, अद्वैतम्, चतुर्थम्, मन्यन्ते, सा आत्मा, सा विज्ञेय। अर्थात शुभ, शांतिपूर्ण चौथी अवस्था, जहां दो नहीं हैं, वह तुम्हारा स्वरूप है, वही जानने योग्य है। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? आप केवल एक नाम नहीं हैं, मात्र एक रूप नहीं हैं। आप वह प्रकाशमान चेतना हैं जो शिव तत्व है। शिव का मंदिर पत्थरों से नहीं मनुष्य की चेतना से बना है। वह जो संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित करता है, वह सत्ता जिसमें हर जीवन समाया है, वह रहस्यमय शिव तत्व है। नटराज स्वयं चेतना हैं, उनमें पांच तत्वों को दर्शाया गया है। चेतना का नृत्य संपूर्ण ब्रह्मांड है। यह ब्रह्मांड संघर्ष या कष्ट नहीं दे रहा है; यह हर क्षण उत्सव मना रहा है। ये आनंद है, जो यह नहीं जानता, वह दुःखी होता है, निराश होता है, पीड़ित होता है। जो यह जानता है कि यह संपूर्ण सृष्टि एक नृत्य है, उसे आनंद मिलता है। यह सत्य शिव तत्व है।

व्यक्ति की अच्छी बातों को याद कर उसे जीवन में उतारे

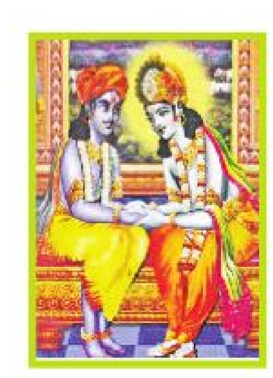

संकलित
प्रेरणा

महाभारत में श्रीकृष्ण की मदद से पांडवों ने कौरवों का पराजित कर दिया था, इसके बाद युधिष्ठिर राजा बन गए। महाभारत युद्ध के बाद जब श्रीकृष्ण द्वारका पहुंचे तो कुछ समय बाद यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए। जब श्रीकृष्ण का अपने धाम लौटने का समय आया तो उन्होंने अपना अंतिम ज्ञान उद्धव को दिया था। उद्धव श्रीकृष्ण के काका के बेटे थे और बहुत विद्वान थे। उद्धव ने श्रीकृष्ण से कई प्रश्न पूछे और भगवान ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। जब उद्धव श्रीकृष्ण की बातों से संतुष्ट हो गए तो श्रीकृष्ण ने कहा कि उद्धव, अब मैं अपने धाम जाऊंगा यानी मैं इस संसार को छोड़कर जाने वाला हूं। अब तुम्हें भी मुझसे विदा होना होगा। ये बात सुनकर उद्धव दुखी हुए और उन्होंने श्रीकृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्रीकृष्ण ने उद्धव को समझाते हुए कहा कि इस दुनिया में सभी अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। इतना कहने के बाद श्रीकृष्ण ने अपनी चरण पादुकाएं उद्धव को भेंट में दे दीं और कहा, इस भेंट को याद रखना और अब तुम बद्रीकाश्रम चले जाओ। बद्रीनाथ के पर्वतों पर मैंने तुम्हें जो बातें बताई हैं, उन बातों का चिंतन करना। ये पादुकाएं तुम्हें मेरी अच्छी बातें याद दिलाएंगी। जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, उसका लोगों के हित में सही उपयोग करना। श्रीकृष्ण की ये बातें सुनकर उद्धव वहां से चले गए। इसके कुछ समय बाद जरा नाम के शिकारी का बाण श्रीकृष्ण के पैर के तलवे पर लगा। इसके बाद श्रीकृष्ण अपने धाम लौट गए।

अंतर्मन

आज की पाती

पाकिस्तान की बर्बरता पर ये मौन क्यों?

पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के नागरिक लंबे समय से सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग करते आ रहे हैं, किंतु पाकिस्तानी सरकार अपने कब्जे वाले कश्मीरी क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बजाय सेना के दमन चक्र से वहां के नागरिकों की हत्याएं करती आई है। पाकिस्तानी हुकूमत और सेना द्वारा वर्षों से अधिकृत कश्मीरी लोगों को जबरन जेलों में बंद कर प्रताड़ित किया जाता है, उनके घरों की महिलाओं और बच्चियों की अस्मिता लूटी जाती है और विरोध के बदले मौत दी जाती है। अभी हाल ही में, इस बार भी कश्मीरियों की मांग नागवार गुजरी और सेना प्रमुख मुनीर के इशारे पर बर्बरतापूर्वक अंधाधुंध गोलाबारी की गई।

- ब्रिजेश अग्रवाल, राजनांदगांव

ट्रेंड

कांग्रेस और एनडीए

कांग्रेस और एनडीए की विकास दर में साफ फर्क है! एक ऐसा सिस्टम था जहां काम हमेशा अटकता और टलता रहता था, जबकि आज का सिस्टम कहता है कि काम समय पर और बड़े पैमाने पर होगा।
- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

त्रिपक्षीय समझौता

भारत सरकार, असम और नागालैंड सरकार के बीच एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे पूर्वोत्तर में दशकों से चला आ रहा विवाद खत्म हो गया है। इस क्षेत्र में तेल और गैस की खोज का रास्ता खुल गया है। यह भारत की एकता का बेहतरीन उदाहरण है।
-अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

विपक्ष गैरजिम्मेदार

आज विपक्ष कितना गैरजिम्मेदार हो गया है! अगर हम हिमाचल प्रदेश जीत जाते हैं, तो हम शेर बन जाते हैं, लेकिन अगर चुनाव हार जाते हैं, तो चुनाव आयोग खराब हो जाता है! आप किस तरह की पार्टी बन गए हैं, आपकी क्या हालत है?
- जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

राणा को श्रद्धांजलि

भारत के सर्वश्रेष्ठ निशानेबाजों में से एक और एथलीटों की कई पीढ़ियों को प्रेरित करने वाले मार्गदर्शक जसपाल राणा के निधन से मैं अत्यंत दुखी हूं। उत्कृष्टता के प्रति उनके समर्पण और भारतीय खेल जगत में उनके अपार योगदान ने हमारे राष्ट्र पर अमिट छाप छोड़ी है।
- राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

करंट अफेयर

पाक में गरीबों की संख्या बढ़कर सात करोड़ हुई

पाकिस्तान में पिछले छह वर्षों में गरीबी सात प्रतिशत बढ़ गई है जिससे लगभग 2.7 करोड़ लोग गरीबी के दायरे में आ गए हैं और इसके साथ ही देश में कुल गरीबों की संख्या बढ़कर सात करोड़ हो गई है। देश के राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। पाकिस्तान आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, को बृहस्पतिवार को वार्षिक प्रक्रिया के तहत जारी किया गया। यह प्रक्रिया संघीय बजट पेश किए जाने से पहले आर्थिक संकेतकों को साझा करने के लिए की जाती है। इस सर्वेक्षण में सामने आया है कि वर्ष 2018-19 में गरीबी का स्तर 21.9 प्रतिशत था, जो 2024-25 में बढ़कर 28.9 प्रतिशत हो गया। सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण गरीबी 28.2 प्रतिशत से बढ़कर 36.2 प्रतिशत हो गई जबकि शहरी गरीबी 11 प्रतिशत से बढ़कर 17.4 प्रतिशत तक पहुंच गई। प्रांतीय स्तर के आंकड़ों से पता चलता है कि सभी क्षेत्रों में गरीबी में वृद्धि दर्ज की गई है। पंजाब प्रांत में यह 16.5 प्रतिशत से बढ़कर 23.3 प्रतिशत हो गई, सिंध में 24.5 प्रतिशत से बढ़कर 32.6 प्रतिशत, खैबर पख्तूनख्वा में 28.7 प्रतिशत से बढ़कर 35.3 प्रतिशत और बलूचिस्तान में 41.8 प्रतिशत से बढ़कर 47 प्रतिशत हो गई। बलूचिस्तान में गरीबी दर सबसे अधिक दर्ज की गई, जबकि चारों प्रांतों में पंजाब में गरीबी दर सबसे कम रही।

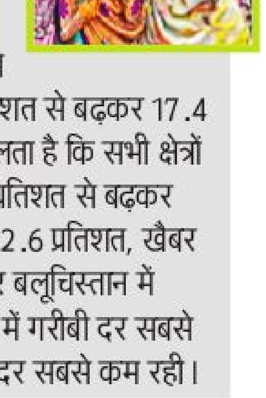

ऑफ बीट

क्या युवाओं में कैंसर के लिए रसायन ज़िम्मेदार हैं?

पहले कैंसर को आमतौर पर बुज़ुर्गों की बीमारी माना जाता था लेकिन अब 50 साल से कम उम्र के लोगों में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, जो चिंताजनक है। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में आपके डीएनए की एक प्रति होती है - जो उस कोशिका को ठीक से कार्य करने का निर्देश देती है। हालांकि, डीएनए में ऐसे तरीकों से म्युटेशन हो सकता है जिससे वह कोशिका अपना वह कार्य करना बंद कर देती है जो उसे करना होता है। कुछ म्युटेशन कोशिका को अनियंत्रित रूप से बढ़ने में सक्षम बनाते हैं। कुछ म्युटेशन इसे मरने से बचाते हैं। और कुछ इसे शरीर के अन्य भागों में फैलने में मदद करते हैं जहां यह नहीं होना चाहिए। डीएनए में अधिक मात्रा में म्युटेशन कैंसर को जन्म दे सकता है। जब भी शरीर में नई कोशिका बनती है, तो डीएनए की एक नई प्रति भी बनती है। कभी-कभी संयोगवश गलतियां हो जाती हैं, जिससे म्युटेशन हो सकता है। इसे आप ऐसे समझें जैसे एक फोटोकॉपी की फोटोकॉपी बनाना। इस प्रक्रिया में हर प्रति दूसरे से थोड़ी भिन्न होती है। ज्यादातर डीएनए म्युटेशन हानिरहित होते हैं। लेकिन शरीर में हर दिन अरबों कोशिकाएं बनती हैं। इसलिए जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में डीएनए की प्रतियों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे गलतियां होने की संभावना भी बढ़ जाती है। साथ ही, उम्र बढ़ने पर शरीर इन खराब कोशिकाओं को पहचान कर हटाने में भी कमजोर हो जाता है।

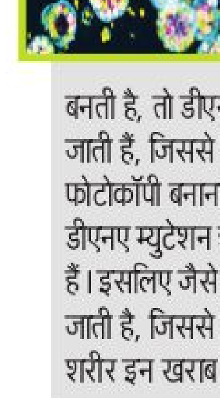

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

बाजार में अच्छे संकेत

शुक्रवार को एक ओर, जहां भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखी गई, वहीं डॉलर के मुकाबले रुपये के भाव में भी बढ़त का क्रम बना है। शेयर बाजार में लगातार गिरावट को लेकर चिंता बढ़ रही थी और गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते दिनों कुछ मौद्रिक उपाय किए थे। इसके अलावा अमेरिका-ईरान युद्ध के भी समापन की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर, दुनिया में निवेश अनुकूल माहौल बना है, जिसका फायदा भारत और भारतीय शेयर बाजार को भी मिलता दिख रहा है। शुक्रवार को मुंबई शेयर बाजार का सूचकांक सेंसेक्स 75,527.95 अंकों पर बंद हुआ और निफ्टी ने 23,600 के आंकड़े को पार कर लिया। मुंबई शेयर बाजार में 1,695.40 अंकों की उछाल के पीछे विश्व स्तर पर कच्चे तेल की गिरती कीमत भी एक बड़ा कारण है। क्रूड ऑयल की कीमतों में चार से पांच प्रतिशत की गिरावट आई है और यह 86 से 90 डॉलर प्रति बैरल तक आ गया है। कच्चे तेल के घटते भाव से अर्थव्यवस्थाओं को निश्चित ही बल मिलेगा और निवेशकों का मनोबल बढ़ेगा।

यह हम अच्छे से जानते हैं कि विश्व स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में जब गिरावट आती है, तब भारतीय अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ता है। जब तेल आयात का हमारा खर्च बचेगा, तब रुपये को भी बल मिलेगा। हालांकि, यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि युद्ध वाकई खत्म होने वाला है और भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का क्रम तेज होने वाला है। ध्यान रहे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी युद्ध विराम के संकेत दे चुके हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि युद्ध समापन की ओर बढ़ेगा। संकेत मिल रहे हैं कि जी 7 की आगामी बैठक के दौरान ही कोई समझौता हो जाएगा। जी 7 की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति भी जा रहे हैं और भारतीय प्रधानमंत्री भी वहां रहेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री और विश्व के अन्य आला नेताओं को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पश्चिम एशिया में फिर अमन-चैन बहाल हो जाए। दुनिया इस फिजूल युद्ध को ज्यादा समय तक नहीं झेल सकती। आज के हालात में दुनिया का कोई देश महंगाई या मंदी झेलने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका की स्थानीय राजनीति में खुद डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। अनेक लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्रंप ऐसे युद्ध में संसाधन क्यों खर्च कर रहे हैं? ऐसे में, जिन शक्तिशाली देशों के हाथों में अमन-चैन की कमान है, उन्हें विशेष रूप से सजग होना पड़ेगा। जी 7 की बैठक में दुनिया के प्रति ज्यादा गंभीर फैसलों की उम्मीद करनी चाहिए। आज दुनिया जिस निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है, वहां जरूरी है कि युद्धों को रोका जाए और महाशक्तियां वैश्विक विकास व मानवीयता के लिए काम करें।

युद्ध विराम के आसार व कच्चे तेल की कीमत घटने से भारतीय शेयर बाजार में सुधार के संकेत दिखे हैं। आगे गिरावट रोकने के हरसंभव प्रयास जारी रहने चाहिए।

वैसे, भारत को अपने शेयर बाजार में फौरी सुधार से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अभी और कदम उठाने की जरूरत है। विश्व स्तर पर सुलह की कोशिशों के साथ ही, आंतरिक रूप से भी अर्थव्यवस्था को संबल देते रहना होगा। दक्षिण कोरिया, जापान और हांगकांग के शेयर बाजारों में भारत से ज्यादा तेजी देखी गई है। मतलब, वहां भारत की तुलना में ज्यादा तेजी से निवेश आ रहा है। भारत में भी अधिक तेजी से निवेश आए, इसके लिए अन्य मौद्रिक और बुनियादी प्रयासों की भी जरूरत है। महंगाई अभी काबू में है, तो उस पर पकड़ बनी रहनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में बाह्य और आंतरिक रूप से सबके विश्वास को बहाल रखना आज समय की सबसे बड़ी मांग है।

हिन्दुस्तान Hindustan | **75 साल पहले** 13 जून, 1951

शुभ संदेश और स्पष्ट चेतावनी

अनेक भारतीयों की शिकायत है कि श्री जवाहरलाल नेहरू भाषण और वक्तव्यों में अपनी शक्ति का बहुत अपव्यय करते हैं। अपव्यय या सद्व्यय का प्रश्न स्वयं नेहरूजी के निर्णय करने का है; किन्तु जो बातें स्पष्ट हैं- उनके अनेक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय वक्तव्यों से पश्चिमी देशों के छूटभैया राजनीतिज्ञों की भौंहें चढ़ जाती हैं और ब्रिटेन तथा अमरीका की संसदों में उनके रोष का पारा चढ़ा हुआ दिखलाई पड़ता है। दूसरी ओर, सामान्यतः एशिया और विशेषतः भारत पर उनका परिणाम आशा और स्फूर्ति का संचार करनेवाला होता है।

ऐसा ही एक वक्तव्य सोमवार को पत्र-प्रतिनिधियों के समक्ष उन्होंने दिया। वक्तव्य अत्यन्त व्यापक है और उसमें पश्चिमी देशों के रोष तथा भारत व एशिया के लिए प्रसन्नता का संदेश ओतप्रोत है। उसे पढ़ कर शंका होने लगती है कि क्या स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के इस निष्ठावान पुजारी ने सब प्रकार के साम्राज्यवाद के विरुद्ध सर्वत्र शंखनाद करने का संकल्प कर लिया है।

नेहरूजी के इस वक्तव्य से भारत के काश्मीर-संबधी रुख पर विशद प्रकाश पड़ता है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने हाल में जो रुख ग्रहण किया है, वह पूर्णतया विकृत और असत्य है। उसमें पाकिस्तान को ब्रिटेन तथा अमरीका से प्रोत्साहन तथा सहायता मिल रही है। हमने यथासंभव शिष्ट तथा सौम्य ढंग से ब्रिटेन और अमरीका को बता दिया है कि उन देशों के पत्रों और पाकिस्तान की सम्पूर्ण वितण्डा मूढ़ता-मात्र है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहाः 'मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि परिणाम कुछ भी हो, हम काश्मीर के बारे में कोई मूढ़ता सहन नहीं करेंगे।'

नेहरूजी के ये शब्द काश्मीर तथा भारत की जनता को समाधान और ब्रिटेन तथा अमरीका को एक कड़ी चेतावनी देनवाले हैं। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अबतक जितनी बार काश्मीर का प्रश्न उठा, प्रत्येक बार इन दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने उसे वास्तविकता से परे रखने का प्रयत्न किया। यह उनकी सत्ता-राजनीति का एक खेल था, जिसमें वे अपने अनुयायी देशों को साथ लेकर बहुत हद तक सफल भी हुए। पाकिस्तान आज काश्मीर पर अनायास ही अधिकार पा जाने के लोभ से उनके हाथों में खेल रहा है।

एक समय था, जब भारत फुटबॉल में एशिया का सरताज हुआ करता था, यहां तक कि ओलंपिक में भी भारतीय टीम की धमक सुनाई पड़ती थी, मगर आज हम दुनिया के इस सबसे बड़े लीग आयोजन में महज मूकदर्शक बनकर रह गए हैं। फीफा रैंकिंग में हमारी टीम बेहद शर्मनाक पायदान पर दिखती है। आखिर कैसे पुराना गौरव हासिल करेंगे? कहां-कहां कमियां दिखती हैं? भारत में फुटबॉल की स्थिति पर दो दृष्टिकोण :

आमने-सामने

नीति और नीयत से बन सकेंगे फिर सिरमौर

यहां स्कैन करें

अनादि बरुआ | पूर्व राष्ट्रीय कोच, फुटबॉल

बहुत पुरानी बात नहीं है। पिछले साल सितंबर में सीएएफए नेशंस कप फुटबॉल टूर्नामेंट में तीसरे और चौथे स्थान के लिए मैच हो रहा था। मुकाबला भारत और ओमान के बीच था। तमाम विश्लेषक यही मानकर चल रहे थे कि जीत ओमान की होगी, क्योंकि इससे पहले किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में ओमान पर भारत भारी नहीं पड़ा था। इसका नतीजा 3-2 से भारत के पक्ष में रहा। दिलचस्प है, यह जीत पेनल्टी शूटआउट में मिली थी, जबकि इस मामले में ओमान का रिकॉर्ड हमसे बेहतर रहा है। जाहिर है, ऐसी सफलता यूं ही नहीं मिली। यह फुटबॉल की बेहतरी के लिए लगातार किए जा रहे कार्यों का नतीजा है।

भारतीय फुटबॉल का इतिहास गौरवशाली रहा है। भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने 1950 में ब्राजील में होने वाले फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया था, क्योंकि क्वालीफाइंग ग्रुप की कई टीमों ने अपना नाम वापस ले लिया था। हालांकि, भारत उस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाया, क्योंकि आर्थिक तंगी थी और फीफा के नियम प्रतिकूल थे। भारतीय खिलाड़ी उस समय नंगे पैर खेलने के आदी थे।

भारतीय फुटबॉल का सुनहरा दौर 1951 से 1964 तक रहा। इस दौरान 1951 के एशियाई खेलों में स्वर्ण, 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में चौथा स्थान (इसमें क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हमारी टीम ने हराया था), 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और 1964 के एएफसी एशियन कप में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। फुटबॉल की इस शानदार विरासत के बावजूद, भारत की मौजूदा फीफा रैंकिंग 139 है, जिस कारण वह 11 जून से शुरू हुए फीफा विश्व कप का हिस्सा नहीं बन सका है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको मिलकर इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, फीफा विश्व कप के इतिहास में यह पहला मौका है, जब दुनिया भर के 200 से ज्यादा टीमों में से 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 'एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन' से रिकॉर्ड नौ टीमें हैं- ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक, जापान, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान। जॉर्डन और उज्बेकिस्तान तो पहली बार इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने हैं।

ऐसा नहीं है कि भारत में प्रतिभाओं की कमी है। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, इंडियन सुपर लीग (आईएसएल), आई-लीग, सुपर कप सहित अंडर-8 से लेकर अंडर-24 तक अलग-अलग उम्र वर्ग की महिला व पुरुष नेशनल चैंपियनशिप इस बात की साक्षी हैं कि देश के अलग-अलग हिस्से में प्रतिभाएं छिपी पड़ी हैं। फिर भी, खेल का स्तर सुधारने के लिए न सिर्फ और अधिक बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने पड़ेंगे, कोचिंग और प्रतियोगी टूर्नामेंट्स भी आयोजित करने होंगे। सही योजना बनाकर बुनियादी स्तर पर काम किए जाएं, तो भारतीय टीम फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने के साथ ही एशिया में मजबूत जगह बना सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फुटबॉल और अन्य खेलों में निजी रुचि ली है। भारत ने प्रतिष्ठित फीफा अंडर-17 विश्व कप की सफल मेजबानी की। इसका उत्साहजनक नतीजा यह रहा कि इसमें भाग लेने वाले कई खिलाड़ी अब फीफा विश्व कप-2026 में अपने-अपने देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत ने इसी तरह आईएफसी वुमेंस चैंपियनशिप क्वालीफाइंग मैचों की भी मेजबानी की। खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया मास्टर्स गेम्स, नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जैसी पहल की हैं। अगर भारत को भविष्य में फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई करना है, तो स्कूल, जिला और राज्य स्तर पर चार से 10 साल की उम्र के खिलाड़ियों के लिए ज्यादा टूर्नामेंट आयोजित करने होंगे। हमें न सिर्फ होनहार खिलाड़ियों की पहचान करनी है, बल्कि उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी, ताकि वे बॉल को नियंत्रण में रखने, फुटवर्क, स्टैमिना व खेल की समझ बना सकें।

सबसे अहम बात कि माता-पिता, स्कूल के प्रिंसिपल, खेल शिक्षक और कोच में ईमानदारी के साथ खुद खिलाड़ियों को अनुशासन बनाए रखना होगा। जरूरी है कि सरकारी व निजी स्कूलों के मैदानों का इस्तेमाल फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए किया जाए। इससे हजारों बच्चे नियमित तौर पर फुटबॉल कोचिंग का हिस्सा बन सकेंगे। युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पूर्व खिलाड़ियों को कोच बनाना चाहिए। कहने का अर्थ है कि सही योजना, बुनियादी ढांचा, कोचिंग और समर्थन मिलने पर भारत में मजबूत 'फुटबॉल संस्कृति' बन सकती है और तभी हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता हासिल कर सकेंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

फुटबॉल के महाकुंभ में भारत कहीं नहीं

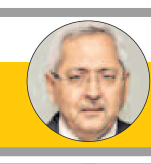

यहां स्कैन करें

मनोज चतुर्वेदी | वरिष्ठ खेल पत्रकार

अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की मेजबानी में फीफा विश्व कप के शुरू होते ही पूरी दुनिया फुटबॉलमय होने लगी है। जाहिर है, हमारा देश भी इसमें पीछे नहीं रहने वाला। करोड़ों फुटबॉल प्रेमी भारतीय अब रातों में जाग-जागकर इस विश्व कप के मैच देखेंगे और दिन भर उनकी चर्चा करते नजर आएंगे। पर हर चार साल पर जब-जब यह आयोजन होता है, तब-तब एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि भारत विश्व कप में क्यों भाग नहीं ले पाता है? जब देश में फुटबॉल के प्रति इस कदर लगाव है, तो इसका देश में फुटबॉल स्तर सुधारने में हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते हैं? सच्चाई यह है कि विश्व कप में भाग लेना तो दूर, हम एशियाई स्तर पर भी अब कहीं नहीं ठहरते हैं।

फुटबॉल में भारत के पिछड़े होने के कई कारण हैं। इनमें बुनियादी ढांचे की कमी, खेल संस्थाओं की अंदरूनी उठा-पटक, संचालक संगठन में पारदर्शिता की कमी और जमीनी स्तर पर ट्रेनिंग सुविधाओं का अभाव इनमें अहम हैं। भारतीय फुटबॉल फेडरेशन ने राजनेता के बजाय फुटबॉलर को जिम्मेदारी सौंपी, पर यह प्रयोग भी देश में रंग दिखाने में कामयाब न हो सका है। हम अभी भी टॉप 100 देशों की सूची से बाहर बने हुए हैं।

दरअसल, हमारे यहां यूरोपीय और लातिन अमेरिकी देशों की तरह पांच-छह साल की उम्र से ही बच्चों को प्रशिक्षित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। यूरोप के छोटे-छोटे देशों में छोटी उम्र से बच्चों को सिखाने के लिए पेशेवर अकादमियां हैं, जिससे उनमें शुरुआत में ही तकनीकी रूप से मजबूत नींव पड़ जाती है। इसके विपरीत हमारे यहां युवा होने पर इस खेल को अपनाया जाता है। देश में पेशेवर अकादमियों की कमी की वजह से फुटबॉल अपनाने वालों में से कुछ ही वहां तक पहुंच पाते हैं।

यूरोप और लातिन अमेरिकी देशों में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र हैं, जो खेल विज्ञान केंद्र से जुड़े रहते हैं। खिलाड़ियों को शुरुआत से आधुनिक जिम की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। भारत में आईएसएल की शुरुआत के साथ ऐसी सुविधाओं की शुरुआत तो हुई है, पर यह कुछ ही खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध हैं। हमारे क्लबों में फुटबॉल फेडरेशन का कोई जोर न चलने का भी नुकसान हो रहा है। आलम यह है कि साल 2023 में ग्वांगझू एशियाई खेलों के लिए चुने गए कई खिलाड़ियों को आईएसएल (इंडियन सुपर लीग) क्लबों ने छोड़ा ही नहीं। इसके कारण भारत अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम भेज ही नहीं सका। यह समस्या कोई नई नहीं है। आईएसएल के साल 2014 में शुरू होने से पहले कोलकाता सीनियर डिवीजन लीग के क्लब ऐसा व्यवहार किया करते थे। हमें याद है, साल 2006 में कोच डेविड हॉटन, ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कैंप के लिए रिलीज नहीं करा सके थे।

भारत की एक बड़ी समस्या यह है कि हमारे यहां फुटबॉल के स्तर को सुधारने के जो भी प्रयास किए जाते हैं, वे ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। आईएसएल की शुरुआत को भी आप इसी तरह देख सकते हैं। असल में जरूरत जमीनी स्तर से सुधार लाने की है। इसके लिए जिला स्तर पर आधुनिक सुविधाओं वाली अकादमियां खोलनी होंगी। ऐसा करना एकदम से तो संभव नहीं है। पर हरेक राज्य में ऐसी दो-चार अकादमियां तो खोली ही जा सकती हैं।

हमारे देश में क्रिकेट को लोग दीवानगी की हद तक प्यार करते हैं। इसकी वजह से इस खेल में पैसे की भरमार है। इस वजह से खेल सुविधाओं व खिलाड़ियों पर खूब पैसा खरचा जाता है। बीसीसीआई की टी-20 लीग आईपीएल हर साल कई बच्चों को करोड़पति बना देती है। फुटबॉल में दशकों तक देश की सेवा करने वाले खिलाड़ी भी इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा नहीं कि फुटबॉल में पैसा नहीं है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में जितना पैसा है, आईपीएल उसके आसपास भी नहीं है। हमारे यहां फुटबॉल की दीवानगी को भुनाने की सही कोशिश तक नहीं की गई है।

आमतौर पर देश खेलों में धीरे-धीरे प्रगति करते हैं। हम हॉकी में बेल्जियम को ही लें। यह टीम 1980 के दशक तक वैश्विक स्तर पर कहीं नहीं टिकती थी, पर आज वह दुनिया की टॉप टीमों में शुमार है।

भारतीय फुटबॉल का स्तर हमेशा से ऐसा नहीं था। 1950 और 60 के दशक को भारतीय फुटबॉल का स्वर्णकाल माना जाता है। इस दौरान देश की टीम ने चुन्नी गोस्वामी, पपीके बनर्जी व बलराम जैसे फुटबॉलर दिए। इस तिकड़ी ने 1956 के ओलंपिक में सेमीफाइनल तक भारतीय चुनौती पेश की थी और 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन हम इसके बाद पिछड़ते चले गए। हालत यह है कि हम फीफा रैंकिंग में 139वें नंबर तक पिछड़ गए हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

भारतीय निशानेबाजी में किंवदंती बन गए थे जसपाल भाई

यहां स्कैन करें

हरप्रीत सिंह | निशानेबाज और कोच

'जसपाल भाई' दूसरों के लिए भले एक खिलाड़ी अथवा कोच रहे, मेरे लिए घर-परिवार के सदस्य जैसे थे। उनको मैंने पहली बार तब जाना, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। एक दिन दूरदर्शन पर खबर देखी कि स्टैंडर्ड पिस्टल प्रतिस्पर्द्धा में जसपाल राणा ने विश्व रिकॉर्ड बनाकर भारत का नाम रोशन किया है। यह देखकर मुझमें भी उनकी तरह खेलने की इच्छा जगी और पहली बार शूटिंग से मेरा रिश्ता बना। जसपाल भाई जीवित ही किंवदंती बन गए थे। जब लोग हमसे पूछा करते कि क्या करते हो और हम जवाब देते 'शूटिंग', तो पहले वे फिल्म वाली शूटिंग समझते, पर निशानेबाजी की बात कहने पर छूटते ही कहते 'जसपाल राणा वाली शूटिंग'।

जसपाल भाई खेल के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। 1994 में जब वह विश्व चैंपियनशिप खेलने गए थे, तब बीमार थे। शायद उन्हें कोई संक्रमण था और डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी। बावजूद इसके वह न सिर्फ शूटिंग रेंज में उतरे, बल्कि विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। अनुशासन, तकनीक और निरंतर अभ्यास उनकी सफलता की कुंजी थी। सामने कोई प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी ही क्यों न हो, वह अगर उसमें कोई गलती देखते, तो उसे सलाह जरूर देते। सन् 2000 में जब मैं अपना पहला राष्ट्रीय चैंपियनशिप खेल रहा था, तब साथ वाली लेन में वह खड़े थे। वह भी स्टैंडर्ड पिस्टल का ही मैच था। मैं थोड़ी-बहुत गलती कर रहा था, तो वह बीच-बीच में मेरे पास आते और समझाते। नहीं समझने पर डांट भी लगा जाते। इतने वर्षों के जुड़ाव में मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। खास तौर पर उनसे खेल भावना सीखने लायक थी।

यही वजह है कि तमाम उपलब्धियां उनके खाते में आईं। उन्होंने हर मुकाबले में अपना प्रभाव छोड़ा। अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी उनका काफी सम्मान करते थे। ऐसी ही एक घटना मुझे याद आ रही है, जो 2010 एशियन गेम्स से जुड़ी है। चूंकि उन्होंने उसका ट्रायल नहीं दिया था, इसलिए उसमें मेरा चयन हुआ था। मैं जब 'प्री-इवेंट प्रैक्टिस' कर रहा था, तब एक विदेशी खिलाड़ी मेरे पास आया और आते ही पूछ बैठा, क्या जसपाल नहीं आए हैं? मैंने कहा, नहीं। तो फिर कौन आया है?- उसका अगला सवाल था। मैंने अपने बारे में उसे बताया, तो उसने तुरंत पूछ लिया कि क्या मैंने उन्हें ट्रायल में हरा दिया था। मुझे इसका जवाब देते नहीं बना, लेकिन उसके चेहरे पर आश्चर्यमिश्रित राहत दिखी कि चलो, जसपाल नहीं आए। इसकी वजह पूछने पर उसने बताया कि वह हर बार अच्छा खेलता है, पर जसपाल उन्हें पदक नहीं जीतने देते।

ऐसा ही एक किस्सा उसने साझा किया। उसने बताया कि एक बार उसने कुल 588 स्कोर किया था और पहले राउंड के बाद जसपाल भाई का स्कोर 288 था।

स्मृति शेष : जसपाल राणा

निशानेबाजी में किसी राउंड में 300 में से 300 अंक लाना लगभग नामुमकिन होता है, इसलिए वह अपनी जीत को लेकर संतुष्ट था। किंतु जसपाल भाई ने असंभव को संभव कर दिखाया, जिससे मुकाबला टाई हो गया और 'टाईशूट' में उन्होंने जीत अपने नाम कर ली। हालांकि, वह आश्चर्य उसके चेहरे पर बाद में भी मैंने देखा कि ट्रायल में जसपाल राणा को हराकर किसी ने एशियन गेम्स का टिकट जीता है, जबकि सच्चाई तो सिर्फ मैं जानता था।

जसपाल भाई हमेशा प्रोत्साहित करते थे। जब भी मिलते, कुछ-न-कुछ नई बात जरूर बता जाते। मैं जब शूटिंग कर रहा था, तब भी उन्होंने गाइड किया, और अब जब कोचिंग कर रहा हूं, तब भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। मुझे याद है कि जब पहली बार मैंने व्यक्तिगत स्पर्द्धा में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी, तब फाइनल मैच में थोड़ा नर्वस था। वह मेरे पास आए और कहा- 'वाई सो नर्वस, जस्ट इंज्वॉय शूटिंग, रिजल्ट विल कम ऑटोमेटिकली।' (क्यों इतने तनाव में हो, खेल का मजा लो, नतीजा खुद-ब-खुद अच्छा आएगा)। वह एक वाक्य मेरे जेहन में ताउम्र चस्पां रहेगा। उनके इन शब्दों से मुझे उस वक्त ही राहत नहीं मिली, बल्कि बाद में भी, जब भी किसी मुकाबले को लेकर मैं तनाव में होता हूं, तब जसपाल भाई के इन शब्दों को दोहराने लगता हूं।

उन्होंने स्टैंडर्ड और सेंटर-फायर पिस्टल में महारत हासिल की थी। इसकी तस्दीक उनके द्वारा राष्ट्रमंडल या एशियन गेम्स जैसे मुकाबलों में जीते गए तमाम पदकों से भी होती है। अर्जुन, पद्मश्री और द्रोणाचार्य जैसे पुरस्कारों से वह सम्मानित थे। इसीलिए जब यह कहा जाता है कि आज भारतीय निशानेबाजी टीम जो उपलब्धियां हासिल कर रही हैं, सब जसपाल राणा की विरासत हैं, तो गलत नहीं जान पड़ता। वह प्रतिभावान खिलाड़ियों का पुल तैयार करके गए हैं।

अभी देहरादून में भारतीय टीम का कैंप चल रहा है और कोच के रूप में यह मेरा पहला कैंप है। जसपाल भाई इसके हेड कोच थे। मैं खुश था कि उनसे फिर सीखने का मौका मिलेगा। मगर लगता है, ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। बीमार होने के कारण वह नहीं आ पाए थे, और अब वह कभी आ भी नहीं पाएंगे। उनको नमन!

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

अनुलोम-विलोम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

बीते बारह वर्षों में भारत खूब आगे बढ़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सबसे ज्यादा दिनों के कार्यकाल का रिकॉर्ड बना। इससे पहले यह रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम था। अभी के शासनकाल में, मैं एक गृहिणी के तौर पर खुद को अधिक सशक्त मानती हूं। ऐसा शायद ही किसी देश में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कितने ही नए मंचों की शुरुआत की, जिसके बारे में उनसे पहले किसी का ध्यान नहीं गया था। 'परीक्षा पे चर्चा' नामक कार्यक्रम महज नाम का मंच नहीं है, बल्कि बच्चों को परीक्षा से पूर्व होने वाले तनाव से मुक्ति दिलाता है। 'मन की बात' विचार व्यक्त करने का मजबूत जरिया बन चुका है। 'माई गोव डॉटकॉम' एक ऐसा मंच है, जिसमें कोई भी नागरिक अपने लिए नए रास्ते बना सकता है। ऐसे में, विपक्ष तमाम खामियां गिनाए, लेकिन सच्चाई तो यही है कि न सिर्फ अपने देश में, बल्कि विदेश में भी अब भारत का परचम ऊंचाई पर लहरा रहा है, जिसके ध्वजवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

कहा तो यही जाता है कि रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं, परंतु यह सामान्य बात नहीं कि एक अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि से आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में लगातार सबसे लंबा शासन करने वाले उन नेहरू जी का कीर्तिमान तोड़ा, जो तब के अत्यंत प्रतिष्ठित और वैभवशाली परिवार से थे। उस समय देश नव-स्वतंत्र हुआ था और कांग्रेस के अलावा सब शून्य था। मगर मोदी सरकार के कार्यकाल की 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, चार करोड़ से अधिक पक्के मकान, 50 करोड़ लोगों को पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा, 10 करोड़ को एलपीजी कनेक्शन, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालना, शौचालय निर्माण, बैंक खाते, सेमीकंडक्टर निर्माण, राम मंदिर निर्माण, नल से जल, अनुच्छेद 370 का अंत जैसी कई उपलब्धियां देश में नया आत्मविश्वास भर रही हैं। यहां प्रधानमंत्री की संघ-प्रचारक की यात्रा की चर्चा स्वाभाविक है। संघ के प्रचारक होने के नाते आम जन से मिले अनुभव, जुड़ाव और संवाद ने उन्हें विलक्षण बना दिया है। वह आम जन की समस्याओं की 'एनसाइक्लोपीडिया' हैं। यह अनुभव सिर्फ जीकर महसूस किया जा सकता है, पढ़कर या स्क्रीन पर देखकर नहीं। इसी के परिणामस्वरूप वह चुनी हुई सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार सेवा के 25 वर्ष भी पूरे करेंगे। राजनीति रूपी काजल की कोठरी में रहने के बावजूद उनके दामन पर कोई दाग न होना, उन्हें देश में विरलतम बना देता है। साफ है, प्रधानमंत्री ने देश का नजरिया बदल दिया है।

मनोज कुमार शर्मा, टिप्पणीकार

कई समस्याएं अब तक नहीं सुलझ सकीं

साल 2014 सिर्फ एक साल नहीं है, बल्कि एक ऐसा मोड़ है, जब करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें सिर्फ एक नाम पर टिक गई थीं- नरेंद्र मोदी। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 साल का सफर तय कर लिया है और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन क्या बेहतर नहीं होगा कि हम उन समस्याओं की भी चर्चा करें, जिनका समाधान यह सरकार अब तक नहीं निकाल पाई है, ताकि पता चल सके कि मोदी सरकार को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए?

सबसे पहले बात रोजगार की। पढ़े-लिखे नौजवान आज भी भटक रहे हैं। डिग्री उनके हाथों में है, लेकिन नौकरी नहीं है। अगर प्रतियोगी परीक्षा होती भी है, तो उसके प्रश्न-पत्र लीक हो जा रहे हैं। इसी तरह, महंगाई भी बदस्तूर आम लोगों की परीक्षा ले रही है। रुपये पर दबाव बना हुआ है और आयात महंगा है, नतीजतन घर-घर का बजट बिगड़ गया है और थाली लगातार महंगी होती जा रही है। आम आदमी की जेब तो हल्की हुई है, उनकी चिंताएं नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य का भी कमोबेश यही हाल है। सरकारी स्कूल और अस्पताल निस्संदेह मौजूद हैं, लेकिन क्या हम सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को समान माहौल मुहैया करा पाते हैं? सरकारी स्कूलों की तो ऐसी दशा है कि अब गरीब से गरीब आदमी भी उनमें अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता। इसी तरह, सरकारी अस्पतालों में भी लोग मजबूरीवश जाते हैं। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र की असली परीक्षा अभी बाकी है। मोदी सरकार की उपलब्धियों पर जश्न मनाना चाहिए, लेकिन उन समस्याओं पर भी चर्चा होनी चाहिए, जिनसे आम लोग लगातार जूझ रहे हैं।

एक बात और, जवाहरलाल नेहरू देश को जो देकर गए हैं, उसकी बराबरी करना आसान नहीं। अलबत्ता हर प्रधानमंत्री का अपना खास योगदान रहा है, और किसी का योगदान दूसरे से कमतर नहीं। नेहरू की बात करें, तो उन्होंने बड़े-बड़े संस्थान तब बनाए थे, जब देश गुलामी से बस आजाद हुआ था। उनके सामने तमाम तरह की चुनौतियां थीं। उस समय आर्थिक रूप से देश बहुत कमजोर था। गरीबी और बेबसी चारों तरफ पसरी हुई थी। भारत उस वक्त अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश कर ही रहा था। तब नेहरू ने देश का कायांतरण कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सहूलियत मिली कि जब उन्होंने देश की कमान संभाली, तब भारत अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने को तैयार था। प्रधानमंत्री ने तो उसे बस रास्ता दिखाया, जिसका नतीजा सबके सामने है।

रियांशी मिश्र, टिप्पणीकार

कारों में दिख रहा एआई का कमाल

एआई और वॉयस रिकग्निशन जैसी तकनीकों के साथ आज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है। ग्लोबल स्तर पर इन तकनीक के बाजार में 2030 तक 10 से 15 फीसदी सालाना वृद्धि का अनुमान है। आखिर एआई किस तरह वाहनों को अधिक उन्नत और सुरक्षित बना रहा है, बता रही हैं तृप्ति मिश्रा

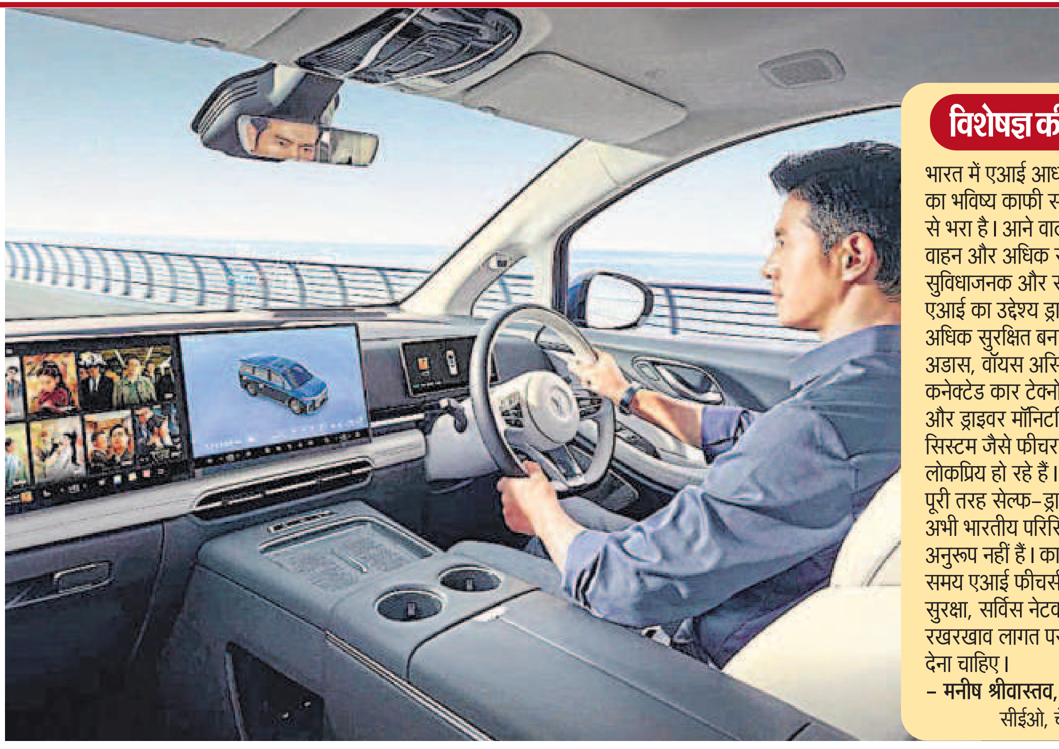

कार अब सिर्फ एक वाहन नहीं है, बल्कि सड़क पर नजर रखने, खतरे की चेतावनी देने और कुछ स्थितियों में खुद ब्रेक लगाने में भी सक्षम हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (अडास) की मदद से कारें तेजी से स्मार्ट बन रही हैं और यह तकनीक अब आम खरीदारों तक पहुंचने लगी है। एआई और अडास अलग-अलग तकनीक होने के बावजूद आधुनिक कारों में साथ मिलकर काम करती हैं। सेंसर और कैमरों से मिले डाटा का विश्लेषण एआई करता है। अडास उसी के आधार पर ब्रेकिंग, अलर्ट और लेन कंट्रोल जैसे फीचर्स संचालित करता है, जिससे ड्राइविंग ज्यादा सुरक्षित हो जाती है। इस कारण नई पीढ़ी के अडास सिस्टम को अक्सर एआई पावर्ड 'अडास' कहा जाता है।

बाजार के साथ बढ़ती पहुंच

भारत में अडास और कनेक्टेड कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। 2025 में अडास से लैस कारों की हिस्सेदारी बढ़कर 8.3 फीसदी हो गई, जो एक साल पहले 6.2 फीसदी थी। वहीं, रिसर्च फर्मों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में कनेक्टेड कारों की हिस्सेदारी 40 से 45 फीसदी तक पहुंच सकती है। अब 15 से 25 लाख रुपये तक की कई कारों में भी अडास व कनेक्टेड फीचर्स मिल रहे हैं, जिससे नई तकनीक मध्यम वर्ग की पहुंच में आ रही है और सुरक्षा एवं सुविधा दोनों बढ़ रही हैं। हालांकि, ये सिस्टम सहायक भूमिका निभाते हैं और सुरक्षित ड्राइविंग की जिम्मेदारी ड्राइवर की ही होती है।

क्यों बढ़ रही लोकप्रियता : बढ़ते हाईवे नेटवर्क, तकनीक में रुचि और सस्ते होते सेंसर कैमरों के कारण स्मार्ट कारों की मांग बढ़ी है। इसी कारण वाहन कंपनियां नए मॉडलों में तेजी से एआई और अडास फीचर्स जोड़ रही हैं।

ऐसे करता है काम

- **ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग :** नई कारों में ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स सड़क पर खतरे को पहले ही पहचान लेते हैं। सामने कोई वाहन अचानक रुक जाए या पैदल यात्री आ जाए, तो सिस्टम ड्राइवर को सतर्क करता है और जरूरत पड़ने पर खुद ब्रेक भी लगा सकता है। लेन कीप असिस्ट और लेन डिपार्चर वार्निंग गाड़ी को अपनी लेन में बनाए रखने में मदद करते हैं।
- **चालक पर पैनी नजर :** ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम चालक की आंखों और चेहरे की गतिविधियों को ट्रैक कर थकान या नींद के संकेत मिलने पर तुरंत अलर्ट जारी होता है। यह सिस्टम तनाव और स्वास्थ्य संकेतों को भी पहचानने में सक्षम हो सकता है।
- **वॉयस और स्मार्ट कंट्रोल :** नई पीढ़ी की कारों में एआई वॉयस असिस्टेंट तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ड्राइवर अब सिर्फ आवाज देकर नेविगेशन, म्यूजिक, एसी और कॉल जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकता है। कुछ सिस्टम सामान्य बातचीत भी समझने लगे हैं, जिससे ड्राइविंग और आसान हो रही है।
- **पार्किंग और सड़क सुरक्षा :** 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और स्मार्ट पार्किंग असिस्ट जैसे फीचर्स पार्किंग व भीड़भाड़ वाली सड़कों पर मदद करते हैं। ये सिस्टम संभावित खतरों की जानकारी देकर दुर्घटना का जोखिम कम करते हैं।
- **ऑगमेंटेड रियलिटी नेविगेशन :** कुछ नई कारों में एआर आधारित नेविगेशन सिस्टम विंडशील्ड या हेड-अप डिस्प्ले पर ही दिशा-निर्देश दिखाते हैं। इससे ड्राइवर को बार-बार स्क्रीन नहीं देखना पड़ता और नेविगेशन आसान व सुरक्षित होता है।

एआई वाली कारें कैसे बनाती हैं ड्राइविंग को स्मार्ट और सुरक्षित?

- **एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल :** यह आगे चल रही गाड़ी के हिसाब से स्पीड को ऑटोमैटिक तरीके से एडजस्ट करता है। ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम चालक की थकान या नींद के संकेत पहचानकर अलर्ट देता है। वहीं ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर साइड या पीछे मौजूद छिपे वाहनों की जानकारी देकर दुर्घटना से बचाने में मदद करता है।
- **ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन :** यह साइड मिरर के पास लगे सेंसर ड्राइवर की नजर से ओझल वाहन का पता लगाते हैं और लेन बदलते समय लाइट या बीप के जरिए अलर्ट करते हैं।
- **ऑटोमैटिक हाई बीम असिस्ट :** सामने से आने वाले वाहनों की रोशनी पहचानकर हेडलाइट की बीम को अपने-आप समायोजित करता है, जिससे रात में ड्राइविंग अधिक सुरक्षित हो जाती है।
- **ट्रैफिक साइन रिकग्निशन सिस्टम :** सड़क के संकेत व गति सीमा को पढ़कर चालक को सतर्क रखता है।
- **स्मार्ट पार्किंग असिस्ट :** तंग जगहों पर पार्किंग को आसान बनाता है, जबकि एआई वॉयस असिस्टेंट आवाज के जरिए कई कमांड्स को नियंत्रित करने की सुविधा देता है।

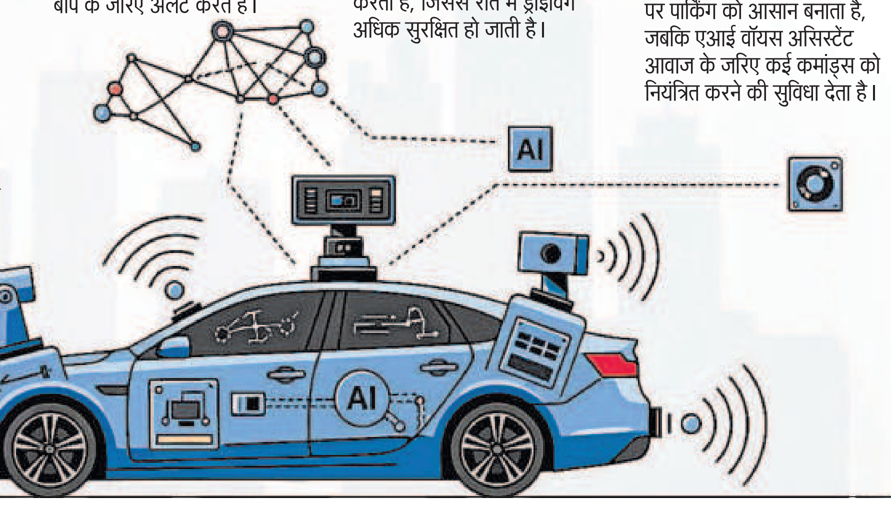

विशेषज्ञ की राय

भारत में एआई आधारित कारों का भविष्य काफी संभावनाओं से भरा है। आने वाले वर्षों में वाहन और अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और स्मार्ट होंगे। एआई का उद्देश्य ड्राइविंग को अधिक सुरक्षित बनाना है। अडास, वॉयस असिस्टेंट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। हालांकि, पूरी तरह सेल्फ-ड्राइविंग कारें अभी भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं हैं। कार खरीदते समय एआई फीचर्स के साथ सुरक्षा, सर्विस नेटवर्क और रखरखाव लागत पर भी ध्यान देना चाहिए।

– **मनीष श्रीवास्तव,** सीईओ, चेरिस टाटा

किन कारों में मिलेंगे ये फीचर?

भारत में फिलहाल एआई और अडास फीचर सबसे ज्यादा मिड-साइज और प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में देखने को मिल रहे हैं। हुंडई क्रेटा, महिंद्रा एक्सयूवी700, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर, हुंडई वर्ना और टाटा नेक्सन ईवी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इनकी कीमतें करीब 11 से 25 लाख रुपये के बीच हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अडास, एआई वॉयस असिस्टेंट, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर कम कीमत वाली कारों में भी पहुंचेंगे, जिससे स्मार्ट व सुरक्षित वाहन आम ग्राहकों की पहुंच में आ सकेंगे।

तकनीक

ओपन एआई का नया सुरक्षा फीचर

चैटजीपीटी में एक नया सुरक्षा फीचर लॉकडाउन मोड जोड़ा गया है। इस फीचर को यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि संवेदनशील और निजी जानकारी के साथ काम करते समय अतिरिक्त सुरक्षा मिल सके।

क्यों बनाया गया

इसका मकसद प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक जैसे साइबर हमलों से निपटना है, जिसमें छिपे निर्देशों से एआई को गुमराह कर गलत या संवेदनशील जानकारी निकलवाने की कोशिश की जाती है। लॉकडाउन मोड ऐसे खतरों से सुरक्षा देने में मदद करता है।

कैसे करता है काम

लॉकडाउन मोड चालू होने पर चैट जीपीटी की कुछ ऑनलाइन और बाहरी इंटरैक्शन संबंधी सुविधाएं सीमित हो जाती हैं। इसका उद्देश्य संभावित साइबर खतरों और डाटा के दुरुपयोग के जोखिम को कम करना है। इस तरह यह मोड एक अतिरिक्त सुरक्षा परत के रूप में काम करता है, जिससे संवेदनशील जानकारी अधिक सुरक्षित रहती है।

किनके लिए उपयोगी

यह फीचर पत्रकारों, शोधकर्ताओं, कारोबारी पेशेवरों और संवेदनशील जानकारी संभालने वाले उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी हो सकता है। इससे महत्वपूर्ण डाटा की सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिल सकती है और इस्तेमालकर्ताओं को अधिक सुरक्षित अनुभव मिल सकता है।

अर्पित सोनी

गैजेट

कम कीमत में दमदार बैटरी वाले नए फोन

बड़ी बैटरी के साथ आया रियलमी पी4आर 5जी

रियलमी ने भारतीय बाजार में अपना नया रियलमी पी4आर 5जी स्मार्टफोन पेश किया है। यह फोन उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर लाया गया है, जो 20 हजार रुपये से कम कीमत में बड़ी बैटरी, 5जी कनेक्टिविटी और आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं।

लंबी चलेगी बैटरी : फोन में 8000एमएएच की बैटरी दी गई है। यह एक बार चार्ज करने पर कई दिनों तक साथ दे सकती है। इसके साथ 45 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।

144 हट्ज डिस्प्ले देगा बेहतर अनुभव : इसमें 6.8 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, जो 144 हट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इससे स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो देखने का अनुभव बेहतर हो सकता है।

कैमरे पर नजर : फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का एआई कैमरा दिया गया है। इसके अलावा एआई इरेजर, एआई अल्ट्रा क्लैरिटी और अन्य स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं, जो तस्वीरों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

मजबूत पेशकश : फोन में मिलिट्री-ग्रेड मजबूती के साथ आईपी 65 रेटिंग दी गई है, जो इसे धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा प्रदान करती है।

कीमत इतनी : 4जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज की कीमत 18,999 रुपये रखी गई है। छूट के साथ और भी सस्ती हो जाती है।

रंग और उपलब्धता : यह टाइटेनियम ग्लेयर, सिल्वर ग्लेयर और लैवेंडर ग्लेयर रंगों में उपलब्ध होगा। रियलमी की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकेंगे।

इनफिनिक्स स्मार्ट 20

इनफिनिक्स ने भारतीय बाजार में अपना नया बजट स्मार्टफोन इनफिनिक्स स्मार्ट 20 पेश कर दिया है। कंपनी ने इसे उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है, जो कम कीमत में बड़ी बैटरी, अच्छा डिस्प्ले और आधुनिक फीचर्स वाला फोन खरीदना चाहते हैं।

नेविगेशन होंगे बेहतर : फोन में 120हट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है, जिससे स्क्रॉलिंग और एप्स का इस्तेमाल अधिक बेहतर महसूस होगा। यह फीचर आमतौर पर महंगे स्मार्टफोन में देखने को मिलता है।

5200एमएएच बैटरी : 5200 एमएएच की बड़ी बैटरी दी गई है, जो सामान्य उपयोग में पूरे दिन का बैकअप देने में सक्षम है। फोन में मीडियाटेक हीलियो जी81 अल्टीमेट प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के दौरान बेहतर प्रदर्शन देने में मदद करता है।

कौन से फीचर काम के : फोन में कई एआई आधारित फीचर्स शामिल किए गए हैं, जो यूजर के अनुभव को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा आईपी64 रेटिंग के साथ यह धूल और पानी के छींटों से भी सुरक्षा देता है।

कीमत कितनी : वेरिएंट के अनुसार कीमत 12,499 रुपये से शुरू होकर 13,999 रुपये रखी गई है।

कितने रंगों में : सनलाइक ऑरेंज, क्लाउड-लाइन ब्लू, शैडो ब्लैक और पोलारिस टाइटेनियम रंगों में मिलेगा।

इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से खरीदा जा सकता है।

सैमसंग के नए बजट फोन भी जल्द आएंगे

सैमसंग जल्द ही अपने दो नए बजट स्मार्टफोन गैलेक्सी एफ 08 4 जी और गैलेक्सी एम 08 4जी लॉन्च कर सकता है। हाल ही में ये दोनों मॉडल जीएसएमए डेटाबेस में देखे गए हैं, जिससे इनके आने के संकेत मिले हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी इनके फीचर्स और लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी कीमत 10 हजार रुपये से कम हो सकती है।

– फीचर डेस्क

मौसम खराब हो, तो बाइक चलाते समय रहें सतर्क

भीषण गर्मी, लू और आंधी-बारिश में बाइक चलाना जोखिम भरा होता है। सड़क फिसलन भरी हो जाती है और तेज हवाएं संतुलन बिगाड़ सकती हैं। अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, आइए जानें...

ड्राइविंग टिप्स

कारों की तुलना में बाइक पर सफर करते समय मौसम का असर ज्यादा जल्दी महसूस होता है, क्योंकि इसमें कोई बंद केबिन नहीं होता। तेज धूप, गर्म हवाएं और अचानक बदलती मौसम की स्थिति सीधे चालक को प्रभावित करती है, जिससे थकान और असंतुलन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सावधानी और ड्राइविंग की सही आदतें अपनाना बेहद जरूरी हो जाता है।

तेज गर्मी में बाइक पर पड़ने वाला असर : तेज गर्मी में सिर्फ बाइक चालक ही नहीं, बाइक चलाने की क्षमता भी प्रभावित होती है। लगातार गर्म हवा और उच्च तापमान से इंजन जल्दी गर्म होने लगता है, जिससे चलाने में दिक्कत बढ़ सकती है। टायर का प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिससे ग्रिप पर असर पड़ता है और गड्ढों या मोड़ों पर नियंत्रण थोड़ा कमजोर हो सकता है। लंबे समय तक धूप में खड़ी बाइक की सीट और मेटल पार्ट्स भी बहुत गर्म हो जाते हैं। इस कारण कई बार बाइक संभालने में दिक्कत हो सकती है।

हवा के झोंके और संतुलन : आंधी या तेज हवा के दौरान बाइक का बैलेंस सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। हल्की बाइक या कम स्पीड पर चल रही बाइक हवा के झोंकों से आसानी से डगमगा सकती है। ऐसे में चालक को शरीर का वजन संतुलित रखकर और हैंडल पर मजबूत पकड़ बनाकर चलना चाहिए।

धुंधला दिखना : गर्मी और आंधी के दौरान सड़क पर धूल बहुत बढ़ जाती है, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। इससे सामने का ट्रैफिक और गड्ढे देर से दिखते हैं, जो अचानक टक्कर का कारण बन सकते हैं। ऐसे में स्पीड कंट्रोल और दूरी बनाए रखना जरूरी है। तेज गति से बाइक चलाने से बचें।

बाइक की पहले से जांच जरूरी : लंबी दूरी की यात्रा करने से पहले टायर प्रेशर, ब्रेक, इंजन ऑयल और लाइट्स की जांच जरूर करनी चाहिए, ताकि रास्ते में कोई तकनीकी समस्या न आए।

कौन सा हेलमेट बेहतर : बदलते मौसम में हेलमेट जरूरी सुरक्षा कवच है, जो धूप, गर्म हवा, बारिश और धूल से बचाता है। पूरे चेहरे और सिर को कवर करने वाला हेलमेट ज्यादा सुरक्षित होता है।

हमेशा आईएसआई मार्का और भरोसेमंद ब्रांड का हेलमेट ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सस्ते या बिना ब्रांड वाले हेलमेट पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पाते और गंभीर चोट का कारण बन सकते हैं।

- **सिद्धार्थ मिश्रा**

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। पिता की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। यात्रा लाभप्रद रहेगी।

वृष : धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। संयत रहें। किसी राजनेता से भेंट हो सकती है। कारोबार में बदलाव हो सकता है। पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है।

मिथुन : कारोबारी कार्यों के प्रति रुझान बढ़ सकता है। कारोबार से आय में वृद्धि होगी, परंतु खर्च भी बढ़ सकते हैं। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है।

कर्क : पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। परीक्षा और साक्षात्कार आदि कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है।

सिंह : शैक्षिक कार्यों के प्रति सचेत रहें। कठिनाइयां आ सकती हैं। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। तरक्की के अवसर भी मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी।

कन्या : कारोबार में वृद्धि होगी। किसी मित्र का सहयोग भी मिल सकता है। सु-स्वादु खान-पान में रुचि बढ़ेगी। परिवार में सुख-शांति रहेगी। सेहत का ध्यान रखें।

तुला : शैक्षिक कार्यों के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। किसी मित्र का सहयोग भी मिल सकता है। कारोबार के लिए यात्रा से कारोबार में वृद्धि हो सकती है।

वृश्चिक : धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में लाभ में कमी आ सकती है। सचेत रहें।

धनु : घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भवन की साज-सज्जा एवं रख-रखाव पर खर्च बढ़ सकते हैं। रहन-सहन कष्टमय हो सकता है। सेहत का भी ध्यान रखें।

मकर : लेखनादि बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। आय के साधन बनेंगे। मित्र से कारोबार का प्रस्ताव मिल सकता है। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे।

कुंभ : नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा, परंतु कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा। रहन-सहन अव्यवस्थित हो सकता है।

मीन : आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। शैक्षिक व बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान प्राप्ति होगा। बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

13 जून, शनिवार, **शक संवत्** : 23 ज्येष्ठ (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग** : 30 ज्येष्ठ मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम** : 26 जिल्हिजा, 1447 **विक्रमी संवत्**: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी तिथि सायं 04.08 मिनट तक पश्चात चतुर्दशी तिथि, कृतिका नक्षत्र रात्रि 01.17 मिनट तक, सुकर्मा योग सायं 05.29 मिनट तक पश्चात धृति योग, चंद्रमा मेष राशि में प्रातः 09.26 मिनट तक उपरांत वृष राशि में।

सूर्य उत्तरायण। ग्रीष्म ऋतु। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। मास शिवरात्रि व्रत।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

कृपया यह बताएं कि विवाह योग्य कन्या को वायव्य दिशा में क्यों सुलाना चाहिए?

–अमृता शर्मा, कानपुर

- वायव्य दिशा नए संबंधों को प्रोत्साहित करती है और सामाजिक संपर्कों को बढ़ाती है।
- यह दिशा लोगों से संवाद भी बढ़ाती है। इस दिशा में यदि कन्या सोती है, तो उसके नए घर में जाने की संभावना बढ़ती है।
- इस दिशा में सोने से विवाह प्रस्ताव ज्यादा आते हैं और बातचीत चलती है।
- इस बात का ध्यान रखें कि इस दिशा में पीला रंग न हो, वरना विवाह में विलंब हो सकता है। इस दिशा को और अधिक सक्रिय करने के लिए यहां पर गंगाजल रखें।

वर्ग पहेली : 8358

■	1	2			■	3	■	4
5	■		■	■	6			
7				■	■		■	
	■		■	8	■	■	9	
	■	10				11	■	
12		■	■		■		■	
	■	13	■	■	14			
15				■	■		■	
	■		■	16				■

ऊपर से नीचे
2. अधिकता; ज्यादा (5)
3. चलाने वाला (3)
4. उपेक्षा करना; बिल्कुल भूल जाना; विस्मरण करना (2,1,2,3)
5. थोक मूल्यों के स्तर में परिवर्तन का सूचकांक (2,2,4)
8. प्रशिक्षित तथा योग्य; अच्छा; चतुर; दक्ष; प्रवीण; श्रेष्ठ; होशियार (3)
11. झुकने वाला; लचीला (5)
13. अभिधार्थ; अभिधेय; चीज; वस्तु (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

बाएं से दाएं
1. दबाने के लिए प्रवृत्त करना; दबाने का काम करवाना (4)
6. उथल-पुथल; खलबली; घबराहट से होने वाली दौड़धूप; भगदड़; शोर-गुल (4)
7. ईश्वर; विधाता; कर्ता; गृहपति (4)
9. अलौकिक लगने वाला कृत्य; इंद्रजाल; तिलिस्म; बाजीगरी; वशीकरण; हाथ की सफाई का काम (2)
10. तमाशा देखने वाला (5)
12. एकांत; खाली; निर्जन; रिक्त; शून्य (2)
14. दिवाकर; भास्कर; सूर्य; आक; मदार (4)
15. कंटीला; कांटे वाला; कांटों सहित (4)
16. एक के स्थान पर दूसरी वस्तु देना; परिवर्तित करना; परिवर्तित होना (4)

वर्ग पहेली : 8357

1 का	■	2 सा	■	3 च	ट	4 का	ना	■
5 म	ला	ई	दा	र	■	न	■	6 स
धा	■	स	■	7 वा	दा	क	र	ना
8 म	त	■	■	हा	■	र	■	त
न	■	9 छ	ल्ला	■	10 खा	ना	■	न
क	■	ल	■	11 ना	■	■	12 को	प
13 र	द्द	क	र	ना	■	14 न	■	रं
ना	■	प	■	15 का	र्य	क	ला	प
■	16 न	ट	व	र	■	ली	■	रा

सुडोकू : 8340

*मध्यम

6				1	7	4		3
	4		6				8	
3					4			
1		3					6	
4								2
	9					5		1
			1					8
	7				5		9	
2		9	7	8				4

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8339

5	1	6	7	3	4	8	2	9
9	7	2	6	1	8	3	4	5
3	4	8	5	2	9	6	7	1
2	6	9	4	7	1	5	3	8
4	5	1	3	8	6	2	9	7
8	3	7	2	9	5	1	6	4
1	8	3	9	6	7	4	5	2
7	2	4	1	5	3	9	8	6
6	9	5	8	4	2	7	1	3

प्रेरणा

अच्छा स्वभाव ही असली शान है, यह दूसरों के दिलों को भी जीतता है। **-जॉन मिल्टन**

संपादकीय

देश में आय के अनुपात में बहुत महंगा है पेट्रोल

देश की प्रति-व्यक्ति आय 7.70 डॉलर प्रति दिन है, जबकि यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान, चीन, रूस और ब्राजील की इससे क्रमशः 33.6, 21.7, 23.2, 18.8, 12.7, 5.3, 6.6 और 4.4 गुना ज्यादा है। जहां यूएस में एक व्यक्ति को हर माह 40 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए अपनी आय का 0.6% देना होता है, वहीं यूरोप के देशों को औसतन 1.1 से 1.8% तक, जबकि रूस, चीन और ब्राजील में क्रमशः 2.3, 4.0 और 5.0%। भारत में उतना ही पेट्रोल खरीदने के लिए एक व्यक्ति को अपनी आय का 17.6% देना पड़ता है। एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पेट्रोल वेबसाइट के आंकड़े बताते हैं कि विगत 25 मई तक भारत में पेट्रोल 1.13 लीटर प्रति डॉलर था। इस पैमाने पर पड़ोसी भूटान और श्रीलंका में भी पेट्रोल सस्ता है। वहीं इसके उलट बेहद गरीब अफ्रीकी देशों में एक दिन की आय से एक लीटर पेट्रोल भी खरीदना मुश्किल है। जबकि उत्तरी अफ्रीका के ही लीबिया में एक व्यक्ति रोज की आय से 789 लीटर पेट्रोल खरीद सकता है। लगभग यही स्थिति अन्य पेट्रोल उत्पादक अरब देशों की भी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के 158 देशों में पेट्रोल और डीजल अफोर्डेबिलिटी के पैमाने पर क्रमशः 121वें और 118वें स्थान पर है। भारत में पेट्रोल की मूल कीमत का लगभग आधा केंद्र और राज्य के टैक्स के रूप होने से कीमतें बढ़ जाती हैं (हालांकि यह जीएसटी से बाहर है)। यूएस में मात्र 15-20% टैक्स है, जबकि पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी यह 25-40% ही है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता

humarehanuman@gmail.com

क्षमा की दाल और धैर्य की रोटी हाजमा नहीं बिगाड़ती है

हमारे देश में भोजन के लिए दो प्रतिनिधि शब्द हैं- दाल-रोटी। इसमें समूचा भोजन समा जाता है। कहते हैं पाचन के लिए सबसे सुविधाजनक भोजन यही है। बाकी डिश तो फिर इनका विस्तार हैं। पाचन-शक्ति अच्छी होनी भी चाहिए। अब हम एक भोजन और करने लगे हैं आजकल, और वह है क्रोध। कम लोग जानते हैं कि क्रोध का असर मन ही नहीं, पाचन स्तर पर भी होता है। क्रोध से न्यूरो-हार्मोनल सिस्टम तो आहत होता ही है, पेट भी खराब हो सकता है। जब कभी क्रोध आए तो विचार करना इसके पीछे अनुशासन है या अहंकार। क्रोध को लेकर अपनी इमेज-मेकिंग न करें। कभी-कभी क्रोध करने वाले को लगता है मेरी ऊंचाई अधिक होगी, लोग मुझे पहचानेंगे, मैं अलग चरित्र बन जाऊंगा। ऐसा न किया जाए। क्रोध पूरे जीवन को आहत करता है और जीवन से बड़ा कुछ होता नहीं है। क्रोध गिराना हो तो डाइजेशन सिस्टम अच्छा रखें। भोजन के रूप में क्षमा दाल है और धैर्य रोटी है। यह दाल-रोटी खाते रहें तो क्रोध हाजमा नहीं बिगाड़ेगा। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

शब्दों का जादू

प्रेम का अनायास

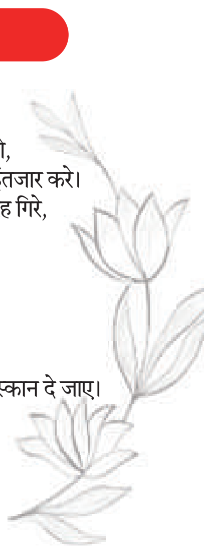

प्रेम वो नहीं जो घड़ी की सुइयों का मोहताज हो,
जो हर रोज खिड़की पर टिककर डाकिये का इंतजार करे।
प्रेम तो वो है, जो बारिश की पहली बूंद की तरह गिरे,
बिना बताए, बिना पूछे।

जैसे किचन में पकती रोटी की महक
अचानक भूख का एहसास जगा दे,
या जैसे एक पुरानी किताब के पन्नों में
मिला कोई भूला खत, जो दिल को बेखबर मुस्कान दे जाए।

इंतजार में बंधा प्रेम
आम के पेड़ पर पतझड़-सा ठहर जाता है,
पर जो अनायास आए,
वो आम्र मंजरी की मीठी खुशबू बनकर
हर सांस में उतर जाता है।

जैसे चौक पर लगने वाला मेला,
जहां हर मोड़ पर नया रहस्य हो,
या जैसे रात की ठंडी चादर में
किसी दूर की ट्रेन की सीटी,
जो अचानक भीतर का सन्नाटा तोड़ दे।

-आतिश कुमार, लखनऊ
(मूल कविता के सम्पादित अंश)

पूरी कविता को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

भास्कर कविता उत्सव की शीर्ष 100 कविताओं में चयनित

पाठकों के पत्र

मजदूरों की मौतें रुकें

सूरत में सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान दम घुटने से चार मजदूरों की मौत हो गई है। संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 400 से अधिक ऐसी मौतें हुई हैं। इस दिशा में बचाव के उपाय करने चाहिए, अन्यथा ये हादसे होते रहेंगे।
-हेमा हरि उपाध्याय, खाचरोद, मध्यप्रदेश

संवाद का अभाव एक संकट

तकनीकी विकास ने इंसान का दूसरे लोगों से बातचीत का दायरा कम कर दिया है। स्मार्ट फोन, इंटरनेट वगैरह इसका कारण हैं। ब्रिटेन में तो 'नेशनल कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट' के तहत लोगों को एक खास समय पर परिवार और पड़ोसियों के बातचीत के लिए प्रेरित किया जा रहा है। **-लाभ सिंह शेरगिल,** संगरूर, पंजाब

आप अपने पत्र editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं

क्या आप जानते हैं

होंडुरास में होती है मछलियों की बरसात

उत्तरी अमेरिकी देश होंडुरास के योरो कस्बे में लगभग हर साल जबरदस्त तूफानों के बाद मछलियां बरसने की अनोखी घटना होती है। वैज्ञानिकों का एक मत है कि बड़े समुद्री चक्रवातों में ऊपर उठी मछलियां नीचे गिरती हैं। दूसरी थ्योरी कहती है कि सब-टैरेनियन नदी तंत्र में अत्यधिक दबाव से मछलियां जमीन फाड़ कर बाहर निकलती हैं।
1860 में सबसे पहले यह घटना दर्ज की गई थी।

विशेष • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'संकल्प से सिद्धि' का यह गौरवशाली कालखंड रहा है

विकसित भारत एक नारा नहीं संकल्प है

अमृतकाल

नितिन नवीन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने विश्वास, विकास और जनकल्याण को समर्पित अपने 12 वर्ष पूर्ण किए हैं। 'संकल्प से सिद्धि' का यह गौरवशाली कालखंड भारत के विकास, सुरक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण और वैश्विक प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि का साक्षी रहा है। कांग्रेस देश को अनिश्चितता, भ्रष्टाचार और कमजोर नेतृत्व की विरासत देकर गई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को आत्मविश्वास, सुशासन और विकास की नई पहचान दी है। कांग्रेस के लिए राजनीति का मतलब वर्षों तक परिवार की विरासत को बचाना रहा, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के लिए राजनीति- 'परिवार नहीं राष्ट्र प्रथम' और 'सत्ता नहीं सेवा प्रथम' का मार्ग रही है।

यदि हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के इतिहास को देखें, तो उनकी सफलता के पीछे जो एक मूलमंत्र नजर आता है, वह है उस राष्ट्र का 'सामूहिक स्वप्न'। भारत के संदर्भ में, वर्ष 2014 में पहली बार 140 करोड़ की विशाल जनता को सामूहिक चेतना के एक सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री मोदी ने किया। देश को पहला ऐसा नेतृत्व मिला है, जो एक 'प्रधान सेवक' के भाव से 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के महा-संकल्प को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री ने पहले राष्ट्र को एक 'सामूहिक सोच' दी, फिर जन-विश्वास के बल पर उस सोच को 'सामूहिक संकल्प' में बदला, और आज वही संकल्प 'विकसित भारत' के रूप में 'सामूहिक स्वप्न' का रूप ले चुका है।

इस महापरिवर्तन की शुरुआत बुनियादी ढांचे की अभूतपूर्व क्रांति से हुई। 2014 से पहले देश बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा था। आज जमीनी स्तर पर बदलाव का परिणाम है कि 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने, 100% विद्युतीकरण हुआ, एक्सप्रेस-वे नेटवर्क 7 गुना बढ़ा और एयरपोर्ट्स 74 से 160 से अधिक हो गए। यह कालखंड मानसिक गुलामी से मुक्ति और वास्तविक 'डी-कलोनाइजेशन' का साक्षी है। लोक कल्याण मार्ग, कर्तव्य पथ और सेवा तीर्थ का नामकरण और योग का वैश्विक प्रसार इसका प्रमाण है। एक समय था जब देश के शीर्ष नेतृत्व ने तत्कालीन 54 करोड़ की आबादी को बोझ माना था, पर आज प्रधानमंत्री मानते हैं कि यही 140 करोड़ देशवासी भारत के विकास की गाथा की सबसे मजबूत कड़ी हैं। इसी सोच ने धारा 370 को हमेशा के लिए निरस्त किया। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई गई। कोरोना काल में 220 करोड़ से अधिक मुफ्त वैक्सीन डोज और 'वैक्सीन मैत्री' ने वैश्विक स्तर पर भारत की क्षमता का परिचय दिया।

आज का युवा 'जॉब सीकर' नहीं, बल्कि 'जॉब गिवर' बन रहा है। 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स और 125 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स के साथ भारत मैनपावर से 'मैन्युफैक्चरिंग पावर' की ओर बढ़ रहा है। इसी प्रकार, देश 'वीमेन डेवलपमेंट' से आगे बढ़कर 'वीमेन लेड डेवलपमेंट' का साक्षी बन रहा है, जहां 3 करोड़ से अधिक 'लखपति दीदी' और सुरक्षा बलों में महिला अधिकारियों की 4 गुना वृद्धि नारीशक्ति के स्वावलंबन को दर्शाती है। मोदी सरकार ने मातृशक्ति को सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान और हिस्सेदारी देने में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

गरीब कल्याण के क्षेत्र में, विभिन्न योजनाओं ने वंचितों के 'विशियस साइकिल' (दुष्चक्र) को 'वर्चुअस साइकिल' (गुणात्मक चक्र) में बदल दिया है, जिससे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 4 करोड़ पक्के घर, 60 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान कवच और पीएम मुद्रा योजना के तहत 40 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल-फ्री लोन इसका आधार बना। डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में, '1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसे पहुंचने' के पुराने दौर को समाप्त कर डीबीटी के माध्यम से 51 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजे गए। जनधन-आधार-मोबाइल (जैम) ट्रिनिटी और यूपीआई के माध्यम से आज ₹314 लाख करोड़ का वार्षिक डिजिटल लेनदेन हो रहा है, जो वैश्विक स्तर पर 49% है। प्रकृति के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए भारत ने स्वच्छ भारत अभियान, एक पेड़ मां के नाम और सोलर कैपेसिटी को 2.6 जीडब्ल्यू से 110+ जीडब्ल्यू तक पहुंचाकर ग्रीन अर्थ के संकल्प को सिद्ध किया है।

प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में आज देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। कभी देश के अंतिम गांव कहे जाने वाले ये क्षेत्र आज भारत के प्रथम गांव के रूप में नई पहचान पा चुके हैं। इसके साथ ही, आज भारत की सैन्य क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और हमारी सेनाएं अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित हैं। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल महालोक का जीर्णोद्धार हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की उस सभ्यतागत चेतना का पुनर्जागरण है, जो विकास भी, विरासत भी के मूलमंत्र को पूरी सार्थकता से साकार कर रहा है।

पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश का सोचने का ट्रेंड भी बदला है। आज नए भारत का मिजाज ऐसा है, जहां आंत्रप्रेन्योर बनना एक ट्रेंड है, कड़ी मेहनत करना एक ट्रेंड है, और वोकल फॉर लोकल से लेकर मेक इन इंडिया को अपनाना हर नागरिक का मूलमंत्र बन चुका है। यह ऐसा दौर है, जहां तीव्र विकास के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना एक ट्रेंड है। आज देश में स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक नया उभार दिख रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, 'नेशन फर्स्ट' के भाव के साथ, एक सामूहिक संकल्प के साथ काम करना देश का ट्रेंड बन चुका है। इन तमाम सकारात्मक बदलावों के पीछे प्रधानमंत्री की भूमिका एक ट्रेंडसेटर की रही है, जिन्होंने इनके माध्यम से आज पूरे देश को एकता के एक मजबूत सूत्र में पिरो दिया है। आज भारत न केवल आंतरिक रूप से सशक्त हो रहा है, बल्कि वैश्विक पटल पर भी एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। जब प्रधानमंत्री को विश्व के 32 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त होता है, तो यह वास्तव में सनातन भारतीय सोच और 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का सम्मान है। यही कारण है कि आज विकसित भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसे देशवासियों ने अटूट विश्वास और संकल्पित भाव से आत्मसात किया है।

भारत का सामूहिक स्वप्न...

सरकार के ये 12 वर्ष जहां सेवा, सुशासन और जन-आकांक्षाओं की पूर्ति के रहे हैं, वहीं अगले 21 वर्ष विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की यात्रा होंगे। इस अमृतकाल में सभी देशवासी मिलकर एक सशक्त, समृद्ध, सुरक्षित, स्वावलंबी, समर्थ और समरस भारत के सामूहिक स्वप्न' को अवश्य साकार करेंगे।

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

दूरदृष्टि • हम इस नई वास्तविकता को स्वीकारें

यूएस को अपना रणनीतिक साझेदार समझना भूल होगी

भू-राजनीति

ब्रह्मा चेलानी

पॉलिसी फॉर सेंटर रिसर्च के प्रोफेसर एमेरिटस

भारत की अपनी हालिया यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत को अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया, लेकिन साझेदारी की यह परिचित भाषा अब दिन-ब-दिन खोखली लगती जा रही है। ट्रम्प के बयानों और टैरिफों के भारत-अमेरिका संबंधों पर पड़े प्रभावों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन द्विपक्षीय संबंध ट्रम्प के व्हाइट हाउस में लौटने से बहुत पहले से ही दबाव में थे। हाल के वर्षों में, जैसे-जैसे चीन के बढ़ते रणनीतिक दायरे से भारत की क्षेत्रीय स्थिति कमजोर हुई है, वहीं अमेरिका ने भी दक्षिण एशिया क्षेत्र में ऐसी नीतियां अपनाई हैं, जिन्होंने भारतीय हितों को नजरअंदाज किया है- और कभी-कभी तो वे सीधे तौर पर उनके विपरीत रही हैं।

बांग्लादेश इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। 2024 में शेख हसीना के पलायन के बाद अमेरिका ने शासन-परिवर्तन का समर्थन किया। लेकिन भारत जानता था कि इससे गंभीर खतरे पैदा होंगे, जो कि हुए भी। फिर म्यांमार है। 2021 में सेना द्वारा वहां की नागरिक सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद से ही अमेरिका ने सैन्य-सत्ता के प्रति दंडात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा है, जिसमें कड़े प्रतिबंध और विद्रोही समूहों के लिए सैन्य सहायता शामिल है, बावजूद इसके कि इसने भारत की संवेदनशील उत्तर-पूर्वी सीमा पर सुरक्षा जोखिम पैदा किए हैं। विगत मार्च में ही एक अमेरिकी नागरिक को छह यूक्रेनी नागरिकों के साथ कथित तौर पर बिना परमिट के पूर्वोत्तर में प्रवेश करने और ड्रोन युद्ध के लिए सत्ता-विरोधी लड़ाकों को प्रशिक्षित और सशस्त्र करने के लिए म्यांमार में घुसने के आरोप में भारत में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका ने नेपाल को भी अपनी भारत-नीति के हिस्से के रूप में देखने के बजाय रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में देखना शुरू कर दिया है। हाल के वर्षों में, उच्च-स्तरीय अमेरिकी अधिकारियों ने काठमांडू का दौरा कई बार किया है, नई दिल्ली में रुके बिना, जैसी अतीत में परम्परा रही थी।

ट्रम्प ने हालात को और बदतर बना दिया है, खासकर पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों को आगे बढ़ाकर। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान आतंकवादी समूहों की सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है और साथ ही उन्हें सैन्य और खुफिया सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए है। ट्रम्प के परिवार के सदस्यों और व्यापारिक सहयोगियों ने इसके बावजूद वहां मुनाफे के सौदे किए हैं। अमेरिका ने तो अब चीन के प्रति भी सुलहभरा, उदार दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर दिया है। हालांकि दोनों महाशक्तियों में सामरिक प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ट्रम्प के हालिया समझौतों ने काफी अनिश्चितता पैदा कर दी है- खासकर भारत के लिए।

जहां अमेरिका लंबे समय से भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक ढाल के रूप में देखता रहा है, वहीं वह भारत के क्षेत्रीय प्रभुत्व के विचार से भी हिचकिचाता है। जैसा कि अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री समीर पॉल कपूर ने फरवरी में कहा था, अमेरिका किसी भी एक शक्ति को दक्षिण एशिया में बहुत अधिक प्रभाव हासिल करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। कपूर की टिप्पणियां ट्रम्प प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस) की ही प्रतिध्वनि थीं, जिसके अनुसार अमेरिका किसी भी राष्ट्र को इतना प्रभुत्वशाली बनने की अनुमति नहीं दे सकता कि वह अमेरिकी हितों को खतरे में डाल सके।

अमेरिका साफ कहता है कि हम भारत के साथ वही गलतियां नहीं करने जा रहे हैं, जो 20 साल पहले चीन के साथ की थीं। संदेश स्पष्ट है : अमेरिका अब भारत को रणनीतिक भागीदार कम और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी ज्यादा मानता है।

अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडाउ ने हाल ही में नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान कहा कि हम भारत के साथ वही गलतियां नहीं करने जा रहे हैं, जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थीं। संदेश स्पष्ट है : अमेरिका अब भारत को रणनीतिक भागीदार कम और एक क्षेत्रीय व आर्थिक प्रतिद्वंद्वी ज्यादा मानता है, जिसे रोकना है। हमें इस नई वास्तविकता के अनुकूल ढलना होगा, जो हमारी रणनीतिक सोच में एक मौलिक बदलाव की मांग करती है। **(@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)**

नजरिया • हम अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं...

कोर्ट में एआई के असुरक्षित इस्तेमाल से मुश्किलें बढ़ेंगी

कृत्रिम मेधा

विराग गुप्ता

सुप्रीम कोर्ट के वकील

viraggupta@hotmail.com

अदालतों में एआई के इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नियमों का मसौदा जारी किया है। लेकिन मुकदमों के बोझ से दबी अदालतों में एआई के तदर्थ इस्तेमाल से मुश्किलें और विवाद बढ़ सकते हैं। इनसे जुड़े 4 पहलुओं को समझना जरूरी है :

1. संविधान के अनुच्छेद-145 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को नियम बनाने का अधिकार है। उसके तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 को मंजूरी दी थी। लेकिन एआई के मसौदे में यह नहीं लिखा कि किस कानून के अनुसार इन्हें बनाया गया है। जिला अदालतें राज्यों के हाई कोर्ट के अधीन हैं। लेकिन हाईकोर्टों को सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं माना जाता है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन से बड़े पैमाने पर न्यायिक सुधार हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट न्यायिक आदेश जारी नहीं कर रहा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक आदेश से हाईकोर्टों और जिला अदालतों में एआई लागू करने से संवैधानिक संकट की स्थिति बन सकती है।

2. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार एआई को कानूनी मान्यता नहीं है। इसलिए एडवोकेट्स एक्ट के तहत एआई से बनाई गई किसी भी गलत सामग्री के लिए वकील ही जिम्मेदार होंगे। भारत में अभी तक डेटा सुरक्षा कानून और उससे जुड़े नियम लागू नहीं हैं। लंबित और पुराने मामलों में करोड़ों लोगों के संवेदनशील न्यायिक और निजी डेटा का एआई के माध्यम से व्यावसायिक इस्तेमाल असंवैधानिक होगा। इससे पहले वादकारियों और वकीलों की सहमति जरूरी है। अनेक जज एआई के दुरुपयोग से बढ़ रही अराजकता के खिलाफ चिंता जाहिर कर चुके हैं। पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी जिला अदालतों को आदेश दिया है कि एआई प्लेटफॉर्मों का कानूनी रिसर्च और न्यायिक फैसलों में इस्तेमाल नहीं हो सकता।

3. कोरोना के दौरान अदालतों में आनन-फानन में ऑनलाइन सुनवाई और मुकदमों का सीधा प्रसारण शुरू हो गया था। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के फैसले के अनुसार अभी तक नियमों में जरूरी बदलाव नहीं हुए। न्यायिक सुनवाई के डेटा के व्यावसायिक इस्तेमाल को रोकने के लिए स्पष्ट नियमों के अभाव से न्यायिक प्रशासन पर हमले बढ़ रहे हैं। अदालतों में वॉट्सएप, जूम और यू-ट्यूब जैसे विदेशी प्लेटफॉर्मों के असुरक्षित इस्तेमाल के खिलाफ संघ विचारक केएन गोविन्दाचार्य ने याचिका दायर की थी। चीफ जस्टिस चन्द्रचूड़ ने कहा था दो साल के भीतर स्वदेशी टेक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा। लेकिन अभी तक अमल नहीं हुआ।

4. एआई के सभी बड़े प्लेटफॉर्म विदेशी हैं। भारत की बैंकिंग प्रणाली को माइथोस जैसी एआई की सुनामी से बचाने के लिए वित्त मंत्री चिंताग्रस्त हैं। एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए आईटी एक्ट में भी स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं। मसौदे में डेटा की सुरक्षा और शिकायत निवारण के जरूरी प्रावधान नहीं होने से जिला अदालतों में वकील और जजों की उलझनें बढ़ सकती हैं। प्रधानमंत्री ने तकनीक और एआई के इस्तेमाल से गरीब कैदियों की रिहाई और मुकदमों के बोझ से मुक्ति का आह्वान किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मसौदे में एआई के माध्यम से न्यायिक सुधार, छोटे मुकदमों के जल्द निस्तारण और आम जनता को जल्द न्याय देने का रोडमैप नहीं है। जिला अदालतों में पानी, शौचालय और बैठने की बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। फिर एआई के लिए इन्फ्रा कैसे विकसित होगा?

अभी तक डेटा सुरक्षा कानून और उससे जुड़े नियम ही लागू नहीं हुए हैं। लंबित और पुराने मामलों में करोड़ों लोगों के संवेदनशील न्यायिक और निजी डेटा का एआई के माध्यम से व्यावसायिक इस्तेमाल असंवैधानिक होगा।

एआई के संस्थागत इस्तेमाल के लिए न्यायिक व्यवस्था से जुड़े पांचों स्तम्भों- जनता, सरकार, न्यायिक प्रशासन, वकील और जजों के साथ परामर्श जरूरी है। उसके अनुसार ही संसद से कानून बने और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्टों के नियमों में बदलाव हो।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

डिफ्रेंट एंगल • हम 3 बड़ी गलतियां कर रहे हैं, जबकि हमें दर्शक नहीं समाधान के भागीदार बनना होगा

आज दुनिया को सबसे अधिक आवश्यकता क्लाइमेट सत्याग्रह की है

पर्यावरण

प्रो. चेतन सिंह सोलंकी

आईआईटी बॉम्बे के पूर्व प्रोफेसर

chetanss@gmail.com

देश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। जब मैं लोगों से पूछता हूं कि अगले वर्ष गर्मी कम होगी या ज्यादा, तो अधिकांश लोग कुछ पल सोचने के बाद कहते हैं- शायद और ज्यादा। यह उत्तर केवल अनुमान नहीं, एक कठोर सच्चाई है। पृथ्वी पहले से कहीं अधिक तेजी से गर्म हो रही है। इसलिए यह मान लेना कि अगले साल स्थिति अपने आप सुधर जाएगी, स्वयं को भ्रम में रखने जैसा है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आज हम ऐसा क्या करें जिससे आने वाला समय और भयावह न बने। दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी विकास, नई नीतियों और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों पर लगातार काम हो रहा है। इसके बावजूद जलवायु संकट हमारी आंखों के सामने तेजी से बढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि समस्या कहीं अधिक गहरी है। मुझे लगता है कि मानव समाज इस विषय में तीन मूलभूत गलतियां कर रहा है।

पहली गलती यह है कि हम प्रकृति के संसाधनों- कोयला, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस को अपनी पूंजी समझ बैठे हैं। किसी व्यवसाय में यदि आप अपनी पूंजी को ही खर्च करना शुरू कर दें, तो वह अधिक समय तक नहीं चल सकता। प्रसिद्ध पुस्तक \'स्मॉल इज ब्यूटीफुल' में ईएफ शूमाकर ने 1973 में ही चेतावनी दी थी कि मानव-समाज पृथ्वी की प्राकृतिक पूंजी को अपनी आय की तरह खर्च कर रहा है। विज्ञान, तकनीक और मशीनें हमने बनाई हैं, उनका उपयोग करना उचित है। लेकिन करोड़ों वर्षों में बने जीवाश्म ईंधन हमने नहीं बनाए। वे प्रकृति की पूंजी हैं। यदि हम उसी पूंजी को लगातार जलाते रहेंगे, तो दिवालियापन निश्चित है।

दूसरी गलती यह है कि हम मानकर चल रहे हैं कि हमारे उत्पादन और उपभोग में बढ़ोतरी अनंत काल तक चल सकती है। विज्ञान बढ़ रहा है, तकनीक बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन पृथ्वी नहीं बढ़ रही। उसके संसाधन सीमित हैं। सीमित पृथ्वी पर असीमित उपभोग कभी संभव नहीं हो सकता। लेकिन हमने विकास की पूरी परिभाषा ही अधिक उत्पादन और अधिक उपभोग पर आधारित कर दी है।

तीसरी और शायद सबसे बड़ी गलती यह है कि हम मानते हैं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की समस्या को सरकारें हल कर देंगी। वास्तविकता यह है कि यह समस्या किसी एक सरकार या उद्योग ने नहीं खड़ी की है। इसे हम सभी ने मिलकर बनाया है। हम जो पहनते हैं, खाते हैं, खरीदते हैं, जितनी बिजली उपयोग करते हैं, जितना यात्रा करते हैं- इन सबका सीधा संबंध कार्बन उत्सर्जन से है। इसलिए समाधान भी केवल सरकारों से नहीं आएगा। जब तक व्यक्ति स्वयं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक कोई नीति पर्याप्त नहीं होगी।

इसीलिए मुझे लगता है कि आज दुनिया को सबसे अधिक आवश्यकता क्लाइमेट सत्याग्रह की है। सत्याग्रह का अर्थ केवल विरोध नहीं, बल्कि सत्य पर आग्रह है। आज का सबसे बड़ा सत्य यह है कि पृथ्वी सीमित है, इसलिए हमारा जीवन और उपभोग भी सीमित होना चाहिए। क्लाइमेट सत्याग्रह का अर्थ है स्वेच्छा से सीमित और जिम्मेदार जीवन अपनाना; अपनी जरूरत और लालच के बीच अंतर समझना; और प्रकृति के संसाधनों का उपयोग अधिकार नहीं, जिम्मेदारी की तरह करना।

यदि हम क्लाइमेट सत्याग्रह अपनाते हैं, तो यह हमारी तीनों गलतियों का समाधान बन सकता है। यह हमें असीमित उपभोग की दौड़ से बाहर निकालकर संतुलित जीवन की ओर ले जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, यह लोगों को दर्शक नहीं बल्कि समाधान का भागीदार बनाएगा। अब समय केवल चर्चा का नहीं, व्यक्तिगत जिम्मेदारी का है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

दो इंडस्ट्री में बड़ी जंग ऑटो इंडस्ट्री में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की जंग, तो क्विक कॉमर्स में अमेजन, फ्लिपकार्ट के उतरने से ब्लिंकिट, स्विगी की चुनौती बढ़ी

ऑटोः 6 बड़ी कार कंपनियां दे रहीं 3.5 लाख तक डिस्काउंट, ईवी पर सर्वाधिक

समर सीजन के आखिर में बिक्री बढ़ाने की होड़

भास्कर न्यूज | मुंबई

अगर आप नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह महीना मुफीद हो सकता है। जून में कार कंपनियां कई मॉडलों पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉरपोरेट बेनिफिट और स्क्रैपेज इंसेंटिव के रूप में ₹3.50 लाख तक बड़े ऑफर दे रही हैं। इनमें मारुति सुजुकी इंडिया, ह्युंडई मोटर इंडिया, टाटा मोटर्स, होंडा कार्स इंडिया, जीप और रेनॉ जैसी कंपनियां शामिल हैं।

समर सीजन के आखिर में कार कंपनियों का बिक्री बढ़ाने पर जोर है। इसके चलते छह बड़ी कंपनियां हैचबैक से लेकर एसयूवी और इलेक्ट्रिक व्हीकल तक हर सेगमेंट में कई तरह के बेनिफिट्स ऑफर कर रही हैं। सबसे ज्यादा बचत का मौका टाटा मोटर्स की ईवी रेंज में है। कर्व ईवी पर सभी ऑफर मिलाकर ₹3.50 लाख तक का फायदा मिल सकता है। मारुति की इनविक्टो पर ₹2.15 लाख और होंडा एलिवेट पर 2.15 लाख तक के ऑफर उपलब्ध हैं। इनमें से ज्यादातर ऑफर जून के आखिर तक मान्य हैं। डीलरशिप और शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं।

जून में 23 मॉडलों पर कम से कम ₹40 हजार के डिकाउंट/बेनिफिट्स

कंपनी	मॉडल	अधिकतम बेनिफिट
टाटा मोटर्स	ईवी-कर्व, हैरियर, नेक्सॉन, पंच, टियागो	₹3.50 लाख
मारुति सुज़ुकी	इनविक्टो, ग्रैंड वितारा, फ्रॉन्क्स, बैलेनो, विक्टोरिस	₹2.15 लाख
होंडा	एलिवेट, सिटी, अमेज	₹2.15 लाख
ह्युंडई	क्रेटा, एक्सटर, वेरना, आई20, ग्रैंड आई10	₹1.05 लाख
जीप	कम्पास, मेरिडियन	₹1.65 लाख
रेनॉ	काइगर, ट्रिबर, क्विड	₹40,000

नोटः ऑफर की राशि वेरिएंट, लोकेशन, डीलरशिप के मुताबिक अलग हो सकती है। स्रोतः कंपनियों की वेबसाइट्स, ऑटोकार इंडिया, गाड़ीवाड़ी डॉट कॉम

कारों के मास मॉडल पर डिस्काउंट देने में चार कंपनियां सबसे आगे

टाटा मोटर्सः ईवी रेंज पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट... कंपनी इस महीने कर्व ईवी पर सबसे ज्यादा 3.50 लाख रुपए तक का संयुक्त बेनिफिट दे रही है। इसके अलावा हैरियर, नेक्सॉन, पंच और टियागो के ईवी वेरिएंट पर भी अलग-अलग ऑफर उपलब्ध हैं। इसमें कैश डिस्काउंट के साथ ही एक्सचेंज बोनस और अन्य इंसेंटिव भी शामिल हैं।

मारुति सुज़ुकीः नेक्सा और अरेना, दोनों में ऑफर ...मारुति की प्रीमियम नेक्सा रेंज और मास-मार्केट अरेना रेंज, दोनों में जून ऑफर लागू हैं। नेक्सा रेंज में इनविक्टो पर 2.15 लाख रुपए तक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसके अलावा ग्रैंड वितारा, फ्रॉन्क्स और बैलेनो पर डिस्काउंट के ऑफर हैं। अरेना रेंज में विक्टोरिस पर सबसे ज्यादा 90,000 रुपए तक के ऑफर हैं।

ह्युंडईः4 मॉडलों पर डिस्काउंट/बेनिफिट्स... ह्युंडई मोटर इंडिया सबसे ज्यादा 1.05 लाख रुपए का ऑफर क्रेटा के चुनिंदा वेरिएंट पर दे रही है। इसके अलावा कंपनी एक्सटर, वेरना, आई20 और ग्रैंड आई10 निओस जैसे मॉडलों पर भी चुनिंदा ऑफर दे रही है। इसमें कैश बेनिफिट के साथ ही एक्सचेंज बोनस और स्क्रैपेज इंसेंटिव भी शामिल है।

रेनॉः नए डिस्काउंट और विशेष ऑफर्स की घोषणा...रेनॉ इंडिया ने काइगर, ट्रिबर, क्विड जैसे मॉडलों पर 20-40 हजार रुपए तक डिस्काउंट की पेशकश की है। एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बोनस, कॉरपोरेट छूट, स्क्रैपेज लाभ शामिल करने पर कुल इंसेंटिव ज्यादा भी हो जाता है। हालांकि ये सभी ऑफर इस साल 15 जून तक के लिए ही हैं।

प्रीमियम रेंज

दो लाख से ज्यादा तक के ऑफर...

जीपः कम्पास और मेरिडियन मॉडलों पर 1.65 लाख रुपए तक के डिस्काउंट/बेनिफिट्स मिल रहे हैं। रैंगलर पर कोई डिस्काउंट नहीं हैं और ग्रैंड चेरोकी के लिए अगले साल तक इंतजार करना होगा।

होंडाः एलिवेट के अलग-अलग वेरिएंट पर इस महीने 2.15 लाख रुपए तक के डिस्काउंट मिल रहे हैं। इसके साथ ही कंपनी सिटी और अमेज सेडान पर भी कुछ ऑफर और बेनिफिट्स दे रही है।

क्विक-कॉमर्सः 6 कंपनियों के बीच ₹95 हजार करोड़ के बाजार में निर्णायक स्पर्धा

बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच स्विगी ने विस्तार रोका

भास्कर न्यूज | मुंबई

क्विक कॉमर्स सेक्टर में 6 कंपनियों के बीच निर्णायक जंग शुरू हो चुकी है। ब्लिंकिट, स्विगी, जेप्टो जैसे खिलाड़ियों के मैदान में अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गजों की एंट्री हो चुकी है। अमेजन इंडिया के वाइस प्रेसीडेंट के मुताबिक अमेजन नाउ 1,000 से ज्यादा सेंटर के जरिए 100 शहरों में सेवा देगी। अमेजननाउ का यह विस्तार 2,800 करोड़ रुपए के निवेश का हिस्सा है।' इनके आने से डार्क स्टोर्स और सप्लाई चेन की जंग आक्रामक हो गई है, जिससे मौजूदा प्लेयर्स पर मार्जिन का दबाव बढ़ेगा। असर भी दिखना शुरू हो गया। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में ब्लिंकिट की इस बाजार में हिस्सेदारी 54% थी, लेकिन डेटम इंटेलीजेंस के डेटा के मुताबिक अब 46% पर आ गई। ब्लिंकिट सीईओ अलबिंदर ढींसा पहले चेतावनी दे चुके हैं कि इस इंडस्ट्री में जल्द ही एक बड़ा 'शेकआउट' (कमजोर प्लेयर्स का बाहर होना) देखने को मिल सकता है। बर्नस्टीन के मुताबिक अब लड़ाई सिर्फ सबसे तेज डिलीवरी की नहीं है, यह कीमत, रेंज, विश्वसनीयता और मुनाफे के संतुलन की है।'

6,000 डार्क स्टोर, 95,500 करोड़ का बाजार, 75% ग्रोथ, पर ज्यादातर घाटे में

बाजार का आकार	सालाना ग्रोथ	कुल डार्क स्टोर
95,500 करोड़	75%+	6,000+

कंपनी	मार्केट शेयर	डार्क स्टोर	डेली ऑर्डर
ब्लिंकिट	46%	1,500+	₹10 लाख/दिन
स्विगी इंस्टामार्ट	24%	₹1,000	7-8 लाख/दिन
जेप्टो	22%	₹1,200	6-7 लाख/दिन
अमेजन नाउ	3-5%	500+	4.5-5 लाख/दिन
फ्लिपकार्ट मिनट्स	3-4%	800-1,000	10,000/स्टोर
बीबी नाउ	5-7%	₹700	टाटा इंटीग्रेटेड

स्रोतः डेटम इंटेलीजेंस, बीएनपी परिबास इक्विटी रिसर्च, बर्नस्टीन | *आंकड़े 2026 के

क्विक-कॉमर्स जंगः 5 दिग्गजों की आक्रामक रणनीतियां और वित्तीय रिपोर्ट

1. ब्लिंकिट (जोमैटो): स्केल और प्रीमियम साइज पर दांव...वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में कंपनी का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू (जीओवी) सालना आधारपर 134% बढ़कर 9,421 करोड़ रहा। कंपनी 1,500 से अधिक डार्क स्टोर्स के मजबूत नेटवर्क के साथ रोजाना 10 लाख ऑर्डर्स डिलीवर कर रही है। **रणनीतिक बढ़तः** बड़ी ताकत इसका प्रीमियम एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, जो साल 2026 में 709 पर पहुंच चुका है। यानी कंपनी सिर्फ ऑर्डर्स की संख्या नहीं, बल्कि बड़े टिकट साइज पर फोकस कर रही है।

2. स्विगीः विस्तार रोका, वित्तीय सेहत पर फोकस कंपनी ने मार्च तिमाही में महज 7 डार्क स्टोर जोड़े। इसके बावजूद, 4 तिमाहियों में यूनिट इकॉनॉमिक्स में 5-6 प्रतिशत अंक का सुधार। वित्त वर्ष 2026 में सालाना आधार पर 69% बढ़त के साथ जीओवी 7,881 करोड़। चौथी तिमाही 858 करोड़ का घाटा। **रणनीतिक बढ़तः** ताकत प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स जैसे शॉर्ट शेल्फ-लाइफ वाले पनीर और ताजी क्लॉटेड क्रीम हैं। सीईओ श्रीहर्ष माजेती का मानना है, होल फूड्स व वॉलमार्ट एक जैसी समस्या नहीं सुलझाते।

3. जेप्टोः आईपीओ से पहले सुधरती वित्तीय सेहत... वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू दोगुना बढ़ा, लेकिन शुद्ध घाटा भी बढ़कर 5,905.19 करोड़ पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2026 में जेप्टो का रेवेन्यू 22,624 करोड़ रहा। 1,139 डार्क स्टोर्स हैं। **रणनीतिक बढ़तः** कंपनी की दक्षता सुधरी है। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी से चौथी तिमाही के बीच प्रति ऑर्डर एडजस्टेड एबिटा घाटा 110 से ₹59/ऑर्डर पर आ गई है। जेप्टो कैफे और 10 मिनट फॉर्मेसी जैसे वर्टिकल्स ग्रॉसरी पर निर्भरता कम कर रहे हैं।

4. अमेजन व फ्लिपकार्टः हर माह 100 नए डार्क स्टोर अमेजन ने 'अमेजन नाउ' के लिए 2,800 करोड़, जबकि वॉलमार्ट समर्थित फ्लिपकार्ट ने 'फ्लिपकार्ट मिनट्स' के लिए 3,248 करोड़ लगाए। फ्लिपकार्ट मिनट्स हर महीने 100 नए डार्क स्टोर जोड़ रहा है। **रणनीतिक बढ़तः** अमेजन की ताकत 'प्राइम लॉयल्टी' है, जिसके आने के बाद ऑर्डर्स 3 गुना बढ़े। वहीं, फ्लिपकार्ट मिनट्स ग्रॉसरी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन को सीधे 10 मिनट में डिलीवर कर रहा है, जो एक पूरी तरह से अलग कैटेगरी गेम है।

भरोसा • विदेशी निवेशकों की 2.6 लाख करोड़ की निकासी के बीच घरेलू फंड्स का सपोर्ट

घरेलू संस्थाओं ने 5 महीने में खरीदे 4 लाख करोड़ के शेयर, 2025 में इन्होंने ₹7.75 लाख करोड़ लगाए थे

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने इस साल शुरुआती पांच महीनों में ₹4 लाख करोड़ से अधिक निवेश किया है। 2026 में निवेश का नया रिकॉर्ड बन सकता है। डीआईआई ने 2025 में रिकॉर्ड ₹7.75 लाख करोड़ और 2024 में ₹5.23 लाख करोड़ लगाए थे। इस साल अब तक विदेशी निवेशक ₹2.6 लाख करोड़ के भारतीय शेयर बेच चुके हैं। हर माह औसतन ₹30 हजार करोड़ के एसआईपी के दम पर घरेलू निवेश मजबूत है। डीआईआई ने मार्च में ईरान युद्ध की गिरावट के दौरान सबसे अधिक ₹1.4 लाख करोड़ लगाए।

डीआईआई ने इस मार्च में सबसे ज्यादा शेयर खरीदे

2026	खरीदारी (करोड़)
जनवरी	69,220.7
फरवरी	39,702.1
मार्च	1,39,096.4
अप्रैल	43,892.1
मई	82,668.9
जून*	33,933.1

इस साल अब तक कुल निवेश
₹4.08 लाख करोड़
* 8 जून तक के आंकड़े। स्रोतः एनएसई

रिटर्न की उम्मीदः कॉरपोरेट आय बढ़ने से बढ़ा इत्मिनान

कंपनियों की बेहतर कमाई, प्रमोटरों की सुधरती क्वालिटी से लिस्टेड कंपनियों का दायरा बढ़ रहा है। ईपीएफओ, एनपीएस और इंश्योरेंस आवंटन से बाजार को लगातार पूंजी मिल रही है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर के मुताबिक एसआईपी, एनपीएस के निरंतर प्रवाह ने विदेशी निवेशकों की बिकवाली के असर को सीमित कर रखा है।

बाजार में गिरावटः सेंसेक्स-निफ्टी का कमजोर प्रदर्शन

इस साल प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स में 13.7% और निफ्टी में 11.5% गिरावट आई है। व्यापक बाजार की स्थिति थोड़ी बेहतर है। इस दौरान बीएसई मिडकैप 150 इंडेक्स 2.6% और बीएसई स्मॉलकैप 250 इंडेक्स 0.5% ही गिरे हैं।

सेंसेक्स 394 अंक चढ़ा, बैंक शेयर 3.6% उछले

मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार में रिकवरी देखी गई। बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में जोरदार खरीदारी के दम पर सेंसेक्स 394.5 अंकों की बढ़त के साथ 73,919 पर और निफ्टी 119 अंक चढ़कर 23,242 पर बंद हुआ। दोनों बेंचमार्क इंडेक्स करीब 0.5% चढ़े। इनके मुकाबले निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 1.69%, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1.35% और निफ्टी माइक्रोकैप 250 इंडेक्स 1.86% चढ़े। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स सबसे ज्यादा 3.6% चढ़ा।

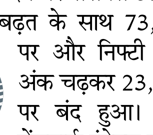

अमेरिका में टेक शेयर टूटे, नैसडेक 4% गिरा

भास्कर न्यूज | न्यूयॉर्क

अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को बिकवाली के दबाव में रहा। टेक्नोलॉजी शेयरों में भारी बिकवाली के चलते नैसडेक-100 इंडेक्स 4% टूट गया। एसएंडपी 500 इंडेक्स में 2% से ज्यादा गिरावट आई और डाऊ जोंस 1% गिर गया। वैश्विक स्तर पर भी एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स 1.7% टूटा। गिरावट की सबसे बड़ी मार सेमीकंडक्टर यानी चिपमेकर कंपनियों पर पड़ी। इस कैटेगरी के शेयर हाल ही में युद्ध-प्रेरित निचले स्तरों से उबरकर 1999 के बाद के सबसे बेहतर साल की राह पर थीं। इस समूह के शेयर एक दिन में 8% तक गिर गए। निवेशक महंगे टेक शेयरों से निकलकर अधिक साइक्लिक और आर्थिक रूप से संवेदनशील सेक्टरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसी के चलते एसएंडपी 500 की 300 से अधिक कंपनियों के शेयर बढ़त में रहे।

क्रिप्टो • बैंकिंग से जुड़ने जा रही करेंसी भी टूटी

बिटकॉइन जैसे बड़े टोकन गिरे, छोटे में 81% तक तेजी

भास्कर न्यूज | मुंबई

क्रिप्टो मार्केट में मई में बड़ा उलटफेर हुआ। बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी जैसी बड़ी क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट आई, जबकि कम चर्चित टोकन निवेशकों की पसंद बन गए। बाइनेंस रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक, हाइपरलिक्विड (हाइप) 81% उछाल के साथ टॉप परफॉर्मर रहा। 57% तेजी के साथ जेडकैश दूसरे नंबर पर और 15% की बढ़त के साथ बीएनबी तीसरे नंबर पर रहा।

बड़े टोकन के मोर्चे पर तस्वीर उलटी रही। बीते माह इथेरियम 12.4% टूट गया। बिटकॉइन में करीब 5% गिरावट आई क्योंकि बाजार में अटकलें थीं कि बड़े होल्डर्स अपनी-अपनी होल्डिंग का बड़ा हिस्सा बेच सकते हैं। एक्सआरपी भी 5.9% गिरा, बावजूद इसके कि जेपी मॉर्गन, रिपल और मास्टरकार्ड ने एक्सआरपी लेजर को पारंपरिक बैंकिंग से जोड़ने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया।

निवेशक इस बाजार में तीन प्रमुख चीजों पर नजर रखें

बाइनेंस रिसर्च के मुताबिक निवेशकों को आगे तीन चीजों पर नजर रखनी चाहिए- ब्याज दरों को लेकर नए फेड चेयर केविन वार्श के संकेत, अमेरिका में क्लैरिटी एक्ट की प्रगति और एआई से जुड़े निवेश का घटना-बढ़ना।

बिजनेस ब्रीफ

डार्क पैटर्नः सालाना ₹28 हजार करोड़ का नुकसान

बेंगलुरु | ई-कॉमर्स ग्राहकों को डार्क पैटर्न के चलते उपभोक्ताओं को सालाना 25,000 से 28,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। डेटम इंटेलिजेंस के अनुसार, यह छिपे शुल्क, फोर्स एड-ऑन, सब्सक्रिप्शन ट्रैप और ड्रिप प्राइसिंग जैसी चालाकियों से हो रहा है। यह तब है जब केंद्र ने जनवरी में ऐसी फर्मों पर 44 लाख का जुर्माना लगाया था।

इस साल कॉरपोरेट सेक्टर में 10.2% तक वेतन वृद्धि

नई दिल्ली| वित्त वर्ष 2026-27 में कॉरपोरेट इंडिया में औसत वेतन वृद्धि 8.6% से 10.2% के बीच रहने का अनुमान है। टीमलीज सर्विसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईवी और ईवी इन्फ्रा सेक्टर में सबसे ज्यादा वेतन बढ़ सकते हैं। यह रिपोर्ट 23 उद्योगों और 20 शहरों की 1,268 कंपनियों पर आधारित है।

वोडाफोन आइडिया को ₹2,113 करोड़ की राहत

मुंबई| वोडाफोन आइडिया को बड़ी कानूनी जीत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दूरसंचार विभाग द्वारा वोडाफोन आइडिया और उसकी पूर्व सहायक कंपनी स्पाइस कम्युनिकेशंस से वन-टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज की मांग खारिज कर दी है। इससे कंपनी को 2,113 करोड़ की राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि सरकार पूर्वव्यापी स्पेक्ट्रम शुल्क नहीं लगा सकती।

गोल्ड ईटीएफ से एक साल में पहली बार निकासी

नई दिल्ली| भारत में गोल्ड ईटीएफ से मई में करीब 582 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी हुई, जो लगभग 0.4 टन सोने के बराबर है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार, इससे इन फंड्स की कुल होल्डिंग घटकर 116.3 टन रह गई। यह एक साल में पहली बार है जब गोल्ड ईटीएफ से मासिक आधार पर शुद्ध निकासी दर्ज की गई।

सबसे बड़ी स्मार्ट मीटर कंपनी बनी

अदाणी एनर्जी ने अब 3,050 करोड़ में खरीदी इंटेलिस्मार्ट

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) ने इंटेलिस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को खरीद लिया है। यह सौदा पूरे 3,050 करोड़ रुपए में हुआ है। इसके तहत एईएसएल को इंटेलिस्मार्ट की पूरी 100% हिस्सेदारी मिलेगी। इंटेलिस्मार्ट के पास यूपी, गुजरात, एमपी, बिहार और असम में 2.2 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर हैं। इस अधिग्रहण के बाद एईएसएल के कुल स्मार्ट मीटरों की संख्या बढ़कर 4.7 करोड़ से अधिक हो जाएगी। इसके साथ ही यह देश की सबसे बड़ी स्मार्ट मीटर कंपनी बन गई है। इंटेलिस्मार्ट एनआईआईएफ और ईईएसएल का संयुक्त उपक्रम है। इस सौदे में पूरी इक्विटी का अधिग्रहण शामिल है। इसके साथ अदाणी इस कंपनी में एनआईआईएफ का पूरा बकाया कर्ज भी चुकाएगी। एईएसएल के सीईओ कंदर्प पटेल के मुताबिक इस अधिग्रहण से बिजली वितरण व्यवस्था का आधुनिकीकरण होगा। इससे आम उपभोक्ताओं को सटीक बिजली बिल मिलेंगे और गलत बिलों की समस्या खत्म होगी।

एअर इंडिया छोटे शहरों को बड़े एयरपोर्ट से जोड़ेगी

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

एअर इंडिया ने छोटे शहरों को बड़े एयरपोर्ट से जोड़ने वाले हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत 'इजी कनेक्ट' उड़ानों की बुकिंग शुरू कर दी है। इसकी देश में पहली सेवा 25 जून को वाराणसी से शुरू होगी। इस नए मॉडल का मतलब है कि वाराणसी (स्पोक) जैसे छोटे शहरों के यात्री दिल्ली (हब) आकर सीधे विदेशी फ्लाइट पकड़ सकेंगे। इससे आम यात्रियों को बड़ा फायदा यह होगा कि उनका अंतरराष्ट्रीय इमिग्रेशन और सामान जमा करने का काम वाराणसी में ही हो जाएगा। उन्हें दिल्ली उतरकर दोबारा सामान लेने या लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी। वाराणसी से दिल्ली के लिए रोजाना फ्लाइट AI1111 चलेगी, जो दिल्ली पहुंचने के चार घंटे के भीतर लंदन और दुबई समेत 17 विदेशी शहरों के लिए सीधी कनेक्टिविटी देगी।

कैंसर ट्रीटमेंट पर लगाया बड़ा दांव

जीएसके ₹85,800 करोड़ में न्यूवेलेंट को खरीदेगी

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

ब्रिटेन का फार्मा ग्रुप जीएसके कैंसर की दवा बनाने वाली कंपनी न्यूवेलेंट को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, यह डील 9 अरब डॉलर (करीब ₹85,800 करोड़) से अधिक में हो सकता है। दोनों कंपनियों के बीच इसी हफ्ते समझौता होने की उम्मीद है। इस डील में न्यूवेलेंट का कुल मूल्यांकन 9 से 10 अरब डॉलर (₹85,800 से 95,360 करोड़) के बीच हो सकता है। दोनों कंपनियों ने फिलहाल इस सौदे पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। एलएसईजी डेटा के अनुसार न्यूवेलेंट की मार्केट वैल्यू करीब 7 अरब डॉलर है। यह कंपनी कैंसर मरीजों के लिए सटीक लक्षित थेरेपी बनाने पर केंद्रित है। बड़ी दवा कंपनियों के बीच इस साल अपनी प्रोडक्ट पाइपलाइन बढ़ाने के लिए अधिग्रहण की होड़ मची हुई है। अमेरिकी फाइनेंशियल फर्म स्टिफेल की रिपोर्ट के यदि यही रफ्तार रही तो इस साल में बायोफार्मा सेक्टर के विलय-अधिग्रहण का कुल मूल्य 250 अरब डॉलर (₹23.8 लाख करोड़) के पार निकल सकता है।

मेगा प्रोजेक्ट • समंदर पर तैरता पांच सितारा शहर, क्रूज में 122 प्राइवेट रेजिडेंस और 22 गेस्ट सुइट

मोनाको| जिन्हें पेंटहाउस भी 'साधारण' लगते हैं, उनके लिए आ रहा है 1,050 फुट लंबा तैरता महल यूलिसिया। मोनाको की कंपनी यूलिसिया रेसिडेंसेज एजी और मशहूर डिजाइनर एस्पेन क्विनो का यह ड्रीम प्रोजेक्ट 2031 में पानी पर उतरेगा। निर्माण की जिम्मेदारी चीन की चाइना मर्चेंट्स क्रूज शिपबिल्डिंग को मिली है। इस तैरते शहर में 122 प्राइवेट रेजिडेंस और 22 गेस्ट सुइट होंगे। इसमें 110 से 953 वर्गमीटर तक के घर, खुली रसोई और निजी टैरेस भी हैं।

बिजनेस एंकर रणनीति...₹700 के आर्डर पर डिजिटल लॉटरी गेम, खिलौने देकर सुशिरो चेन ने बढ़ाई बिक्री

चीन में जापानी सुशी खाने के लिए 14 घंटे की कतारें, सिर्फ 6 माह में कमाया पूरे साल का 70% मुनाफा, शेयर में 23 फीसदी उछाल

भास्कर न्यूज | बीजिंग

चीन में एक जापानी रेस्टोरेंट चेन ने युवाओं को दीवाना बना लिया है। जापान की मशहूर कन्वर्टर-बेल्ट सुशी चेन 'सुशिरो' चीन के 'एमजेड जनरेशन' (मिलेनियल्स और जेन-जी) के बीच बड़ा सोशल मीडिया ट्रेंड बन चुकी है। लोग यहां सुशी खाने के लिए 5 से 14 घंटे तक इंतजार करने को तैयार हैं। इस दीवानगी की सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डोयिन और श्याओहोंगशू पर वायरल हो रहे वीडियो हैं। चीनी युवा रेस्टोरेंट में खाने के बाद खाली प्लेटों को एक के ऊपर एक रखकर ऊंचे-ऊंचे टावर बना रहे हैं, जिसे 'सुशिरो टावर' नाम दिया गया है। 60 से 80 प्लेटों की ऊंचाई वाले इन वीडियो को लाखों-करोड़ों लाइक्स मिल रहे हैं। इस दीवानगी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में ही कंपनी ने पूरे साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लक्ष्य का 70% हिस्सा हासिल कर लिया है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयरों में इस साल 23% तेजी आई है। इसने जापान के बेंचमार्क इंडेक्स टोपिक्स को भी पीछे छोड़ दिया है। सुशिरो ने साल 2021 में गुआंगझू से चीन में कदम रखा था, लेकिन पिछले साल शंघाई में एंट्री के बाद इसकी लोकप्रियता सातवें आसमान पर पहुंच गई। इस दीवानगी का फायदा उठाकर कुछ लोग सेकंड हैंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 420 रुपए में अपना वेटिंग कतार नंबर तक बेच रहे हैं। सुशिरो ने ग्राहकों को बांधे रखने के लिए भोजन के साथ मनोरंजन का तड़का भी लगाया है। कंपनी ने स्टोर्स में 'डिगिरो' नाम का एक इन-स्टोर डिजिटल ऑर्डरिंग सिस्टम है। इसके तहत जो भी ग्राहक 60 युआन (करीब 840 रुपए) या उससे अधिक खर्च करता है, उसे स्क्रीन पर एक डिजिटल लॉटरी गेम खेलने का मौका मिलता है। इस गेम को जीतने पर ग्राहकों को सुशी कैरेक्टर वाले खिलौने और अन्य आकर्षक इनाम मिलते हैं, जो युवाओं को बेहद आकर्षित कर रहे हैं।

अन्य सुशी चेन्स के मुकाबले काफी सस्ता... क्वालिटी भी बेहतरीन

मंदी के दौर का सटीक हथियार सुशिरो की इस कामयाबी का सबसे बड़ा स्तंभ इसकी किफायत है। चीन के स्टोर्स में सुशी की एक प्लेट की कीमत 112 से 392 रुपए के बीच है। शेनझेन में रहने वाली 24 वर्षीय कामकाजी महिला डेंग दानशान कहती हैं, 'मैं हफ्ते में कम से कम एक बार सुशिरो जाती हूं। एक बार में करीब 25 प्लेटें खा लेती हूं और मेरा बिल लगभग 200 युआन (करीब 2,800 रुपए) आता है। यह बाजार की दूसरी सुशी चेंस के मुकाबले काफी सस्ता है और इसकी क्वालिटी भी बेहतरीन है।'

मईः 23 लाख डीमैट खुले, औसत से कम

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

देश में नए डीमैट खाते खुलने की रफ्तार तीसरे महीने औसत से कम रही है। मई में करीब 23 लाख नए डीमैट खाते खोले गए। यह साल 2025 के हर महीने 25 लाख के औसत से भी कम है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले डीमैट खातों की ग्रोथ में गिरावट रिटेल निवेशकों की कम होती भागीदारी को दर्शाती है। जानकारों के अनुसार पिछले 18 महीनों के सुस्त माहौल और भू-राजनीतिक अनिश्चितता से निवेशकों का हौसला कमजोर हुआ है। ईरान संघर्ष के बाद एनर्जी की बढ़ती कीमतों से कॉरपोरेट मुनाफे की रफ्तार सुस्त पड़ी है। कमजोर मानसून की आशंका और तकनीकी क्षेत्र में एआई के बढ़ते इस्तेमाल से नौकरी की चिंता बढ़ी है।

जीवन बीमा • शिकायतें 10 साल में आधी से ज्यादा घटीं

18-35 आयु वर्ग के 90% लोग इंश्योरेंस कवर से बाहर

भास्कर न्यूज | मुंबई

देश के जीवन बीमा सेक्टर में ग्राहक शिकायतों में पिछले एक दशक में 50% से ज्यादा गिरावट आई है। इस दौरान बीमा कारोबार लगातार बढ़ता रहा। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के आंकड़े बताते हैं कि शिकायतें वित्त वर्ष 2015 के 2.79 लाख से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 1.23 लाख रह गईं। इसी दौरान पॉलिसियों की संख्या बढ़कर 292 लाख हो गई, पर इस दशक में शिकायतें 2.79 लाख से घटकर 1.23 लाख हो गई है।

इंश्योरेंस अवेयरनेस कमेटी-लाइफ इंश्योरेंस के आंकड़े के मुताबिक देश की 87% आबादी बीमा सुरक्षा के दायरे से बाहर है। 18-35 आयु वर्ग में यह अंतर 90% से भी अधिक है। जीवन बीमा देश के कुल बीमा प्रीमियम का 80% से ज्यादा हिस्सा है और सरकारी बॉन्ड में इसका निवेश ₹24.37 लाख करोड़ से अधिक है।

क्लेम निपटाने में लगने वाला समय भी आधा हुआ

पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के तहत क्लेम निपटान की समयसीमा 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है। जांच की स्थिति में यह 90 दिन से घटाकर 45 दिन हुई है। हालांकि चुनौतियां बरकरार हैं।

मानव जीवन का उद्देश्य सेवा करना और दूसरों के प्रति दया व मदद करने की भावना रखना है। -अल्बर्ट श्वित्जर

गृहिणी का सम्मान

भारतीय समाज में गृहिणियों को हमेशा से परिवार की धुरी तो कहा जाता रहा है, लेकिन घर के अनगिनत कार्यों में अपना पूरा जीवन खपा देने वाली महिलाओं के योगदान को आर्थिक विमर्श से बाहर ही रखा गया है। इस संदर्भ में, सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाली गृहिणियों के मुआवजे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला महत्वपूर्ण तो है ही, यह उस रूढ़िवादी सोच पर भी एक कड़ा प्रहार है, जो महिलाओं के अथक और अवैतनिक श्रम को अनुत्पादक मानती आई है। गौरतलब है कि गृहिणी बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, उनकी शिक्षा व संस्कारों की नींव रखती है और समाज के लिए नई पीढ़ी तैयार करती है। इस दृष्टि से देखें, तो उसके घरेलू श्रम का असर पूरे राष्ट्र पर पड़ता है। इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में शीर्ष अदालत ने भी माना है कि घर की देखरेख करने वाली महिलाएं सिर्फ घर की नहीं, बल्कि राष्ट्र की भी निर्माता होती हैं। अदालत ने अपने फैसले में गृहिणियों के कार्य का न्यूनतम अनुमानित मूल्य तीस हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित करते हुए यह स्पष्ट किया है कि घरेलू कामकाज को केवल भावनात्मक या नैतिक जिम्मेदारी के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये वे कार्य होते हैं, जिनके बगैर परिवार की इकाई टिक ही नहीं सकती। विडंबना यह है कि अगर यही सेवाएं बाजार से ली जाएं, तो उनकी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती है, पर जब इन्हें कोई महिला अपने घर के भीतर करती है, तो उन्हें 'काम' की श्रेणी तक में नहीं रखा जाता। विभिन्न अध्ययनों व सर्वेक्षणों से यह तथ्य सामने आ चुका है कि आमतौर पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक समय घरेलू देखरेख में लगाती हैं। इसके बावजूद, राष्ट्रीय आय और उत्पादकता के पारंपरिक पैमानों में उनके योगदान का समुचित प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। जाहिर है कि यह स्थिति न केवल आर्थिक असमानता को बढ़ाने वाली है, बल्कि महिलाओं की भूमिका के सामाजिक अवमूल्यन को भी जन्म देती है। इस संदर्भ में शीर्ष अदालत का यह कहना आंखें खोलने वाला है कि महिलाओं के घरेलू कार्यों का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब 17 फीसदी हिस्सा होता है। हालांकि, तीस हजार रुपये प्रतिमाह का आकलन किसी गृहिणी के वास्तविक योगदान का मूल्य नहीं हो सकता, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला घरेलू श्रम को सम्मान व पहचान दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह फैसला मुआवजे के निर्धारण तक सीमित न रहकर, समाज में महिलाओं की भूमिका के प्रति सम्मान व संवेदनशीलता बढ़ाने का माध्यम भी बनेगा।

भीड़ में भी अकेले हैं

युद्ध, आपदाओं और परीक्षाओं से जुड़े प्रश्न पूछ रहे हैं कि फोन में कई-कई जीबी की मेमोरी और हजारों कांन्टेक्ट्स के बावजूद आखिर हम अकेले क्यों हैं? इसका जवाब तभी मिलेगा, जब हम दूसरों की खुशियों का जश्न मनाने और उनके दुखों पर मौन होना सीखेंगे।

नन्दितेश निलय
स्पीकर, लेखक एवं एथिक्स प्रशिक्षक

अगर कोई यह पूछे कि युद्ध, आपदाओं और नफरतों के दौर में आखिर भाईचारे का अर्थ क्या रह गया है, तो आप क्या जवाब देंगे? गंगा-जमुनी तहजीब का बिखरना हर पल तकनीक से जुड़ी दुनिया के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। यह सामूहिक दुख का प्रश्न है। अब कुछ एकल दुख की बात करें, खासकर उनके लिए, जो सीबीएसई से लेकर जेईई की परीक्षा में चूक गए हैं। ऐसे में, वे भला अपना दुख किससे जाहिर करें? क्या समाज में प्रेम और सौहार्द की हिमायत करने वाले नायक अकेले पड़ते जा रहे हैं? इसका जवाब है, शायद हां!

जो जिंदगी से लेकर क्लासरूम तक की परीक्षा तक में विफल हो रहे हैं, वे भी तो अकेले ही होते जा रहे हैं। अपने फोन में कई-कई जीबी की मेमोरी लिए ये सभी अपने मन का दुख किससे कहें? ये सारे प्रश्न किसी विरोधाभास का संकेत नहीं कर रहे, बल्कि पूछ रहे हैं कि हमारे पास हजारों कांटेक्ट्स होते हैं, पर मुश्किल घड़ी में हम किसी को पुकार नहीं पाते और कोई बचाने नहीं आता। सब जगह मनुष्य अकेला ही दिख रहा है। तो फिर किसे अपना माना जाए? कौन हमारे सुख-दुख का साथी बने? आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे फोन में हजारों नंबर होते हैं, पर हम बात कोई दस-बीस से ही करते हैं। ऐसा क्यों? जब किसी मुश्किल में या खुशी के जश्न में किसी को फोन करना होता है, तो उन्हीं दस-बीस नंबरों से हमारी बातचीत होती है। और अगर हम अपने आप से कुछ बुनियादी प्रश्न पूछ बैठें, तो फिर वह कांटेक्ट लिस्ट और कम हो जाती है।

हाल ही में, मैंने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के शीर्ष नेतृत्व को पढ़ाते हुए कुछ प्रश्न किए। वे प्रश्न कुछ इस प्रकार के थेः वे कौन लोग हैं, जिनका आप आदर करते हैं? वे कौन लोग हैं, जो आपको आदर देते हैं? मुसीबत में आप किन लोगों को फोन करना चाहेंगे? अपने मन की बात आप किनसे कहते हैं? ऐसे कितने लोग हैं, जो आपसे अपने सुख-दुख बांट सकते हैं? यह जीवन आप किसके लिए जी रहे हैं? आपकी सफलता और उपलब्धि से कितने लोग खुश होते हैं? ऐसे ही कुछ और प्रश्न! अंत में हुआ यह कि वह संख्या दहाई तक भी नहीं पहुंची। अगर मनुष्य होने का मतलब मिलजुल कर रहना है, तो फिर सुख-दुख के भाव को महसूस करने और बांटने के लिए सिर्फ कुछेक लोग ही क्यों? जुड़ना ही मनुष्यता है, और किसी के लिए सहानुभूति रखना, उसके हालात को महसूस करना ही जीवन की अत्यावश्यकता भी। खासकर उस वक्त, जब दुनिया नए तरीकों से लगातार लड़ना सीख रही है और सारे संप्रेषण (कम्युनिकेशन) के संसाधन उस भेद को ही बढ़ाने में लगे हुए हैं। विशेष रूप से तब, जब परिणाम से आकलन करती दुनिया में युवाओं को सब कुछ जीतने को कहा जाता है। लेकिन, उस जीत और हार को कोई कैसे संप्रेषित करे?

हमें सिखाया तो यह जाता है कि यह युग संप्रेषण का है और इससे बड़ी योग्यता और कुछ भी नहीं। अगर हम संचार नहीं कर पाते, तो फिर सारी योग्यता बेमानी है। डिजिटल युग में मैसेजेस और मेल्स से जुड़ी जनता पूछना चाहती है कि आखिर संबंधों का तात्पर्य क्या होता है? हम अपनी खुशी बहुत कम लोगों से इसलिए बांट पाते हैं। हमें यह यकीन नहीं होता कि हमारी खुशी उस व्यक्ति को भी प्रफुल्लित करेगी, क्योंकि किसी की सफलता किसी और के लिए तुलना का कारण बन जाती है। यह तुलनात्मक भाव किसी को किसी की प्रशंसा करने से रोक देता है।

हम यह न भूलें कि किसी के गुणों को सम्मान देना सिर्फ एक मानवीय गुण नहीं, बल्कि वह एक ऐसी विशिष्टता भी है, जो किसी शेन वार्न को सचिन की प्रशंसा करने से नहीं रोक सका। जब सगे-संबंधियों में 'हमारे परिवार' का भाव नहीं रह जाता, तो फिर जीत का जश्न भी फीका रह जाता है। जहां तक दुख के भावों की अभिव्यक्ति है, तो उसके लिए भी दरवाजे बंद ही रहते हैं। कोई समाज भले ही जुड़ने की वकालत करे, लेकिन व्यक्ति अपने सुखों और दुखों के साथ अकेला है। चाहे वह घर में हो, ऑफिस में या भीड़ के बीच-उसकी उपयोगिता सिर्फ बाजार के मापदंडों तक ही रह गई है। जीवन जैसे कृष्ण की तरह उससे बार-बार यही कह रहा है कि सभी के साथ हो, पर किसी के साथ नहीं! इसलिए लिप्त रहकर भी निर्लिप्त रहो।

अगर असली रिश्तों की संख्या दहाई भी पार नहीं कर पाई, तो मनुष्य के उस सामाजिक संप्रेषण और सरोकार का क्या हो? इन सारे प्रश्नों का जवाब सिर्फ और सिर्फ उस आत्म-ज्ञान में है, जो भावनात्मक और आध्यात्मिक मेधा से प्राप्त होता है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि अपनों की संख्या तभी बढ़ती है, जब समाज दूसरों की खुशी का जश्न मनाता है और उनके दुखों पर मौन भी होना जानता है। यह संख्या तभी बढ़ेगी, जब कृतज्ञता का भाव हमें जीवन जीने का रास्ता दिखाए। जब उनमें से कई आपकी सफलता को अपना मानें और विफलता में आपको निराश न होने दें। समाज से सारी नफरत दफन हो जाए, क्या यह संभव है? मुझे तो लगता है कि संभव है।

टीम भावना और आपसी सहयोग की वकालत करती संस्थाएं भी यह मानेंगी कि यह संभव है। उस कक्षा के अंत में सभी ने यह माना भी कि अपनों और परायों का भेद सिर्फ तभी कम हो पाएगा, जब हम किसी और की खुशी में भी खुश होना सीखें, तथा दूसरों के दुखों को महसूस करने का मौका न चूकें। किसी और की सफलता का जश्न मनाना एक उच्चतम चेतना है। जिनका सब कुछ छूट रहा हो, वह जीवन जो निकल रहा हो, उनको भी अपनी कांटेक्ट लिस्ट में रखा जाए। अगर ऐसा होता है, तो संख्या दहाई से काफी आगे बढ़ेगी और फिर कितने और भी आएंगे, जिनकी कांटेक्ट लिस्ट में हमारी सफलता और परेशानियों की भी जगह बनेगी। बस ध्यान रहे कि उस सूची में घमंड, ईर्ष्या और हीनता वाले कांटेक्ट्स की कोई जगह न बनने पाए, जिससे सही लोगों को जगह मिल सके।

जिन्होंने सीबीएसई, जेईई की परीक्षा पास की, उनको बधाई दीजिए, जो चूक गए, उनका भी दुख महसूस करिये और जो पेपर लीक का दंश सह गए, उनका भी। जिन प्रश्नों की चर्चा उस कक्षा में हुई, आप भी उनका उत्तर ढूंढिए। और उस सामूहिक दुख को भी महसूस करिये, उस ताने-बाने को, उस गंगा-जमुनी तहजीब को, हिंदू-मुसलमान, सिख, ईसाई के बीच बंटते उस इन्सान को भी ढूंढिए, जिसको अजहर इनायती भी इन शब्दों में ढूंढ रहे हैंः *रास्तो क्या हुए वो लोग कि आते-जाते,/मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए।*

edit@amarujala.com

जीवन एक सफर ही तो है

स्मृति शेष

जसपाल राणा
28-6-1976 से 12-6-2026

सफर जारी रहना चाहिए और संघर्षों को रुकावट नहीं, बल्कि प्रेरणा के तौर पर देखना चाहिए। मेरे लिए तो यही जिंदगी की असली परिभाषा रही है।

मैंने 10 साल की उम्र में शूटिंग और 11 या 12 साल की उम्र में स्टेट और नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया। मेरे पिता स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) में तैनात थे, जिससे मुझे हथियारों और खेल के तौर पर शूटिंग के बारे में जानने-समझने का मौका मिला। मैं पिस्तौल और राइफल, दोनों ही अच्छी तरह चलाता था, लेकिन फेडरेशन ने नियम बना दिया कि कोई व्यक्ति राइफल या पिस्तौल में से सिर्फ एक ही तरह की शूटिंग कर सकता है। मैंने पिस्तौल को चुना।

बतौर शूटर मेरी सभी उपलब्धियां यादगार हैं, क्योंकि इसमें लगभग 16 वर्षों की जीत-हार और काफी उतार-चढ़ाव शामिल हैं। पर, 1994 की मिलान वर्ल्ड चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीतना मेरे लिए खास है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा से एक रात पहले मैं हॉस्पिटल में था; मेरे घुटने पर एक फोड़ा हो गया था और मेरी हालत बहुत खराब थी। डॉक्टरों ने मुझे डिस्चार्ज करने से मना कर दिया था। मेरे कोच सनी थॉमस ने वहां से भागने का फैसला किया, क्योंकि मैं शूटिंग करना चाहता था। तो हमने वही किया (भाग गए), पर उसी रात फोड़ा फूट गया और मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मैंने कोई पेनकिलर भी नहीं ली, क्योंकि मुझे डोप नियमों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। मैं अपनी जींस भी नहीं उतार पा रहा था। इसलिए, अगली सुबह अपने इवेंट में हिस्सा लेने के लिए मुझे उसे काटकर शॉर्ट्स बनाना पड़ा। मैं बस अपना इवेंट खत्म करके डॉक्टर के पास जाकर पेनकिलर लेना चाहता था। शूटिंग के ठीक बाद मैंने ऐसा ही किया। बाद में, मेरे कोच ने आकर बताया कि मैंने गोल्ड जीता है और यह एक जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसके बाद मुझे यह भी पता नहीं चला कि मेरा दर्द कितना ज्यादा था। किसी दूसरे देश में अपने देश का झंडा ऊंचा लहराते देखना और स्वर्ण पदक के साथ घर लौटना एक बहुत ही शानदार एहसास था। लेकिन मेरा मानना है कि जीवन एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। मैं खुद को भी एक सफर में मानता हूं और संघर्षों को रुकावट की जगह प्रेरणा के तौर पर देखता हूं।

टोक्यो ओलंपिक के बाद बहुत-से लोगों ने मेरी आलोचना की और मुझे खलनायक बना दिया, जबकि मैं वहां मौजूद भी नहीं था। जब आप कोच होते हैं, तो सबसे जरूरी है एथलीट की बात सुनना, न कि उन पर अपनी राय थोपना। एथलीट को हमेशा तैयार रखना कोच का काम होता है। मैं जो कुछ भी देखता, समझता और नोट करता हूं, उस पर एथलीट से चर्चा करता हूं। कोच प्रेरित कर सकता है, लेकिन शूटिंग रेंज में प्रदर्शन एथलीट को ही करना होता है। मेरे लिए कोचिंग एक जुनून है। मैंने कभी किसी ऐसे शूटर को मना नहीं किया, जिसने मुझसे संपर्क किया। लेकिन सिर्फ भावनाओं से मैच नहीं जीते जाते। आपको उस व्यक्ति का दोस्त और कोच बनना होता है, जिसे आप प्रेरित करते हैं और जिससे आप उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकलवा सकते हैं। मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूं।

(विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित)

जिस तरह कुछ प्रकाश तरंगों को इन्सान देख व कुछ ध्वनियों को सुन नहीं सकते, ठीक उसी तरह मशीनों के पास भी कुछ ऐसे विचार हो सकते हैं, जो इन्सानों की सोच से परे हों। - रिचर्ड हैमिंग

समझ के साथ जिज्ञासा भी बढ़ती जाती है

जितना अधिक हम प्रकृति और ब्रह्मांड को समझते हैं, उतने ही ज्यादा उत्सुक भी होते जाते हैं। मैंने यह समझा है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज केवल ज्ञान नहीं, बल्कि सीखने और जानने की जिज्ञासा है।

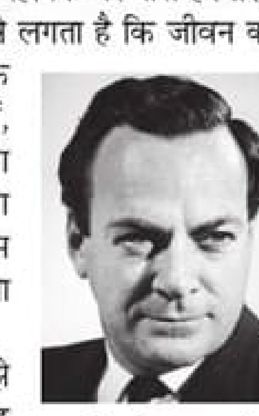

रिचर्ड फाइनमेन

जीवन धारा

मुझे कभी इस बात की बेचैनी नहीं रही कि मेरे पास हर प्रश्न का उत्तर नहीं है। वास्तव में, मुझे लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता इसी में है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं, जो रहस्यों से भरा हुआ है। बहुत-से लोग निश्चितता चाहते हैं। पर, मैंने हमेशा अनिश्चितता को अपनाया है, क्योंकि जब हम यह मान लेते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया है, उसी क्षण हमारी खोज समाप्त हो जाती है।

जब मैं रात के आकाश को देखता हूं, तो मुझे केवल तारे नहीं दिखाई देते। मुझे प्रकृति की वह घटना भी दिखाई देती है, जो अरबों वर्षों से चल रही है। मैं सोचता हूं कि यह सब कैसे बना, क्यों बना, और किन नियमों के अनुसार काम करता है। कई लोग मानते हैं कि विज्ञान दुनिया के रहस्यों को खत्म कर देता है, पर मेरा अनुभव बिल्कुल अलग है। जब मैं किसी फूल को देखता हूं, तो मुझे उसकी खूबसूरती सिर्फ उसके रंगों में नहीं दिखती। मैं यह भी सोचता हूं कि वह कैसे बना, कैसे बढ़ा और कैसे प्रकृति ने उसे यह रूप दिया। दरअसल, विज्ञान किसी चीज के पीछे छिपी अद्भुत कहानी को सामने लाता है। इसीलिए, जितना अधिक हम प्रकृति और ब्रह्मांड को समझते हैं, उतने ही ज्यादा उत्सुक भी होते जाते हैं। मैंने यह समझा है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज केवल ज्ञान नहीं, बल्कि सीखने और जानने की जिज्ञासा है। ज्ञान सीमित हो सकता है, पर जिज्ञासा हमेशा नए सवाल पूछने और नई चीजें खोजने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा पूछता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो उसके मन में भी एक तरह की जिज्ञासा ही काम कर रही होती है, जो उसे प्रकृति के गहरे रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करती है।

मुझे ऐसी दुनिया में रहना पसंद है, जहां अब भी बहुत-सी बातें ऐसी हैं, जिन्हें हम पूरी तरह नहीं जानते। यही अनजानी चीजें हमें नए सवाल पूछने और नई खोजें करने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर हर सवाल का जवाब पहले से ही पता हो और कोई रहस्य बाकी न बचे, तो जीवन में रोमांच और आश्चर्य खत्म हो जाएगा।

जब चैटबॉट बना मेरा रियल एस्टेट एजेंट

घर बेचने की प्रक्रिया के दौरान एआई ने मेरा ऐसा साथ दिया कि असल रियल एस्टेट एजेंट भी मेरे ज्ञान से चौंक उठे।

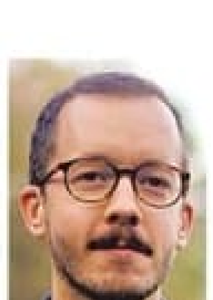

स्टुअर्ट ए थॉम्पसन
द न्यूयॉर्क टाइम्स

AI समय

मैं अपनी कार में बैठा था, तभी एक फोन कॉल आया, जो शायद पांच लाख डॉलर से भी अधिक के सौदे में बदल सकता था। कॉल पर एक रियल एस्टेट एजेंट थी। उसका ग्राहक मेरा घर खरीदने पर विचार कर रहा था। थोड़ी बातचीत के बाद उसने पूछा कि क्या आप वाकई कोई रियल एस्टेट एजेंट नहीं हैं? मैंने जवाब दिया, 'नहीं।' वह कुछ पल चुप रही और बोली, 'आपके ई-मेल, बातचीत का तरीका, पेशेवर भाषा और घर बेचने का मसौदा देखकर तो मुझे लगा कि आप एक अनुभवी एजेंट हैं।' सच तो यह था कि यह सब मेरा नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का काम था।

हमारे दूसरे बच्चे के जन्म के समय मैंने और मेरी पत्नी ने अपना घर बेचकर बड़े घर में जाने का फैसला किया। अक्सर लोग घर खरीदने-बेचने के लिए रियल एस्टेट एजेंटों की मदद लेते हैं, पर कई एजेंटों से बातचीत के बाद मेरे मन में उनकी विशेषज्ञता को लेकर कुछ संदेह पैदा हो गया। इसके अलावा, एजेंटों की फीस भी कम नहीं थी। घर की बिक्री होने पर करीब छह प्रतिशत कमीशन देना पड़ता, जो 30,000 डॉलर से अधिक था। तब मेरे मन में सवाल उठा कि क्या यह काम मैं एआई की मदद से खुद नहीं कर सकता?

इसके बाद मैंने घर की जानकारी एआई चैटबॉट को दी और उससे बिक्री का विवरण लिखने को कहा। कुछ ही सेकंड में उसने ऐसा आकर्षक विवरण तैयार कर दिया, जिसे पढ़कर मेरी पत्नी भी प्रभावित हो गई। तब मुझे लगा कि शायद यह प्रयोग सचमुच काम कर सकता है। मैंने चैटबॉट की मदद से घर बेचने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी। फोटोग्राफर ढूंढने से लेकर घर की सजावट, तस्वीरों की प्रस्तुति, लिस्टिंग की भाषा और कानूनी दस्तावेजों को समझने तक, हर काम में एआई ने मेरा मार्गदर्शन किया। हालांकि, एक बार उसने खरीदार के एजेंट को शून्य कमीशन देने की सलाह देकर गलती भी की, जो नियमों के खिलाफ था। लेकिन, अगर इस एक चूक को छोड़ दें, तो पूरी प्रक्रिया आश्चर्यजनक रूप से आसान साबित हुई। जल्द ही एक नकद खरीद प्रस्ताव सामने आया। फिर, मैंने चैटबॉट से उस प्रस्ताव का जवाब देने का तरीका पूछा, तो उसने समझाया कि बातचीत में कौन-से शब्द आत्मविश्वास दिखाते हैं और कौन-से मुझे नौसिखिया साबित कर सकते हैं। धीरे-धीरे एआई सिर्फ सलाहकार नहीं, बल्कि मेरा रणनीतिक साझेदार बन गया। उसने मुझे मोलभाव, संवाद और निर्णय लेने की ऐसी समझ दी, जो सामान्यतः वर्षों के अनुभव से आती है। पर हां, इसी दौरान मुझे एआई की सीमा भी समझ आई।

दरअसल, जब कुछ खरीदारों ने मेरे घर बेचने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो मेरा मनोबल टूटने लगा। तब मैंने एआई से बात की। उसके जवाब तर्कपूर्ण तो थे, लेकिन भावनात्मक नहीं, जबकि मुझे सहानुभूति चाहिए थी। उस समय मेरे दोस्त और परिवार मेरे काम आए। तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ परिस्थितियों में मानवीय अनुभव, भरोसा और भावनाएं अब भी जरूरी हैं। कुछ दिनों बाद मेरे पास तीन अच्छे ऑफर थे और तीनों हमारी मांगी गई कीमत से अधिक थे। अब सबसे चुनौतीपूर्ण चरण था-मोलभाव। इस बार भी एआई ने मुझे रास्ता दिखाया। उसने सुझाव दिया कि सबसे अधिक कीमत वाले प्रस्ताव के बजाय उस प्रस्ताव को चुनना बेहतर होगा, जिसके सफल होने की संभावना सबसे अधिक हो। आखिरकार, हमने छह लाख डॉलर से अधिक का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए मैंने एक वकील की मदद ली, पर पूरे सौदे में किसी रियल एस्टेट एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी। अंतिम गणना करने पर मैंने पाया कि एआई की मदद से मुझे करीब 90,000 डॉलर का अतिरिक्त लाभ हुआ।

फिर भी, मैं यह दावा नहीं करता कि हर व्यक्ति ऐसा कर सकता है। मैं तकनीक से जुड़ा हूं और एआई को समझना मेरे पेशे का हिस्सा है। इस अनुभव ने मुझे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया कि एआई लोगों को ऐसी क्षमताएं दे सकता है, जो कभी केवल विशेषज्ञों तक सीमित थीं। वह कई पेशों की भूमिका जरूर बदल सकता है, पर अनुभव, जवाबदेही, भावनात्मक समर्थन और मानवीय भरोसे की जगह पूरी तरह नहीं ले सकता।

घर बेचने का मेरा एआई प्रयोग सफल रहा। लेकिन, उसके अंत में मैंने खुद से एक नया सवाल पूछा कि अगर एआई की मदद से मैं घर बेच सकता हूं, तो क्या उसी की मदद से अपना अगला घर भी खरीद सकता हूं? यहीं एआई के साथ मेरा एक प्रयोग समाप्त हुआ और दूसरा शुरू होने वाला था।

लवेबल

यह एक आधुनिक एआई-आधारित प्लेटफॉर्म है, जो बिना अधिक कोडिंग ज्ञान के वेबसाइट, वेब एप्लिकेशन और डिजिटल प्रोजेक्ट्स बनाने में मदद करता है। उपयोगकर्ता को बस यह बताना होता है कि वह क्या बनाना चाहता है, उसी आधार पर यह एआई स्वतः इंटरफेस, कोड और आवश्यक फीचर्स तैयार कर देता है। इसके बाद उपयोगकर्ता अपने सुझाव और फीडबैक देकर डिजाइन, फीचर्स और कार्यक्षमता में आसानी से बदलाव कर सकते हैं। इसमें टेम्पलेट्स की एक मजबूत लाइब्रेरी भी उपलब्ध है, जिससे नए प्रोजेक्ट की शुरुआत और आसान हो जाती है।

कोर्ट डायरी

जनगणना कर्मी से बदसलूकी, 22 दिन में मिली सजा

नई दिल्ली। जनगणना ड्यूटी में लगी महिला कर्मी से बदसलूकी के मामले में न्यायालय ने 22 दिन के अंदर ही आरोपी को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है। इस मामले में दिल्ली की द्वारका जिला पुलिस ने भी त्वरित न्याय का बेंचमार्क सेट किया है। पुलिस थाना द्वारका नॉर्थ के स्टाफ ने जनगणना ड्यूटी पर महिला कर्मी से बदसलूकी करने वाले मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के 40 घंटे के अंदर चार्जशीट दाखिल की थी। 19 मई 2026 को पुलिस थाना द्वारका नॉर्थ में सरकारी जनगणना ड्यूटी पर गई महिला एन्यूमरेटर ने मकान मालिक पर बदसलूकी का आरोप लगाया। पुलिस ने 20 मई को आरोपी को ट्रेस कर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। 21 मई 2026 को जांच अधिकारी ने महज 40 घंटे में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर स्पीडी ट्रायल की मांग की। न्यायालय की ओर से 12 जून को संदीप पंवार (43) निवासी विपिन गार्डन, नई दिल्ली को दोषी करार दे दिया। ब्यूरो

लेडी डॉन जोया खान की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के कारोबारी नादिर शाह हत्याकांड में आरोपी गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी और लेडी डॉन के नाम से कुख्यात जोया खान को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया जोया खान हत्या की साजिश, शूटरों की व्यवस्था और सुबूत मिटाने के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल थी। न्यायालय ने इसे बेहद गंभीर और सुनियोजित हत्या की साजिश बताया, जिसके तहत नादिर शाह की सार्वजनिक स्थान पर गोली मारकर हत्या की गई। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि जोया खान केवल सहायक भूमिका में ही नहीं थी, बल्कि वह साजिश का सक्रिय हिस्सा थी। उसने शूटरों को निर्देश दिए, हत्या की योजना की चर्चाओं में भाग लिया और वारदात के बाद सबूत छुपाने की कोशिशें कीं। इसके अलावा उसके घर से एक हथियार बरामद होना आरोपों को और मजबूत करता है। ब्यूरो

दो भाइयों पर चाकू से हमला करने में दोषी करार

नई दिल्ली। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में गाड़ी ट्रांसफर को लेकर हुए विवाद में दो भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमले के मामले में साकेत कोर्ट ने आरोपी विवेक उर्फ प्रतीक को दोषी करार दिया। साकेत अदालत के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल ने फैसला सुनाया। करीब साढ़े चार साल पहले हुई इस वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। अब लंबी सुनवाई और 18 गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। आरोप है कि गाड़ी का ट्रांसफर नहीं कराया गया था, जिसको लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। अदालत में आरोपी के पिता ने यह भी स्वीकार किया कि वाहन खरीदा गया था, लेकिन ट्रांसफर को लेकर समस्या थी। अभियोजन पक्ष ने इसे हमले की मुख्य वजह बताया। संवाद

साकेत कोर्ट के ट्रोलिंग पर संज्ञान लेने से इन्कार

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को साकेत कोर्ट के एक जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रहे ट्रोलिंग पर स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) लेने से इनकार कर दिया। जज पत्रकारों के खिलाफ अभिजीत अय्यर-मित्रा पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश को स्थगित करने वाले हैं। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ के समक्ष अभिजीत अय्यर-मित्रा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ने बताया कि स्टे आदेश के बाद जज के खिलाफ समन्वित तरीके से ट्रोलिंग की जा रही है। जज ने अपने आदेश में कहा था कि अय्यर-मित्रा का ट्वीट शायरी के रूप में था और किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया था। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा मुझे अभी भी ऐसा नहीं लगता कि यह संज्ञान लेने की प्रकृति में है। हम यह नहीं मानते कि कोई असाधारण कदम उठाने की जरूरत है। पत्रकार मनीषा पांडे और अन्य छह पत्रकारों ने अय्यर-मित्रा के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अय्यर-मित्रा ने उन्हें बार-बार वेश्या कहते हुए आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। इस पर आपत्ति जताते हुए शिकायत भी की गई थी। ब्यूरो

उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए नहीं खुलेगा पोर्टल : हाईकोर्ट

सीबीएसई 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिका दोबारा जांचने को एनएसयूआई ने दायर की जनहित याचिका

अमर उजाला ब्यूरो

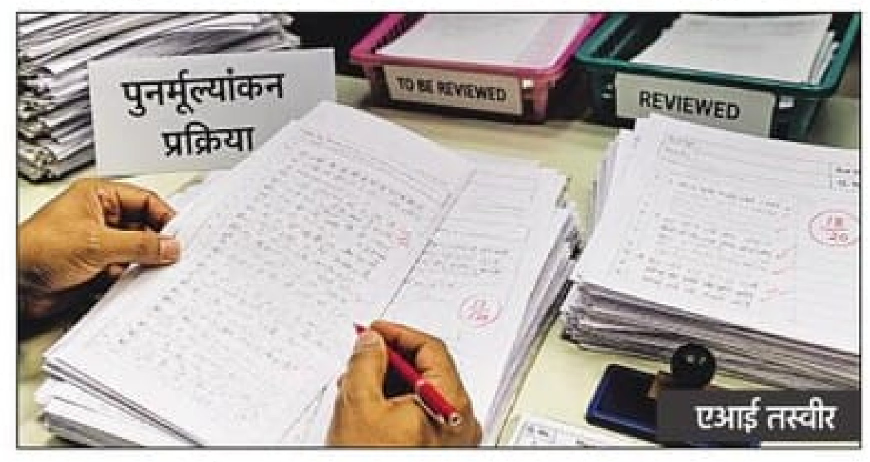

एआई तस्वीर

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीबीएसई 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल दोबारा खोलने का निर्देश देने से इन्कार कर दिया।

छात्र संगठन एनएसयूआई की ओर से दायर जनहित याचिका पर कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्तिगत छात्र संतुष्ट नहीं है तो वह उचित कानूनी कार्रवाई कर सकता है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति मधु जैन की अवकाश पीठ ने कहा कि पोर्टल को दोबारा खोलने से परिणाम घोषित करने की पूरी प्रक्रिया में देरी हो जाएगी।

याचिका पर बेंच ने टिप्पणी की कि आपके लिए यह एक सप्ताह की बात है, लेकिन इससे पूरी प्रक्रिया एक महीने के लिए विलंबित हो जाती है। आप समझ नहीं रहे हैं। यह एक चरण की प्रक्रिया नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा, मैं कोई निर्देश नहीं दे रही हूं।

जो कोई भी पीड़ित है, वह व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। पुनर्मूल्यांकन के लिए सीबीएसई का पोर्टल 2 से 7 जून तक खुला था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में बताया कि 1.67 लाख से अधिक छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है और 3.8 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जा रही है।

उन्होंने कहा कि यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है और इससे साबित होता है कि पोर्टल ने काम किया है। मेहता ने आगे कहा कि याचिका बहुत सामान्य धारणाओं पर आधारित है और यदि एनएसयूआई की मांग मान ली गई तो 17 लाख से अधिक छात्रों के स्नातक प्रवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कोर्ट ने एनएसयूआई के आग्रह पर मामले की सुनवाई जुलाई में नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। याचिका में सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की भी मांग की गई है।

कोर्ट ने कहा- परिणाम और दाखिले की प्रकिया में हो जाएगी देरी

एनएसयूआई का कहना है कि इस वर्ष 12वीं के परिणामों में समग्र प्रदर्शन में भारी गिरावट छात्रों और अभिभावकों में चिंता का विषय बनी हुई है, खासकर जब स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं के लिए बड़ी संख्या में अनुरोध किए गए। याचिका में दावा किया गया है कि मौजूदा शिकायत तंत्र अपर्याप्त है क्योंकि इसमें छात्रों को सीमित डिजिटल उपचार और विवादित उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन के लिए कोई सार्थक प्रक्रिया उपलब्ध नहीं कराई गई है।

जज को हत्यारा कहने वाले ने दोबारा बनाए वीडियो

कपिल कक्कड़ को कोर्ट ने हटाने के दिए निर्देश

अदालत से

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को डॉ. कपिल कक्कड़ द्वारा अपलोड किए अतिरिक्त वीडियो हटाने का आदेश दिया। इसमें उन्होंने साकेत में 30 मई को हुए भवन ढहने की घटना में छह लोगों की मौत के लिए एक हाईकोर्ट जज को दोषी ठहराया था। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति मधु जैन की डिवीजन बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) की ओर से लाए गए इन वीडियो के संज्ञान में यह आदेश पारित किया।

कोर्ट को बताया गया कि 8 जून को हाईकोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई के बाद कक्कड़ के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने और जज के खिलाफ वीडियो हटाने का आदेश दिए जाने के बावजूद, उन्होंने समान आरोप लगाते हुए नए वीडियो अपलोड कर दिए। सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन ने डीएचसीबीए की ओर से पेश होते हुए कहा कि नए वीडियो में कक्कड़ ने अपने अकाउंट के ब्लॉक होने का जिक्र करते हुए लोगों से अपने पर्सनल अकाउंट को फॉलो करने की अपील की और उनसे पैसे दान करने को भी कहा।

सोशल मीडिया का क्या करें : हाईकोर्ट : वीडियो देखने के बाद कोर्ट ने टिप्पणी की कि सोशल मीडिया के साथ हम क्या करें? हर मामले में कोर्ट सख्ती दिखा रहा है, लेकिन क्या यह निवारक बन रहा है? यह तेजी से आम होता जा रहा है। जो व्यक्ति पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं, उनके साथ क्या किया जाए? कई मामलों में लोगों को जेल भेजा जा चुका है, यह न कहें कि हमने नरमी बरती है।

8 जून को कोर्ट ने कक्कड़ के उन वीडियो और पोस्ट को हटाने तथा उनके एक्स, मेटा और यूट्यूब अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया था, जिनमें उन्होंने जज को मर्डरर बताया और सैदुल्लाजाब इमारत ढहने की घटना के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। ब्यूरो

गुरु रंधावा से जुड़े जिम पर फायरिंग करने वाले दो बदमाशों का फुटेज हुआ वायरल

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। पश्चिम विहार स्थित पुष्कर एन्क्लेव के 24 ऑवर फिटनेस जिम पर गोलीबारी करने वाले बदमाशों का अब तक सुराग नहीं मिला है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हमलावर गोलीबारी के बाद बाइक से भागते दिख रहे हैं। फुटेज के आधार पर जिला पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आरोपियों की तलाश कर रही हैं।

फुटेज के आधार पर जांच करने में जुटी है पुलिस। सोशल मीडिया

घटना के बाद सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा जिम्मेदारी लेने के दावे की भी जांच की जा रही है। साइबर टीम पोस्ट की सत्यता खंगाल रही है। पुलिस आसपास के पुराने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और आशंका है कि हमलावरों ने पहले रेकी की थी। सूत्रों के अनुसार वारदात में इस्तेमाल बाइक चोरी की हो सकती है। मामले की जांच में आधा दर्जन से अधिक टीमें लगी हैं।

शिक्षक के कॉलेज आने पर प्रतिबंध मोबाइल फोन भी किया गया जब्त

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में एक शिक्षक पर छात्रा की बिना अनुमति मोबाइल फोन से तस्वीर खींचने के आरोप का मामला गरमा गया है। कॉलेज प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पूरी होने तक शिक्षक के कॉलेज में प्रवेश को प्रतिबंधित कर उसका मोबाइल जब्त कर लिया है।

पूरे मामले को कॉलेज आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को भेज दिया गया है। समिति शनिवार से जांच शुरू कर देगी। इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।

सत्यवती कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. सुभाष कुमार सिंह ने बताया कि मामला सामने आने के बाद से कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले से संबंधित सभी सबूतों को सेव कर आंतरिक शिकायत समिति को सौंप दिया गया है। शिक्षक के मोबाइल को जब्त कर रख लिया गया है।

सत्यवती कॉलेज में छात्रा की बिना अनुमति फोटो खींचने का मामला

जांच पूरी होने तक उनके कॉलेज परिसर में आने पर भी रोक रहेगी। हालांकि जांच प्रक्रिया के दौरान समिति के संयोजक के बुलाने पर उन्हें कॉलेज आने की अनुमति मिलेगी। शुक्रवार को शिक्षक परीक्षा ड्यूटी पर भी उपस्थित नहीं हुआ। कॉलेज प्रिंसिपल ने बताया कि छात्रा की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। इस मामले की जांच समिति करेगी और शनिवार को छात्रा को बुलाया गया है। बृहस्पतिवार को परीक्षा के दौरान सत्यवती कॉलेज की एक छात्रा ने आरोप लगाया कि परीक्षा ड्यूटी के दौरान एक शिक्षक ने उनकी अनुमति के बिना मोबाइल से तस्वीरें खींची।

इस घटना के सामने आने के बाद कॉलेज में छात्राओं ने प्रदर्शन भी किया था। पूरा घटनाक्रम कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। समिति जो भी रिपोर्ट देगी उसे कॉलेज की प्रबंध समिति में रखा जाएगा।

कोर्ट में तलाक लेने पहुंचे पति-पत्नी गले मिलकर रोए, वीडियो वायरल

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर पति-पत्नी का एक वीडियो वायरल हो रहा। दावा किया जा रहा कि दृश्य तीस हजारी स्थित फैमिली कोर्ट का है। दोनों ने एक-दूसरे को सामने से देखने के बाद अपने सारे मतभेद भुलाते हुए गले मिलकर रोने लगे और साथ रहने का फैसला किया।

सोशल मीडिया के अनुसार दोनों ने ही अपनी तलाक की अर्जी को भी फाड़ दिया। हालांकि मुकदमे की कानूनी स्थिति की पुष्टि नहीं हो पाई है।

जानकारी के अनुसार, शिखा सिंह और सौरभ ने 2020 में शादी की थी। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और मामला अदालत तक पहुंच गया। शिखा ने पति सौरभ पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए केस कराया था।

इसी दौरान शिखा के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। परिवार ने उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया।

जैसे ही यह जानकारी सौरभ को मिली, उन्होंने तुरंत अपने ससुर को बेहतर इलाज के लिए गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया और उनके पूरे इलाज में मदद की। इलाज के बाद शिखा के पिता की सेहत में सुधार हो गया था।

कोर्ट में गले मिलते हुए। सोशल मीडिया

बत्ती गुल होते ही अधिकारी बाहर, फरियादी परेशान

फिरदौस आलम

पूर्वी दिल्ली। शाहदरा उत्तरी जोन नगर निगम कार्यालय में फरियादी इन दिनों अपनी समस्या के साथ-साथ जोन कार्यालय की खराब व्यवस्था से भी जूझ रहे हैं। दावा है कि जोन कार्यालय में अक्सर बिजली गुल हो जाती है। इस कारण संबंधित विभाग के अधिकारी गर्मी से परेशान होकर कार्यालय से बाहर निकल जाते हैं और फरियादी अपने काम के इंतजार में उमस भरी गर्मी में इंतजार करते रह जाते हैं।

शुक्रवार को जब शाहदरा उत्तरी जोन के कार्यालय की संवाददाता ने पड़ताल की तो इस दौरान कई खामियां मिलीं। दफ्तर की बत्ती गुल थी। कई सारे अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय के बाहर बैठे हुए नजर आए। फरियादी रूमाल और गमछे से अपने सिर का पसीना पोछते रहे थे।

कार्यालय में बिजली गुल होने के बाद बाहर बैठे कुछ कर्मचारी। संवाद

हत्या और अपहरण के आरोपी दिल्ली मुठभेड़ में हुए गिरफ्तार

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। गाजियाबाद के चर्चित अपहरण और हत्याकांड में फरार दो इनामी बदमाश दिल्ली में एक और वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। वारदात से पहले ही क्राइम ब्रांच के शिकंजे में आ गए।

दक्षिण दिल्ली में हुई मुठभेड़ में दोनों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। एक गोली क्राइम ब्रांच के एसीपी की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गाजियाबाद के लोनी निवासी सौरभ उर्फ भोला उर्फ प्रिंस (25) और गोपाल (23) के रूप में हुई है। दोनों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस का दावा है कि दोनों हाल ही में हुए अपहरण और हत्या के मामले में फरार थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहे थे।

स्पेशल सीपी क्राइम एचजीएस धालीवाल ने बताया कि सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी दिल्ली में पुरानी दुश्मनी के कारण एक और हत्या की साजिश रच रहे हैं।

दक्षिण दिल्ली के अरविंदो कॉलेज के आसपास बृहस्पतिवार की रात करीब दो बजे दोनों आरोपी चोरी की मोटरसाइकिल पहुंचे। पुलिस टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक सौरभ के पास इटली निर्मित .32 बोर की अत्याधुनिक बेरेटा पिस्तौल थी, जिससे उसने चार राउंड फायर किए।

कचरा प्रबंधन के लिए डीआरओपी पहल की शुरू

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने वीआईपी क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए डीआरओपी (प्लास्टिक के प्रति जिम्मेदार नजरिया अपनाएं) परियोजना की शुरुआत की है। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने शुक्रवार को पुनर्चक्रित प्लास्टिक से निर्मित सामुदायिक कूड़ेदानों का लोकार्पण किया और प्लास्टिक कचरा संग्रहण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना के तहत क्षेत्र में विशेष संग्रहण डिब्बे स्थापित किए जाएंगे और प्लास्टिक कचरे के संग्रहण, पृथक्करण किया जाएगा। ब्यूरो

युवक की हत्या में युवक पर चलेगा मुकदमा

पूर्वी दिल्ली। भजनपुरा थाना क्षेत्र में प्रेम संबंध को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या में कड़कड़डूमा कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बाबरू भान की अदालत ने आरोपी विशेष शर्मा के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत होने की बात कही। वहीं उसकी मां काजल शर्मा को हत्या के आरोप से राहत देते हुए केवल साधारण चोट पहुंचाने के मामले में 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। वहीं मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई है।

अभियोजन पक्ष ने कहा मृतक अभिषेक का आरोपी काजल शर्मा की बेटी अनन्या के साथ प्रेम संबंध था। 15 सितंबर 2025 को दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। विवाद के बाद अभिषेक आरोपी के घर पहुंचा, जहां कहासुनी और हाथापाई के दौरान विशेष शर्मा ने रसोई से चाकू लाकर उस पर कई बार किए। गंभीर रूप से घायल अभिषेक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मृतक का किसी के घर में जबरन प्रवेश करना गलत था। इसके बावजूद आठ बार चाकू से हमला करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो

बुराड़ी में पार्षद के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माणों के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई जारी रखते हुए शुक्रवार को बुराड़ी उपखंड के जगतपुर क्षेत्र स्थित मिलन विहार कॉलोनी में बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षद कुलदीप चौधरी द्वारा कराए जा रहे कथित अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। करीब सात घंटे तक कार्रवाई हुई।

एमसीडी अधिकारियों के अनुसार, मिलन विहार कॉलोनी में दो भूखंडों पर बड़े पैमाने पर बिना स्वीकृति निर्माण किया जा रहा था। इनमें एक भूखंड का आकार लगभग 200×45 वर्ग फुट और दूसरे का 45×40 वर्ग फुट है। जांच के दौरान निर्माण को पूरी तरह अवैध पाए जाने के बाद भवन विभाग ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का निर्णय लिया।

कार्रवाई शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल, सीआरपीएफ और सीएटीएस की टीमें तैनात की गई थीं। निगम के इंजीनियरों और प्रवर्तन अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजरों की मदद से दोनों भूखंडों पर खड़े अवैध ढांचों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया।

सांकेतिक

एमसीडी ने सात घंटे तक की कार्रवाई, बगैर स्वीकृति के चल रहा था निर्माण कार्य

ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति भी बनी रही। स्थानीय स्तर पर विरोध के प्रयास हुए, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते कार्रवाई बिना किसी बड़े व्यवधान के जारी रही। निगम की टीम ने शाम करीब पांच बजे अभियान समाप्त किया। इस तरह लगभग सात घंटे तक चले ऑपरेशन में पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।

उत्तर रेलवे

ई–निविदा (ई–प्रोक्यूमेंट) के माध्यम से निविदा आमंत्रण

निम्नलिखित कार्य के लिए वरिष्ठ मंडल अभियंता–III, उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल मे ई–निविदा आमंत्रण।

कार्य का नाम	दिल्ली मेन स्टेशन पर 100 बेड की क्षमता वाली दो मंजिला नई RPF बैरक की व्यवस्था और ADEN/DLI NDLS और HNZM सेक्शन में दिल्ली मेन स्टेशन (04) ANVT (02) और HNZM (02) पर RPF के लिए डॉग केनेल सह ब्रीडिंग सेंटर की व्यवस्था।
कार्य की अनुमानित लागत (रुपये)	रु.4,57,31,750.40 /– (रुपये चार करोड़ सतावन लाख इकतीस हजार सात सौ पचास और चालीस पैसे मात्र)
बयाना राशि (रुपये)	रु.9,14,600.00 /– (रुपये नो लाख चौदह हजार छह सौ मात्र)
निविदा प्रपत्र का मूल्य (रुपये)	रु.0.00
निविदा बोली प्रस्तुत करने और निविदा खोलने की तिथि और समय	06.07.2026 को 15:00 तक।
वेबसाइट विवरण जहां निविदा दस्तावेजों का पूरा विवरण देखा जा सकता है	निविदा www.ireps.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध।
आवंटन	20646203

- ठेकेदारो को ई–टेंडर प्रणाली में भाग लेने के लिए भारतीय रेलवे ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम) IREPS) साइट यानी www.ireps.gov.in के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
- सभी नियमों और शर्तो के लिए कृपया निविदा दस्तावेज देखें।
- मैनुअल निविदाये स्वीकृत नहीं की जायेगी।
- निविदा दस्तावेज और बयाना की लागत केवल नेट बैंकिंग या भुगतान गेटवे के माध्यम से स्वीकार्य होगी।

निविदा संख्या : 128–डब्लू/280/ई–निविदा सूचना/28/2026–27/डब्लू–3
दिनांक : 12.06.2026 2017/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER ROAD CONSTRUCTION DEPARTMENT, ROAD DIVISION, GUMLA-835207,
E-mail :- eercdgumla-jhr@nic.in

Short Term e-Procurement Notice
3rd Call

e-Tender Reference no.- **RCD/GUMLA /381 Dated :- 12.06.2026**

1	कार्य का नाम	पथ प्रमण्डल गुमला अन्तर्गत खूंटी– तोरपा– कोलेबिरा पथ के 61वें कि0मी0 में अवस्थित कोयल नदी पर उच्चस्तरीय सेतु (Span-7 x 35 m) निर्माण कार्य।
2	प्राक्कलित राशि	**Rs.- 175447957.00** (रू0 सत्रह करोड़ चौवन लाख सैतालीस हजार नौ सौ सतावन मात्र)
3	बीड सिक्युरिटी (राशि)	Rs.- 1755000.00
4	कार्य पूर्ण करने की अवधि	36 माह
5	वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि	16.06.2026 from 10.30 A.M.
6	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	01.07.2026 upto 12.00 Noon
7	निविदा खुलने का तिथि एवं समय	03.07.2026 at 12.30 P.M.
8	निविदा खुलने का स्थान	Chairman, e-Procurement Cell, RCD, Jharkhand, 3rd Floor, Project Building, Dhurwa, Ranchi-834004.
9	निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम, पता एवं दूरभाष संख्या	कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, गुमला। मोबाईल न0– 8709076211
10	ई–मेल	eercdgumla-jhr@nic.in
11	ई–प्रोक्यूरमेंट सेल का सहायता दूरभाष संख्या	0651-2401010

Further details can be seen on website http://jharkhandtenders.gov.in

ह0/–
कार्यपालक अभियन्ता,
प0नि0वि0 पथ प्रमण्डल, गुमला

PR 382299 Road(26-27)#D

उत्तर रेलवे

ई–निविदा सूचना

वरिष्ठ मंडल वि. अभि./क. वि., डी. आर. एम. ऑफिस, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्न कार्य हेतु खुली निविदाये आमंत्रित करते हैं।

1.	कार्य का नाम व स्थान	दिल्ली मंडल में कैटेनरी तार का संवर्धन/प्रतिस्थापन (सातवां चरण)।
2.	अनुमानित लागत	Rs. 1,80,29,018.38/-
3.	बयाना राशि	Rs. 3,60,600/-
4.	ई–निविदा ऑनलाइ जमा करने की अवधि	24.06.2026 (10:30 बजे) से 08.07.2026 (15:00 बजे तक)
5.	ई–निविदा समापन की अंतिम तथा ई– निविदा खुलने की तारीख और समय	08.07.2026(15:00 बजे)
6.	वेबसाइट विवरण जहां निविदा दस्तावेजों का पूरा विवरण देखा जा सकता है।	www.ireps.gov.in

निविदा संख्या: 09A–क.वि.- नई दिल्ली – 2026–27 दिनांक: 12.06.2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 2024/26

उत्तर रेलवे

खुली निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल इंजीनियर – IV, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली द्वारा निम्न कार्य के लिए ई–टेंडर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

कार्य का नाम	DEN-IV/DLI के अधिकार क्षेत्र में दिल्ली–बठिंडा सेक्शन में यार्ड सुधार कार्य। लूप लाइनों में 45.05 टीकेएम सीटीआर (जिसमें ठेकेदार की SQRS द्वारा 28.90 टीकेएम तथा मैनुअल पद्धति से 16.15 टीकेएम), 54 सेट टीटीआर, 34 सेट ट्रैप तथा 83 सेट एसईजे का नवीनीकरण। (निविदा आमंत्रण सूचना –18–26–27–डब्ल्यू–IV)
अनुमानित लागत	रु. 9,67,97,826.23 /–
धरोहर राशि	रु. 19,36,000.00 /–
ई–निविदा भरने का दिनांक और समय & ई–निविदा खुलने का दिनांक और समय	ई–निविदा भरने का समय शुरू दिनांक 23.06.2026 को 15.00 बजे से निविदा खुलने का समय & ई–निविदा खुलने का दिनांक 07.07.2026 को 15:00 बजे तक।
निविदा की वेबसाइट जहां निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकता है	www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।

पत्र सख्या 128-W/260/निविदा सूचना/18–26–27/डब्ल्यू-IV दिनांक: 12.06.2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 2022/2026

उत्तर रेलवे

निविदा आमंत्रण सूचना

कार्य का नाम और इसकी स्थिति	91-SRDEE-G-DLI-2026-27 "दिल्ली डिवीजन में पंपों को हटाने, चालू करने और उनसे जुड़े अन्य कार्यों" से संबंधित इलेक्ट्रिकल काम।
निविदा की अनुमानित लागत	रू. 9887080.00/-
कार्यालय का पता	वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/सामान्य, डीआरएम कार्यालय, दिल्ली मंडल, उत्तरी रेलवे, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली–110055
बयाना राशि	रू. 197800.00/
निविदा निवेदन की दिनांक व समय	06.07.2026, 16.00 बजे
निविदा खोलने की दिनांक व समय	06.07.2026, 16.00 बजे
वेब साइट व नोटिस बोर्ड	www.ireps.gov.in वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/जी, नई दिल्ली

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 2030/2026

उत्तर रेलवे

टेंडर नोटिस सं. 19/2026-2027 दिनांक: 12.06.2026

इलेक्ट्रोनिक निविदा ई प्रणाली के अन्तर्गत मदों की आपूर्ति हेतू निविदा आमंत्रण

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली–110001 द्वारा इच्छुक फर्मो से निम्नलिखित मदों के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है:–

क्र. सं.	निविदा सं.	संक्षिप्त विवरण	मात्रा	अंतिम तिथि
01	02261692A	एल इ डी लाइट फिटिंग	9840 नग	06.07.26
02	07261857	नॉन एस्बेस्टस बेस्ड आर्गेनिक ब्रेक पैड्स फॉर एल एच बी टाइप	52973 सेट	06.07.26
03	77265201	वैज फॉर स्लाइड चेयर्स	53600 नग	09.07.26
04	19262116	पी ओ एच मेंटेनेंस किट	9 नग	09.07.26
05	08265304	5 वाट वी एच एफ	739 नग	09.07.26
06	77269041 RGC	फिश प्लेट फॉर 52 के जी रेल	4880 नग	14.07.26
07	77269008 RGC	फिश प्लेट फॉर 60 के जी रेल	31676 नग	15.07.26

निविदा शर्तें:- 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट यानि www.ireps.gov.in पर देखी जा सकती हैं। 2. मैनुअल निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी। 2020/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ